चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

10 मार्च–16 मार्च 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

तीसरा मोर्चा

यह अवसरवादी राजनीति है

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद, जब कभी भी देश में तीसरे मोर्चे की बात हुई, वह राजनीतिक विकल्प देने से अधिक मौक़े का फ़ायदा उठाने के लिए ही हुई. वाम दलों की अगुवाई में एक बार फिर वही क़वायद जारी है, लेकिन स्पष्ट नीति, एजेंडा और दृष्टिकोण का अभाव इस मोर्चे को शायद ही वह मजबूती दे पाए, जिसकी ज़रूरत इसके अस्तित्व को बनाने और बचाने के लिए है.

अभिषेक रंजन सिंह

वह 27 अक्टूबर, 2012 का दिन था. राजधानी दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में वामपंथी और समाजवादी पृष्ठभूमि से जुड़ी कई पार्टियों के शीर्ष नेता एक साथ मंच पर उपस्थित थे. मौक़ा था समाजवादी लेखक–पत्रकार मस्तराम कपूर की पुस्तक– लोकसभा में लोहिया के लोकार्पण का. यह कार्यक्रम उस वक्त हो रहा था, जब देश में तीसरे मोर्चे की कोई विशेष सुगबुगाहट नहीं थी. ऐसे समय में मस्तराम कपूर के बहाने ग़ैर कांग्रेस–ग़ैर भाजपा विकल्प पर विमर्श किया जा रहा था. उस समय समाजवादी और वामपंथी दलों के कई नेताओं ने मुद्दा आधारित वैकल्पिक राजनीति का एक प्रस्ताव भी पारित किया. इन नेताओं ने समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को इसकी कमान संभालने की सलाह दी. इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव के अलावा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता ए बी बर्द्धन, डी राजा, अतुल कुमार अंजान, तेलगुदेशम संसदीय दल के नेता नागेश्वर राव, फारवर्ड ब्लॉक के नेता देवव्रत विश्वास और समाजवादी बुद्धिजीवी एवं वर्तमान में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉ. आनंद कुमार और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए इंडियन जस्टिस पार्टी के नेता उदित राज ने भी देश की जनता को ग़ैर कांग्रेस–ग़ैर भाजपा विकल्प देने की बात कही. हालांकि, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं था. ग़ौरतलब है कि इस कार्यक्रम के छह महीने बाद यानी अप्रैल, 2013 में मस्तराम कपूर का निधन हो गया.

बहरहाल, देश को ग़ैर भाजपा–ग़ैर कांग्रेस विकल्प देने के संबंध में जिन लोगों ने कांस्टीट्यूशन क्लब में लोकसभा चुनाव से छब्बीस महीने पहले वामपंथी और समाजवादी नेताओं के भाषण सुने होंगे, उन्हें मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में कई बदलाव देखने को मिल रहे होंगे. मिसाल के तौर पर उस कार्यक्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता ए बी बर्द्धन एवं डी राजा जैसे नेताओं ने संभावित तीसरे मोर्चे का कुनबा बढ़ाने और उसकी अगुवाई करने की अपील मुलायम सिंह यादव से की थी. मुलायम सिंह ने भी उन दिनों कहा था कि देश में अच्छे हालात नहीं हैं. कांग्रेस ने ग़ैर–बराबरी के ख़ात्मे के लिए जनता से जो वादे किए थे, वे आज तक पूरे नहीं हो सके हैं. उनके मुताबिक़, वह देश में ग़ैर–कांग्रेस और ग़ैर–भाजपा सरकार चाहते हैं, इसलिए वामपंथी दलों को साथ आना चाहिए, क्योंकि समाजवाद और साम्यवाद में बेहद मामूली फ़र्क़ है, जिसे इन दोनों पार्टियों को नज़रअंदाज़ करना होगा. उस समय इस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक समन्वय समिति के गठन का प्रस्ताव भी दिल्ली में रखा गया, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया था. अपने संबोधन के बाद कार्यक्रम के बीच से निजी व्यस्तता का हवाला देते हुए वह चले गए. कार्यक्रम के आख़िरी पड़ाव में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव आते हैं. उस समय शरद यादव एनडीए के संयोजक थे. शरद यादव का पूरा भाषण डॉ. लोहिया के इर्द–गिर्द घूमता रहा. तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि इसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं.

याद रहे कि पिछले साल नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था. नतीज़तन वही शरद यादव अब तीसरे मोर्चे को लेकर होने वाली बैठकों में न केवल शामिल हो रहे हैं, बल्कि उन्हें इसकी प्रबल संभावना भी दिखती है. अब बात करते हैं समाजवादी पृष्ठभूमि से जुड़े रहे डॉ. आनंद कुमार की, जो फ़िलहाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं. मस्तराम कपूर की पुस्तक–'लोकसभा में लोहिया' के लोकार्पण समारोह में उन्होंने क़रीब पैंतालीस मिनट तक भाषण दिया था. उस समय आनंद कुमार की पहचान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में विशुद्ध प्राध्यापक की रही थी. डॉ. आनंद कुमार ने अपने भाषण में कहा था कि राजनीति और आंदोलन दो अलग–अलग चीजें हैं. जिस तरह आंदोलन से जुड़े लोग राजनीति में सफल नहीं हो सकते, उसी तरह राजनीति से संबंध रखने वाले आंदोलन के लिए मुफ़ीद नहीं हैं. आम आदमी पार्टी से जुड़ने और उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच, उनसे यह ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि क्या आंदोलन और राजनीति को लेकर उनकी राय वही है या उसमें तब्दीली आई है?

भारतीय राजनीति में तीसरे मोर्चे की संभावना जनता पार्टी के प्रयोग की असफलता के बाद लगातार बनी रही. वर्ष 1989 में वामपंथी दलों और भाजपा के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा बना, उसके बाद वर्ष 1996 में संयुक्त मोर्चा. हालांकि, केंद्र की राजनीति में ये दोनों प्रयोग बहुत ज़्यादा सफल साबित नहीं हुए. तीसरे मोर्चे की राजनीति उभरने से पहले ही काल–कलवित हो गई. यही वजह है कि देश की राजनीति में तीसरा मोर्चा कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा बनकर रह गया. जब भी इसकी ज़रूरत महसूस होती है, उस समय तीसरे मोर्चे के अवशेषों की तलाश की जाती है. लिहाज़ा लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में तीसरे मोर्चे की बातें फिर से होने लगी हैं. जहां परंपरागत राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव आदि कांग्रेस की साज़िशों में फंसकर अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं इस पूरे परिदृश्य में वामपंथी पार्टियां आज भी एक आख़िरी उम्मीद के साथ धर्मनिरपेक्षता की दरक चुकी नाव को थामने की कोशिश कर रही हैं, ताकि लोकसभा चुनावों में सांप्रदायिक–फ़िरकापरस्त ताक़तों का हौव्वा खड़ा करके किसी तरह चार–पांच सवारों को इस पर बैठने और पार जाने के लिए मनाया जा सके. इसमें कोई शक नहीं कि वामपंथी पार्टियों की नाव को इस बार डूबना ही होगा, क्योंकि इस पर मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और जयललिता जैसे प्रधानमंत्री पद का सपना संजोए महत्वाकांक्षी मुसाफ़िर सवार हैं, जो कभी भी अपनी राजनीतिक निष्ठाएं बदल सकते हैं.

इसे महज इत्तेफ़ाक नहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी नेता किशन पटनायक की प्रेरणा से राजनीति करने वाले और अब आम आदमी पार्टी के चाणक्य बन चुके विनम्र बुद्धिजीवी योगेंद्र यादव ने खुलेआम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे डाला. उन्होंने माकपा के नेताओं से कहा कि वे चाहें, तो डेपुटेशन पर आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं. अगर वे चुनाव में हार गए, तो वापस अपनी पार्टी में लौट सकते हैं. जाहिर है, यह आम आदमी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

लोक के लिए या लोभ के लिए **03**

किया न धरा, गिलास तोड़ बारह आना **04**

उपेक्षा का सिलसिला जारी है **07**

साई की महिमा **12**

यह अवसरवादी राजनीति है

फोटो–प्रभात पाण्डेय

पृष्ठ एक का शेष

पार्टी की नई राजनीतिक व्याख्या हो सकती है. बहरहाल, फरवरी के आख़िरी सप्ताह में संभावित तीसरे मोर्चे की राजनीति करने वाले दलों की ओर से एक बैठक हुई. बैठक में शामिल प्रकाश करात जैसे नेताओं ने भरोसा दिलाया कि संयुक्त मोर्चे के रूप में वे ग़ैर कांग्रेस और ग़ैर भाजपा विकल्प देने को तैयार हैं. बग़ैर किसी नाम के इस मोर्चे में शामिल नेताओं की ओर से यह कहा गया कि उनकी संख्या ग्यारह से बढ़ेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी तादाद बढ़ने की बजाय घटती जा रही है. इससे पहले भी कथित तीसरे मोर्चे की बैठक में चौदह पार्टियां शामिल हुई थीं. हालांकि इस बार बीजू जनता दल और असम गण परिषद के शीर्ष नेता नवीन पटनायक एवं प्रफुल्ल कुमार महंत इस बैठक में कहीं नज़र नहीं आए. 5 फरवरी को ग्यारह राजनीतिक दल ग़ैर कांग्रेस–ग़ैर भाजपा मोर्चा खड़ा करने के लिए लामबंद हुए थे. इस बैठक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसपी, फारवर्ड ब्लॉक, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, अन्नाद्रमुक, जनता दल सेक्युलर, झारखंड विकास मोर्चा, असम गण परिषद और बीजू जनता दल शामिल थे. मोर्चा गठित होने के पांच दिनों बाद यानी दस फरवरी को इस बाबत पुन: एक बैठक होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल और असम गण परिषद का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं हुआ.

हो सकता है कि उनकी ग़ैर मौजूदगी की कोई वजह रही हो, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता ने स्वयं न आकर अपने एक प्रतिनिधि को दिल्ली भेजा. हैरानी की बात तो यह है कि जिस समय यह तीसरा मोर्चा दिल्ली में अपनी ताक़त दिखा रहा था, उसी समय तमिलनाडु में जयललिता अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी कर रही थीं. उनके इस रुख़ से कतई नहीं लगता कि वह किसी तीसरे या चौथे मोर्चे को लेकर संजीदा हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस मोर्चे का न तो अभी कोई नाम तय हुआ है और न ही कोई नेता, वह भला आगामी लोकसभा चुनाव के बाद किस बुनियाद पर ग़ैर कांग्रेस और ग़ैर भाजपा सरकार बनाने की बात कर रहा है. प्रधानमंत्री के दावेदार संबंधी पूछे जाने वाले सवाल पर वे मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल का नाम गिनाने लगते हैं कि ये नेता चुनाव बाद ही प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किए गए थे. ग़ैर कांग्रेस और ग़ैर भाजपा सरकार बनाने का दंभ भरने वाले कथित तीसरे मोर्चे में शामिल नेताओं को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि एच डी देवेगौड़ा और आई के गुजराल की सरकारें कांग्रेस की मेहरबानी से ही चल पाईं. फ़िलहाल तीसरे मोर्चे के नेता कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी रखने की बात कह रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव जैसे नेता एक तरफ़ कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को कोसते हैं, वहीं दूसरी तरफ़ उसे समर्थन भी देते हैं. जहां तक जनता दल यूनाइटेड की बात है, तो एनडीए की सहयोगी रही यह पार्टी नरेंद्र मोदी के सवाल पर भाजपा से अलग हो गई. लोकसभा चुनाव नज़दीक आते देख जदयू ने बिहार में कांग्रेस के साथ तालमेल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का साथ न मिलने पर वह संभावित तीसरे मोर्चे में अपना भविष्य तलाश रही है.

फ़िलहाल इस मोर्चे को अमलीजामा पहनाने का काम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश करात कर रहे हैं. संयोग से यह उसी माकपा के वरिष्ठ नेता हैं, जिसने अपने साढ़े तीन दशकों के शासन में पश्चिम बंगाल के उद्योग–धंधों को रसातल में पहुंचा दिया और वहां की जनता को रोज़ी–रोज़गार के लिए पलायन करने को मजबूर कर दिया. वर्ष 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने चौंतीस वर्षों से सत्ता पर क़ाबिज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के किले को ध्वस्त कर दिया. इस चुनाव में माकपा की शर्मनाक हार का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटों पर जीत हासिल की थी. पश्चिम बंगाल में वामदलों की हार का सिलसिला यहीं नहीं थमा, बल्कि कुछ समय बाद हुए पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस का परचम लहराया. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत इस लिहाज़ से भी महत्वपूर्ण है कि उसने बंगाल की अवाम को वामदलों के उस मोह से बाहर निकाला, जिसका फ़ायदा अब तक वामपंथी दल किसी न किसी रूप में उठाते रहे थे.

वर्ष 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने चौंतीस वर्षों से सत्ता पर क़ाबिज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के किले को ध्वस्त कर दिया. इस चुनाव में माकपा की शर्मनाक हार का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटों पर जीत हासिल की थी.

प्रधानमंत्री बनने की तीव्र महत्वाकांक्षा पाले मुलायम सिंह यादव की राह में न सिर्फ़ मायावती ही रोड़े अटकाएंगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के बदले हुए राजनीतिक और सामाजिक माहौल में मुलायम की मंशा फलीभूत होती दिखाई नहीं दे रही है. तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक डीएमके से टूटकर वजूद में आई थी. जयललिता और करुणानिधि तबसे राज्य में एक–दूसरे के प्रबल विरोधी हैं. तीसरे मोर्चे का राग अलापने वाले वामपंथी दल यूपीए प्रथम सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे. अमेरिका के साथ परमाणु क़रार के मुद्दे पर ही वामदलों ने मनमोहन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया. उस वक्त मनमोहन सरकार को समाजवादी पार्टी ने संजीवनी देने का काम किया था.

उल्लेखनीय है कि पंद्रहवीं लोकसभा में मौजूदा तीसरे मोर्चे में शामिल 11 दलों के पास सौ से कम सीटें हैं. अगली लोकसभा में अगर इनकी संख्या 100 हो जाती है, जैसा कि उम्मीद नहीं है, फिर भी इस दम पर केंद्र में सरकार बनाने का उनका दावा हास्यास्पद प्रतीत होता है. दरअसल, तीसरे मोर्चे में एक नहीं, बल्कि कई अंतर्विरोध हैं. मसलन, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक साथ तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनना संभव नहीं है. उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड कभी भी एक साथ नहीं हो सकते.

जहां तक माकपा के महासचिव प्रकाश करात का सवाल है, तो उन्होंने अप्रैल, 2013 में अगरतला की एक सभा में कहा था कि केंद्र में तीसरा मोर्चा बनाना आसान नहीं है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इसे लेकर अपना रुख बदलती रही हैं. अगर देखा जाए, तो तीसरे मोर्चे को लेकर प्रकाश करात के बयानों में भी काफी विरोधाभास नज़र आता है. इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल की खुलकर तारीफ़ की थी. उन्होंने माकपा नेताओं को आम आदमी पार्टी से सीख लेने तक की नसीहत दे डाली. लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तीसरे मोर्चे की हो रही क़वायद के बीच जहां संसदीय राजनीति करने वाले वामदल समाजवादियों के साथ मिलकर देश को नए राजनीतिक विकल्प का सपना दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वाम बुद्धिजीवियों का एक बड़ा तबका तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को सिरे से ख़ारिज करता है.

दरअसल, देश की राजनीति में तीसरा मोर्चा उस कमज़ोर पेड़ की तरह है, जिसकी न जड़ मजबूत है और न ही तना और अंत में जिसमें कोई फल नहीं लगता. अगर फल आ भी जाए, तो वह असमय गिरकर नष्ट हो जाता है. मौजूदा समय में जिस अनाम तीसरे मोर्चे की शक्ल दिख रही है, वह देश को ग़ैर कांग्रेस और ग़ैर भाजपा विकल्प देने से कहीं ज़्यादा अपना सियासी वजूद बचाने का फ़िक्रमंद है. पश्चिम बंगाल में वामदलों, बिहार में जनता दल यूनाइटेड, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और असम में असम गण परिषद के शीर्ष नेताओं को फ़िलहाल अपने राज्यों में यही चिंता सता रही है.

बहरहाल, आगामी लोकसभा चुनाव के परिणाम न सिर्फ़ चौंकाने वाले होंगे, बल्कि कई और लिहाज़ से भी 2014 को याद रखा जाएगा. अगले कुछ महीनों में होने वाले इन चुनावों से पहले कई सियासी समीकरण बनेंगे और कई ध्वस्त होंगे, इससे इंकार नहीं किया जा सकता. लिहाज़ा मौजूदा समय में तीसरे मोर्चे की जो क़वायद वामपंथी और समाजवादी दलों के नेता कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की संभावना और उसकी ताकत लगातार कमज़ोर हुई है. ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि आगामी लोकसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बुरी तरह नाक़ाम साबित हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ, तो राजनीति के गलियारे में यह नाम हमेशा के लिए गुमनाम हो जाएगा. ■

arsingh@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 01
दिल्ली, 10 मार्च–16 मार्च 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

एक बार फिर सीवीसी बनाम सीबीआई

दिलीप चेरियन

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) एक बार फिर देश की प्रमुख जांच एजेंसी में वरिष्ठ नियुक्तियों के मसले पर आमने–सामने हैं. सूत्रों का कहना है कि दोनों संगठनों के बीच ताजा विवाद सीबीआई में एक विशेष निदेशक की नियुक्ति को लेकर है. यह मुश्किल कुछ दिनों पहले सीबीआई में एक अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति पर हुए संघर्ष के बाद सामने आई है, जिसमें सीबीआई ने बाजी मारी थी. सूत्रों का कहना है कि ये एजेंसियां सीबीआई में नंबर दो पद यानी एक विशेष निदेशक की नियुक्ति के लिए गठित पैनल पर आपस में भिड़ गई हैं. सीवीसी, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस पद के लिए पांच नाम प्रस्तावित किए हैं और शीघ्र निर्णय के लिए जोर दिया जा रहा है. दिलचस्प रूप से, सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित नामों में से चार के पास सीबीआई या सतर्कता विभाग में काम करने का पर्याप्त अनुभव नहीं है. केवल एक उम्मीदवार, ओडिशा के पुलिस महानिदेशक प्रकाश मिश्रा हैं, जिनकी दावेदारी सबसे मजबूत है. सीबीआई ने इस तरह के पैनल के गठन का विरोध किया है और कहा है कि इस नियुक्ति के लिए इतनी जल्दी क्या है, जब अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में विशेष निदेशक के कई अन्य पद रिक्त पड़े हुए हैं. ■

केरल में बाबुओं की कमी

केरल को बाबुओं की कमी झेलनी पड़ रही है. राज्य में 165 आईएएस, 125 आईपीएस और 88 वन सेवा के अधिकारियों की कमी है. नतीजतन, 36 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ रहा है. जाहिर तौर पर राज्य सरकार ने इस वर्ष केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए केरल कैडर के अधिकारियों की सिफारिश न करने का फ़ैसला किया है. इसके अलावा, केंद्र में पांच साल की प्रतिनियुक्ति पूरी करने वाले अधिकारियों को तुरंत राज्य में वापस आना होगा और किसी को भी एक्सटेंशन की अनुमति नहीं होगी. सूत्रों के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को इस आशय की जानकारी मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने दे दी है और इसे स्वीकार कर लिया गया है. कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव भानु प्रताप शर्मा ने राज्य के मुख्य सचिव ई के भारत भूषण को सूचित किया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रतिनियुक्ति की अवधि के बाद अधिकारियों को तुरंत अपने मूल कैडर में वापसी को मंजूरी दे दी है. ■

टॉप कॉप की सलाह

सेवा नियमों की वजह से और अपने करियर के दौरान सरकार एवं व्यवस्था के प्रति वफादारी के कारण सिविल सेवक अक्सर सेवानिवृत्ति के बाद ही अपनी ईमानदारी दिखा पाते हैं. खासकर तब, जब वे सेवानिवृत्ति के बाद अपनी आत्मकथा या संस्मरण लिखते हैं. लेकिन, आंध्र प्रदेश में पुलिस अतिरिक्त निदेशक सेवा के विनय कुमार सिंह एक ऐसे दुर्लभ अधिकारी हैं, जिन्होंने नौकरी में रहते हुए यह काम कर डाला है. सिंह की किताब–इज इट पुलिस: कंफेसन ऑफ ए टॉप कॉप पुलिस सुधारों और आपराधिक न्याय प्रणाली को न्यायपूर्ण बनाने की बात कहती है. 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी विनय कुमार सिंह की यह पुस्तक नौकरशाही के भीतर चर्चा का विषय बन गई है, लेकिन यह सब आसान नहीं था. सूत्रों का कहना है कि सिंह ने चार साल पहले यह पुस्तक लिख ली थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे तीन साल तक प्रकाशित नहीं होने दिया. कथित तौर पर, पुलिस अधिकारियों एवं वरिष्ठ बाबुओं के एक वर्ग ने इस किताब के कुछ अंशों और शीर्षक पर आपत्ति जाहिर की थी और सिंह को इसे प्रकाशित कराने से पहले संशोधित करना पड़ा. सिंह अब उन लोगों की जमात में शामिल हो गए हैं, जो सरकार से जल्द से जल्द पुलिस सुधारों को लागू करने और पुलिस मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करने की बात कहते हैं. लेकिन, क्या नेतागण ध्यान देंगे? ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

पंकज संस्कृति मंत्रालय जाएंगे

1990 बैच एवं मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी ंकज राग संस्कृति मंत्रालय के नए संयुक्त सचिव होंगे. वर्तमान में वह मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत पुरातत्व विभाग के निदेशक (संयुक्त सचिव के समकक्ष) के रूप में कार्यरत हैं. पंकज 1990 बैच एवं केरल कैडर के आईएएस वी वेणु का स्थान लेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया है.

किरन संयुक्त सचिव बनीं

1998 बैच की सीएसएस अधिकारी किरन पुरी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. वह पहले खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थीं.

मीरा और रवींद्र केंद्र में शामिल

2005 बैच की आईएएस अधिकारी मीरा मोहंती अवर सचिव के रूप में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली पारी की शुरुआत करेंगी. वर्तमान में वह हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ लोक निर्माण विभाग में सचिव (उपसचिव के समकक्ष) के रूप में कार्यरत हैं. इसी प्रकार 1999 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रवींद्र केंद्र सरकार में शामिल हो सकते हैं. फिलहाल वह उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में अपर आयुक्त की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं. रवींद्र औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग में निदेशक का पद संभालेंगे. वह आर के मलिक का स्थान लेंगे, जिन्हें विद्युत नियामक बोर्ड में स्थानांतरित किया गया है.

शैलेश गृह मंत्रालय से जुड़े

असम सरकार के अंतर्गत गृह, राजनीतिक एवं पासपोर्ट विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत आईएएस अधिकारी शैलेश जल्द ही भारत सरकार के साथ जुड़ सकते हैं. शैलेश को 1986 बैच एवं जम्मू–कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी लोकेश दत्त झा के स्थान पर संयुक्त सचिव नियुक्त किया जा सकता है. लोकेश आगामी 31 मार्च को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

15वीं लोकसभा में बनी नीतियां

लोक के लिए या लोभ के लिए

चौदहवीं लोकसभा के बाद जब देश में पंद्रहवीं लोकसभा का गठन हो रहा था और नई सरकार बनी, तब ऐसा लगा कि बस रंगमंच का पर्दा बदल रहा है, क्योंकि पात्र तो वही पुराने हैं. इसलिए नीतिगत स्तर पर यह तो तय था कि यह लोकसभा उन्हीं नीतिगत रास्तों पर चलेगी, जैसा कि यूपीए-1 के दौर में रहा, लेकिन तब यह अंदाजा किसी को नहीं था कि नीति नियंताओं की इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी यह सरकार इस लोकसभा को इस कदर कमजोर कर देगी कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह लोकसभा एक पंगु लोकसभा के तौर पर दर्ज हो जाएगी.

नीरज सिंह

नीतियों के आधार पर अगर इस लोकसभा को बांटा जाए, तो इसके दो कार्यकाल करने होंगे. पहले कार्यकाल में सरकार इस खुमारी में थी कि चूंकि ज़्यादातर घोटाले यूपीए-1 के कार्यकाल में हुए, फिर भी जनता ने उसे चुना. इसलिए पहले कार्यकाल में इस लोकसभा में हर उन नीतियों की, नियम-क़ानूनों की अनदेखी की गई, जिन्हें जनहित के तौर पर देखा जा रहा था. यही वजह है कि इस लोकसभा के उत्तरार्द्ध काल में जिस जनलोकपाल क़ानून तो पास कराकर मौजूदा सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, पूर्वार्द्ध में उसी जनलोकपाल के मसौदे को इसी लोकसभा में फाड़कर फेंक दिया गया था. जबकि उस दौर में देश अपनी इस मांग को लेकर आंदोलित था. गौर करिए, तो 15वीं लोकसभा में वही नीतियां क़ानून का रूप ले सकीं, जिनमें सरकार को चुनावी लाभ छिपे दिखे.

यह बात भी सही है कि इसी लोकसभा ने महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा पर सबसे सख्त क़ानून बनाया. खाद्य सुरक्षा क़ानून, भूमि अधिग्रहण क़ानून जैसे फ़ैसले भी किए, जिन्हें जन-लाभकारी कहा जा सकता है. सरकार ने महिलाओं, एससी-एसटी और माइनॉरिटी के हक़ में भी अहम फ़ैसले लिए. महिलाओं के लिए सबला, मातृत्व सहयोग योजना, प्रियदर्शिनी और नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन जैसी योजनाएं इसी कार्यकाल की देन हैं. लेकिन, यह श्रेय लोकसभा से ज़्यादा भारतीय न्यायिक व्यवस्था को जाता है, जिसने केवल चुनावी लाभ पर केंद्रित हो चली कार्यपालिका को कई बार झकझोरा और नींद से जगाया. और, तब इसी लोकसभा के सदस्यों ने न्यायपालिका को अपनी हदों में रहने की नसीहत दी और खुद को न्याय व्यवस्था के ऊपर साबित करते हुए अपराधी सांसदों की सदस्यता ख़त्म करने संबंधी क़ानून को निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश और क़ानून बनाने का रास्ता अपनाया. हां, इसके उत्तरार्द्ध काल में जब राहुल गांधी का एकाएक प्रायोजित पदार्पण हुआ, तो इस अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने वाला बताते हुए उन्होंने इस लोकसभा की गरिमा नहीं बचाई, बल्कि अपनी खोई गरिमा को वापस पाने की कोशिश की.

यूपीए सरकार जब पहला कार्यकाल बीतने के बाद दूसरे कार्यकाल की तैयारी कर रही थी, तब यह माना जा रहा था कि उसे दूसरा कार्यकाल दिलाने में मनरेगा की प्रमुख भूमिका रही. इसी गफ़लत में यूपीए-2 ने चुनावी लाभ को ध्यान में रखते हुए बिना किसी तैयारी के लोकसभा से नकदी स्थानांतरण योजना संबंधी बिल पास करा लिया और लागू कर दिया. सरकार का मानना था कि इससे ज़रूरतमंदों को सीधा लाभ मिलेगा और सब्सिडी का दुरुपयोग रुकेगा, लेकिन इस योजना को लेकर सरकार की नीयत शुरू ही अच्छी नहीं रही. सरकार केवल सात तरह की योजनाओं में लाभ दे पा रही है, जबकि इसके अंतर्गत 29 योजनाएं हैं. योजना एक जनवरी, 2013 से 15 राज्यों के 51 चुनिंदा ज़िलों में शुरू की जानी थी, लेकिन 20 ज़िलों में ही शुरू हो पाई. सरकार की कोशिश है कि इस योजना के चुनावी फ़ायदे को बनाए रखने के लिए 2014 में आम चुनाव आने से पहले देश के लगभग सभी 600 ज़िलों में इसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो यह दूर की कौड़ी है. इस योजना को लागू करने को लेकर सरकार की एक मंशा यह भी दिख रही है कि कहीं केंद्र सरकार ग़रीबों को उन्हें दी जाने वाली सब्सिडी के लाभ से वंचित तो नहीं करना चाहती?

सरकार का दावा है कि आधार कार्ड बुनियादी जन-सुविधाओं एवं उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी का आधार भी बनेगा. चुनावी माहौल बनाने के क्रम में इस योजना को आपका पैसा, आपके हाथ का नारा भी दिया गया. लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अभी तक देश में 21 करोड़ आधार कार्ड बन पाए हैं, जबकि लाभार्थियों की संख्या 42 करोड़ से ज़्यादा है. आधे बचे लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? 2009 के चुनावों में यूपीए सरकार पूरे देश में यह राग अलाप रही थी कि मनरेगा के माध्यम से उसने देश के हर हाथ को रोज़गार दिया है, लेकिन जैसे-जैसे रोज़गार देने के आंकड़े बाहर आए, तो खुलासा हुआ कि सरकार ने इस योजना को वास्तव में ग़रीबों के लिए नहीं, बल्कि अपनी झोली भरने के लिए लागू किया. आज मनरेगा को देश की सबसे भ्रष्ट योजनाओं में शुमार किया जा रहा है. सीएजी द्वारा संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक़, क़रीब सभी राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में भारी अनियमितताएं बरती गईं. मनरेगा के फंड का इस्तेमाल उन कामों के लिए किया गया, जो इसके दायरे में नहीं आते. कैग के मुताबिक़, मनरेगा के 13,000 करोड़ रुपये की बंदरबांट हुई और इसका लाभ भी सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है.

14 राज्यों में ऑडिट के दौरान पाया गया कि सवा चार लाख जॉब कार्ड्स में फोटो नहीं थे. 1.26 लाख करोड़ रुपये के 129 लाख प्रॉजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई, लेकिन इनमें से सिर्फ़ 30 फ़ीसद में ही काम हुआ. यह सच्चाई भी सामने आई कि 2,252 करोड़ रुपये ऐसे प्रॉजेक्ट्स के लिए आवंटित कर दिए गए, जो नियम के मुताबिक़ मनरेगा के तहत नहीं आते हैं. सीएजी का यह भी कहना है कि मनरेगा से छोटे राज्यों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन बड़े राज्य जैसे असम, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल और महाराष्ट्र को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार में 46 फ़ीसद लोग ग़रीब हैं, लेकिन सिर्फ़ 20 फ़ीसद फंड का ही लाभ उन लोगों को मिला है. मार्च 2011 में इस योजना के तहत क़रीब 1960.45 करोड़ रुपये निकाले गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है. ग़ौरतलब है कि मनरेगा यूपीए सरकार की फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम है. सवाल यह है कि जिस योजना को इस सरकार ने अपनी नाक का विषय बनाया, जिस योजना का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम से बदल कर उसमें महात्मा गांधी का नाम शामिल करते हुए मनरेगा कर दिया, उसी योजना से महात्मा गांधी के अंत्योदय सिद्धांतों को धता बताते हुए इस सरकार ने केवल अपना उदय किया.

चुनावी पत्ते फेंकने की इसी कड़ी में इसी लोकसभा के माध्यम से चुनावोन्मुखी नीति भोजन गारंटी योजना को भी लागू कराया गया. सरकार ने अपनी चला-चली की बेला में खाद्य सुरक्षा क़ानून लागू किया. अब इस क़ानून के अंतर्गत तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो मोटे अनाज मिलेंगे. खाद्य सुरक्षा बिल के प्रावधानों के मुताबिक़, ग्रामीण इलाक़े के 46 फ़ीसद लोगों को महीने में सात किलो अनाज दिया जाएगा. नवजात बच्चों की माताओं को एक हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. गर्भवती एवं ग़रीब महिलाओं को मुफ़्त में खाना दिया जाएगा. कांग्रेस इस क़ानून को अपने लिए इन चुनावों में रिटर्न टिकट मान रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी योजना के लिए पैसा कहां से आएगा? एनएसी के अनुमान के मुताबिक़, सरकार को इस योजना के लिए क़रीब 28 हज़ार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देनी होगी. मौजूदा राशन की दुकानों से इसे कैसे लागू किया जाएगा, इस पर भी सवाल है. जितनी बड़ी योजना-उतना बड़ा भ्रष्टाचार की कहावत क्या चरितार्थ नहीं होगी? बिल तैयार करने वाली नेशनल एडवायजरी काउंसिल के मुताबिक़, क़ानून बनने के बाद देश की 63 फ़ीसद आबादी को 20 से 25 मिलियन टन अतिरिक्त अनाज की ज़रूरत होगी. कृषि मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि ज़्यादा अनाज पैदा करने के लिए एक लाख 10 हज़ार करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी. राज्य सरकारों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा.

एक अनुमान के मुताबिक़, राज्य सरकारों को सालाना क़रीब 320 करोड़ रुपये एफसीआई के गोदामों से बाज़ार तक की ढुलाई में ख़र्च करने होंगे. आर्थिक संकट से जूझ रहे कई राज्य इस अतिरिक्त भार के लिए तैयार नहीं हैं. बिल में यह भी साफ़ करने की ज़रूरत है कि अगर किसी को अनाज नहीं मिलता है, तो वह कहां शिकायत करेगा? लेकिन, सूत्रों के मुताबिक़ सरकार ने शिकायत निवारण की व्यवस्था खाद्य सुरक्षा एक्ट में नहीं रखी है. इतने लूप होल के साथ यह तय है कि इसकी परिणति भी मनरेगा के रूप में ही होने जा रही है. यूपीए सरकार ने पिछले दस वर्षों में जितनी भी नीतियां बनाईं, सबकी परिणति उसे भ्रष्टाचार के दलदल की ओर ही ले गई. अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखते हैं कि सरकारी कर्मियों द्वारा कितने धन का ग़बन हुआ, यह पता लगाना उतना ही कठिन है, जितना यह पता लगाना कि मछली ने तालाब में कितना पानी पिया. सरकार ने अपनी इन नीतियों, इन योजनाओं के ज़रिये सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्षकों को जनता के रक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया है.

नीतिगत स्तर पर यह लोकसभा हंगामा और शांति के दोहरे चरित्र में दिखाई दी. जिन नीतियों पर चुनावी फ़ायदा दिखा, उन्हें हर हालत में पास कराने की कोशिश की गई और तब विपक्ष एवं सत्तापक्ष एक हो गए. याद कीजिए, पिछले दिनों जब जनलोकपाल बिल संसद में पेश हुआ, तब माकपा नेता प्रकाश करात ने कहा था कि आप दोनों (कांग्रेस और भाजपा) का तो आंखों-आंखों में इशारा हो जाता है और तब संसद में कोई क़ानून या नीति बनने से कौन रोक सकता है. लेकिन जिन फ़ैसलों में सरकार खुद मुश्किल में फंसती दिखी, तब वह पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति में आ गई. यूपीए-2 में लंबे अर्से तक सरकार पर पॉलिसी पैरालिसिस यानी फ़ैसला न ले पाने का आरोप लगता रहा. हालांकि कई मामलों में प्रधानमंत्री गठबंधन धर्म की मजबूरी गिनाते हुए बड़े फ़ैसलों पर अमल करने से कतराते रहे. महंगाई, विदेश नीति एवं आर्थिक सुधारों पर अपनी चुप्पी और काला धन जैसे मुद्दे पर ढिलाई जैसे मसले में कई बार सरकार ने इसी पॉलिसी पैरालिसिस को ढाल बनाकर खुद को छिपाने की कोशिश की.

विचारक इटी व्हाइट ने अपनी किताब-द वंस एफ्यूचर किंग में लिखा है कि ज़्यादातर समाजों में, चाहे वह कितना ही लोकतांत्रिक क्यों न हो, में समाज का बंटवारा कुछ इस तरह से होता है कि वहां सौ लोगों में से नब्बे मूर्ख, नौ धूर्त और एक ही ईमानदार होता है. धूर्तों में से धूर्ततम उनका नेता बन जाता है और मूर्खों का शोषण करता है. एक होने के कारण ईमानदार आदमी अकेला और अलग-थलग पड़ जाता है और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है. वास्तव में इस लोकसभा को इटी व्हाइट का यह विचार पूरी तरह से पारिभाषित करता है. मौजूदा लोकसभा के आख़िरी दिन हमें इसी तस्वीर की ओर ले जाते हैं, जब मूर्खों के ऐसे ही समूहों ने अपने स्वार्थ लाभ और एक-दूसरे को पछाड़ने की होड़ में हर वे हथकंडे अपनाए, जिनके चलते इस मौजूदा लोकसभा का एक दिन भारतीय लोकतंत्र में सबसे काले दिन के तौर पर दर्ज हो गया.

एक आम राय है कि इस लोकसभा का प्रदर्शन देश के समूचे लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे खराब रहा. आख़िर इसका ज़िम्मेदार कौन है? जब इस लोकसभा का समापन हो रहा था, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा, माना कि मतभेद बहुत रहे, लेकिन देश हित में सबने कोशिश की, तो रास्ता निकला. उन्होंने कहा कि तेलंगाना विधेयक के पारित होने से संकेत मिलता है कि यह देश मुश्किल फ़ैसले ले सकता है. लेकिन, सवाल यह है कि यह मसला कोई आज का नहीं है, फिर फ़ैसला अभी क्यों लिया गया? इस सवाल पर मनमोहन सिंह एक बार फिर मौन हो जाएंगे और धूमिल के शब्दों में, इस देश की संसद भी मौन हो जाएगी. लेकिन, सवाल फिर भी बना रहेगा कि पंद्रहवीं लोकसभा में बनाई गईं नीतियां किसके लिए हैं, लोक के लिए या लोभ के लिए? ■

feedback@chauthiduniya.com

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम से मिला अनाज का अधिकार

4.98 करोड़ घरों को मनरेगा से रोज़गार

19.97 करोड़ बच्चों को मिला अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा का अधिकार

सूचना के अधिकार ने प्रत्येक नागरिक को सरकार को जवाबदेही बनाने का अधिकार दिया

भारत निर्माण के प्रमाण

जन-जन को छुआ, जन-जीवन बदला

davp 22111/13/0293/1314

> इस लोकसभा की शुरुआत में ठीकठाक काम चलता रहा, लेकिन जैसे ही 2010 के दौरान 2जी मामला सामने आया, संसद में भारी गतिरोध शुरू हो गया. इसके बाद लगातार संसद में विभिन्न मुद्दों जैसे कोल ब्लॉक, लोकपाल से लेकर तेलंगाना तक यह गतिरोध बना रहा.

15वीं लोकसभा

किया न धरा, गिलास तोड़ा बारह आना

शशि शेखर

सांसदों का मूल काम होता है विधेयक बनाना. संसद में बैठे सांसदों से यही अपेक्षा की जाती है कि वे देशहित एवं जनहित में बेहतरीन क़ानून बनाने का काम करेंगे. इस लिहाज से देखें, तो पंद्रहवीं लोकसभा कामकाज के मामले में अब तक की सबसे फिसड्डी लोकसभा साबित हुई है. संसद के एक सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही के एक मिनट के लिए जनता की जेब से 2.5 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं. सत्र चलने के दौरान सांसदों को अलग से हज़ारों रुपये रोजाना भत्ते के रूप में दिए जाते हैं. ऐसे में इन महानुभावों से यही उम्मीद की जाती है कि ये संसद में बैठकर जनता से जुड़ी समस्याओं पर बात करेंगे, उनके समाधान के लिए क़ानून बनाएंगे. इस हिसाब से अगर एक सत्र का एक दिन औसतन आठ घंटे का हो और उस दिन अगर कोई काम न हो, तो जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाते हैं.

पिछले 62 सालों के संसदीय इतिहास में इस 15वीं लोकसभा ने निकम्मेपन का कीर्तिमान स्थापित किया है. पहली से लेकर पांचवीं लोकसभा, जो पांच साल तक चली, ने न्यूनतम 216 और अधिकतम 482 विधेयक पास किए. एनडीए के शासनकाल (1999 से 2004) में भी 297 विधेयक पास किए गए. खुद यूपीए–1 की सरकार ने भी (2004 से 2009 के बीच) 248 विधेयक पास किए, लेकिन यूपीए–2 के दौरान यानी पंद्रहवीं लोकसभा क़रीब 165 विधेयक ही पारित हो सके. इसके अलावा, जहां तक सत्र के दौरान बर्बाद हुए समय का सवाल है, तो इस दौरान ऐसे कई मौक़े आए, जब एक पूरे सत्र के दौरान 99 फ़ीसद से भी अधिक समय संसद में बैठे महानुभावों के हंगामे की भेंट चढ़ गया. सिर्फ़ पहला सत्र (एक जून से 9 जून, 2009) ही ऐसा रहा, जिसमें 100 फ़ीसद काम हुआ. ग़ौरतलब है कि यह सत्र यूपीए–2 के सत्ता में आने के तुरंत बाद आयोजित किया गया था. 15वीं लोकसभा में महज 61 फ़ीसद समय ही हमारे महानुभावों ने काम किया यानी 39 फ़ीसद वक्त हंगामे और शोर–शराबे के नाम रहा. यह आंकड़ा संसदीय इतिहास में एक नया कीर्तिमान है.

ग़ौरतलब है कि इस लोकसभा की शुरुआत में ठीकठाक काम चलता रहा, लेकिन जैसे ही 2010 के दौरान 2जी मामला सामने आया, संसद में भारी गतिरोध शुरू हो गया. इसके बाद लगातार संसद में विभिन्न मुद्दों जैसे कोल ब्लॉक, लोकपाल से लेकर तेलंगाना तक यह गतिरोध बना रहा. ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे जनप्रतिनिधि संसद में जाकर आख़िर करते क्या हैं? क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनके एक–एक मिनट के लिए जनता की जेब से लाखों रुपये खर्च होते हैं. पांच सालों के दौरान इस लोकसभा ने अब तक के इतिहास में सबसे कम काम किया है और दूसरी तरफ़ माननीय सांसदों ने सदन की बैठक बाधित करने, वक्त खराब करने, सदन की कार्यवाही स्थगित कराने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी. मजेदार बात यह है कि इस सबमें न सिर्फ विपक्ष, बल्कि सत्ता पक्ष के सांसद भी पीछे नहीं रहे. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

कितने घंटे काम, कितने घंटे बर्बाद

(जून 2009 से मई 2013 के बीच 13 सत्रों के दौरान)

सत्र	काम	समय की बर्बादी
प्रथम सत्र (1 जून–9 जून, 2009)	100 फ़ीसद	शून्य फ़ीसद
दूसरा सत्र (2 जुलाई–7 अगस्त, 2009)	87.4 फ़ीसद	12.6 फ़ीसद
तीसरा सत्र (19 नवंबर–18 दिसंबर, 2009)	76.9 फ़ीसद	23.1 फ़ीसद
चौथा सत्र (22 फरवरी–7 मई, 2010)	66.4 फ़ीसद	33.6 फ़ीसद
पांचवां सत्र (26 जुलाई–31 अगस्त, 2010)	75.2 फ़ीसद	24.8 फ़ीसद
छठा सत्र (9 नवंबर–13 दिसंबर, 2010)	6 फ़ीसद	99.4 फ़ीसद
सातवां सत्र (21 फरवरी–25 मार्च, 2011)	82.2 फ़ीसद	17.8 फ़ीसद
आठवां (1 अगस्त–8 सितंबर, 2011)	67.1 फ़ीसद	32.9 फ़ीसद
नौवां (22 नवंबर–21 दिसंबर, 2011)	52.7 फ़ीसद	47.3 फ़ीसद
दसवां (12–30 मार्च, 24 अप्रैल–22 मई, 2012)	79.5 फ़ीसद	20.5 फ़ीसद
ग्यारहवां (8 अगस्त–7 सितंबर, 2012)	76.2 फ़ीसद	23.8 फ़ीसद
बारहवां (22 नवंबर–20 दिसंबर, 2012)	51 फ़ीसद	49 फ़ीसद
तेरहवां (21 फरवरी–22 मार्च और 22 अप्रैल–10 मई 2013)	50.5 फ़ीसद	49.5 फ़ीसद

लोकसभा		बिल पास हुए
पहली	(1952)	333
दूसरी	(1957)	327
तीसरी	(1962)	272
चौथी	(1967)	216
पांचवीं	(1971)	482
छठी	(1977)	130
सातवीं	(1980)	329
आठवीं	(1984)	334
नौवीं	(1989)	63
दसवीं	(1991)	277
ग्यारहवीं	(1996)	61
बारहवीं	(1998)	56
तेरहवीं	(1999)	297
चौदहवीं	(2004)	248
पंद्रहवीं	(2009)	165 (दिसंबर, 2013 तक)

15वीं लोकसभा

घोटालेबाज़ों की सभा

राजीव रंजन

> 15वीं लोकसभा का सत्र समाप्त हो चुका है. लोकसभा के पांच वर्षों के दौरान सांसदों ने जिस तरह से घोटाले किए, देश को लूटा, उससे लगता है कि इन सांसदों ने एक–दूसरे को बेशर्म और खुली लूट को चुनौती दे रखी थी. इन सांसदों ने दोनों हाथों से देश को लूटा. इस तरह 15वीं लोकसभा बन गई घोटालासभा.

गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि पूरी प्रकृति के पास इतने अधिक संसाधन हैं कि वह प्रत्येक मनुष्य का पेट भर सकती है, लेकिन वह संसाधन इतना भी नहीं है कि किसी एक लालची का पेट भरा जा सके. सच है कि लुटेरों या भ्रष्टों को पूरी पृथ्वी भी दे दी जाए, तो कम पड़ेगी. कम से कम 15वीं लोकसभा के दौरान सांसदों ने जिस तरह से देश को लूटा, जिस तरह विभिन्न घोटालों में उनके नाम सामने आए, उससे यही पता चलता है कि स्वार्थ में अंधा शख्स किसी भी हद तक गिर सकता है. मीडिया के माध्यम से देश के कुछ नामी–गिरामी सांसदों के नाम विभिन्न घोटालों में सामने आए. इनमें प्रमुख नाम हैं–प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, शरद पवार, सलमान खुर्शीद, लालू यादव, जगदीश शर्मा, रशीद मसूद, पवन बंसल, सुरेश कलमाड़ी, दयानिधि मारन, ए राजा, कनिमोझी और सुप्रिया सुले. इन घोटालेबाज सांसदों की फेहरिस्त यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह काफी लंबी है, जिसमें सत्ता पक्ष के सांसद ही नहीं, बल्कि विपक्ष और अन्य राज्यों के सांसद भी सम्मिलित हैं. हम कुछ ऐसे ही सांसदों की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जिन पर घोटाले का आरोप लगने से देश शर्मसार हुआ.

मनमोहन सिंह और सुबोधकांत सहाय

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सांसद और सुबोधकांत सहाय रांची से लोकसभा सांसद हैं. सुबोधकांत सहाय का नाम प्रमुखता से कोयला घोटाले से जुड़ा. सरकार पर आरोप है कि उसने कोयला ब्लॉक का आवंटन गलत तरीके से किया. उस समय सुबोध कोयला मंत्री थे. इस घोटाले की खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी अपने मातहतों को बचाने का आरोप लगा. सीएजी की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक, इस घोटाले के कारण सरकारी खजाने को एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. जिन लोगों के नाम कोयला ब्लॉक आवंटन की गड़बड़ी में सामने आए, उनमें केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय, भाजपा के राज्यसभा सांसद अजय संचेती, कांग्रेस नेता विजय दर्डा एवं राजेंद्र दर्डा, आरजेडी नेता एवं पूर्व कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और कांग्रेस सांसद एवं जिंदल स्टील एंड पॉवर के चेयरमैन नवीन जिंदल प्रमुख हैं. इसी दौरान यह बात सामने आई कि क़ानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई को कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट में कुछ बदलाव करने को कहा है.

ए राजा

ए राजा तमिलनाडु के नीलगिरी से सांसद हैं. आरोप है कि 2008 में ए राजा ने दूरसंचार मंत्री रहते हुए स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में नियमों में हेर–फेर करके कुछ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया. 1,76,000 करोड़ रुपये के इस घोटाले में साजिश, धोखाधड़ी, नकली दस्तावेज पेश करने के साथ ही पद के दुरुपयोग और गलत काम के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए. प्रधानमंत्री को भी इस मामले में देर से जागने के लिए कई बार फटकार लग चुकी है. द्रमुक अध्यक्ष करुणानिधि की पुत्री एवं राज्यसभा सांसद कनिमोझी का भी नाम दूरसंचार घोटाले से जुड़ा. कनिमोझी पर आरोप है कि वह ए राजा की सबसे बड़ी राजदार हैं.

शरद पवार और सुप्रिया सुले

केंद्रीय मंत्री शरद पवार माधा से और उनकी पुत्री सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा सांसद हैं. भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से वकील बने वाई पी सिंह ने केंद्रीय मंत्री शरद पवार और उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने विवादित लवासा हिल सिटी परियोजना के लिए एक निजी डेवलपर को कथित तौर पर अनुचित फ़ायदा पहुंचाया. लवासा को महज 23,000 रुपये के मासिक किराये पर जमीन आवंटित की गई. वाई पी सिंह की ओर से जारी बयानों के मुताबिक, शरद पवार की बेटी एवं बारामती से लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले के पास कंपनी के 20.81 फ़ीसद शेयर थे. सिंह ने दावा किया कि 2006 में सुले ने अपने सारे शेयर लवासा कॉरपोरेशन को बेच दिए.

सलमान खुर्शीद

सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद से लोकसभा सांसद हैं. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट सलमान खुर्शीद के दादा और पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाम पर है. सलमान की पत्नी लुईस खुर्शीद इस ट्रस्ट की कार्यकारी अधिकारी हैं. कुछ महीने पहले ही आरोप लगा था कि ट्रस्ट ने सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिए जारी 71 लाख रुपये का गबन किया है. हालांकि लुईस इन आरोपों को खारिज करती हैं.

मुलायम सिंह यादव

मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं. उत्तर प्रदेश खाद्यान्न घोटाला 2002 से 2010 के बीच हुआ. उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे. यह घोटाला लगभग 3500 करोड़ रुपये का था. आरोप है कि पीडीएस के तहत जो खाद्यान्न ग़रीबों में वितरित किया जाना था, उसे खुले बाज़ार में बेच दिया गया. आरोप तो यहां तक है कि इन खाद्यान्नों को बांग्लादेश और नेपाल में बेचने के लिए भेजा जाता था. इस क्रम में बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों को सुरक्षाबलों ने सीज भी किया था. सबसे पहले यह घोटाला 2003 में सामने आया.

पवन बंसल

चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल का नाम घूस कांड से जुड़ा. आरोप है कि पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला ने ट्रांसफर–पोस्टिंग के लिए रिश्वत ली. विपक्ष और जनता के बढ़ते दबाव के बीच रेल मंत्री पवन बंसल को इन आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा. बंसल को 10 करोड़ रुपये के रेल घूस कांड मामले में अभियोजन पक्ष का गवाह नामित किया गया है. 3 मई, 2013 को सीबीआई ने रेल मंत्री के भांजे विजय सिंगला को 90 लाख रुपये घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया. महेश कुमार पर सिंगला को प्रमोशन के लिए घूस देने का आरोप है. आरोप है कि प्रमोशन के लिए 10 करोड़ रुपये की रकम तय की गई थी. महेश कुमार ने एडवांस के तौर पर सिंगला को 90 लाख रुपये एक कुरियर के माध्यम से भेजे.

लालू यादव और जगदीश शर्मा

राजद अध्यक्ष लालू यादव सारण और जदयू नेता जगदीश शर्मा जहानाबाद से लोकसभा सांसद रह चुके हैं. लालू प्रसाद यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहरा दिया गया है. चुनाव आयोग के नए नियमों के अनुसार, लालू प्रसाद अब 11 साल तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. जगदीश शर्मा को भी 10 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है. चारा घोटाले को पशुपालन घोटाला भी कहते हैं. यह स्वतंत्र भारत के बिहार राज्य का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के नाम पर 950 करोड़ रुपये सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ा करके निकाल लिए गए. हालांकि यह घोटाला 1996 में हुआ था.

सुरेश कलमाड़ी

सुरेश कलमाड़ी पुणे से लोकसभा सांसद हैं. 70,000 करोड़ रुपये के कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले (2011) में उनका नाम सामने आया. यह भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है. आरोप है कि नई दिल्ली में आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के दौरान पैसों की बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई. उस समय सुरेश कलमाड़ी दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति के अध्यक्ष थे.

दयानिधि मारन

डीएमके सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन चेन्नई सेंट्रल से लोकसभा सांसद हैं. चेन्नई में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के आवास तक 300 से ज़्यादा हाईस्पीड टेलीफोन लाइनों के आवंटन और इन लाइनों द्वारा मारन के भाई के चैनल सन टीवी को लाभ पहुंचाने का आरोप है. मारन पर यह भी आरोप है कि जब वह दूरसंचार मंत्री थे, तब उन्होंने एयरसेल की कई सर्किलों के लिए लाइसेंस देने का फ़ैसला लटका रखा था. मारन इन आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

मनमोहन सिंह

लालू प्रसाद यादव

जगदीश शर्मा

सलमान खुर्शीद

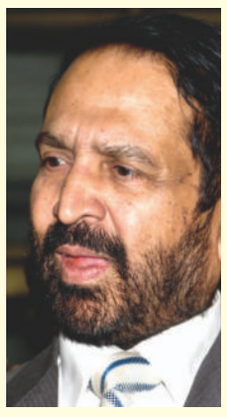
सुरेश कलमाड़ी

ए राजा

शरद पवार

सुप्रिया सुले

पवन बंसल

दयानिधि मारन

पंद्रहवीं लोकसभा में एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहली बार लोकसभा में लगभग सभी उच्चशिक्षा प्राप्त और नौकरीपेशा महिलाएं थीं. भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि इसमें अनपढ़ लोग भी आ जाते हैं. हालांकि, इस बार की लोकसभा में महत्वपूर्ण यह बात थी कि जहां पुरुष सांसद 30 प्रतिशत थे, वहीं 32 प्रतिशत महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएट थीं, जबकि 46 प्रतिशत पुरुष सांसद स्नातक थे.

15वीं लोकसभा

महिलाओं में निराशा

वसीम राशिद

पंद्रहवीं लोकसभा इस लिहाज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी अध्यक्ष मीरा कुमार हैं. वैसे तो सदन में सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, जयाप्रदा, मीनाक्षी नटराजन, मेनका गांधी जैसी कई महिला राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन पंद्रहवीं लोकसभा इस मायने में भी ख़ास महत्व रखती है कि इसमें महिलाओं का प्रतिशत पहली लोकसभा से लेकर चौदहवीं लोकसभा तक सबसे अधिक था.

ग़ौरतलब है कि वर्ष 1994 के लोकसभा चुनाव में कुल 284 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं, जिसमें 49 महिलाओं ने जीत हासिल की थी. वर्ष 2004 के चुनाव में 355 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं, लेकिन उनमें केवल 45 महिलाएं ही लोकसभा में पहुंच पाईं. इसी तरह वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में 556 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थीं, जिनमें से 59 महिलाएं पंद्रहवीं लोकसभा में अपनी जगह बना पाईं और आज़ादी के बाद यह सबसे बड़ा प्रतिशत था, जिसके बाद में दो महिलाएं डिम्पल यादव लोकसभा मध्यावधि चुनाव 2012 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से और गिरिजा व्यास जून, 2013 में चुनकर आईं. इस तरह यह तादाद बढ़कर 161 हो गई. ज्ञात हो कि छठी लोकसभा में यह महिलाओं की भागीदारी केवल 3.8 प्रतिशत था, पहली लोकसभा में यह केवल 4.4 प्रतिशत ही था. तेरहवीं लोकसभा में लगभग 9.2 प्रतिशत महिलाएं लोकसभा में थीं और वर्ष 2009 में यह सबसे अधिक 10 प्रतिशत था.

आंकड़ों की बात करें, तो पंद्रहवीं लोकसभा में कांग्रेस से 23 महिला सांसद, भाजपा से 13 महिला सांसद, समाजवादी पार्टी से 1, बसपा से 1, जनता दल (यू) से 2, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से 2, तेलंगाना राष्ट्र समिति से 1, आरजेडी, शिवसेना, डीएमके, सीपीएम सबसे एक-एक महिला सांसद लोकसभा में पहुंची थीं. उनमें उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक महिला सांसद हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की 7 महिला सांसद थीं.

पंद्रहवीं लोकसभा में एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहली बार लोकसभा में लगभग सभी उच्चशिक्षा प्राप्त और नौकरीपेशा महिलाएं थीं. भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि इसमें अनपढ़ लोग भी आ जाते हैं. हालांकि, इस बार की लोकसभा में महत्वपूर्ण यह बात थी कि जहां पुरुष सांसद 30 प्रतिशत थे, वहीं 32 प्रतिशत महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएट थीं, जबकि 46 प्रतिशत पुरुष सांसद स्नातक थे. उनके मुक़ाबले 42 प्रतिशत महिलाएं स्नातक थीं. महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पुरुष सांसदों की उम्र का अनुपात 54 वर्ष था, वहीं महिलाओं में यह प्रतिशत 47 वर्ष था.

पंद्रहवीं लोकसभा में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं के लिए कई विकास योजनाएं बनाईं थी. इसमें 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देना उसकी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन लोकसभा के अंतिम सत्र में भी यह विधेयक पास नहीं हो पाया. महिला आरक्षण

बिल के प्रावधानों के मुताबिक़, लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना था. इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौडा ने 12 सितंबर, 1996 को पेश किया था. उसके बाद यह कई बार लोकसभा में पेश किया गया. राज्यसभा में यह बिल 9 मार्च, 2010 में ही पास हो गया था. हालांकि, इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ था. इस विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों में मतभेद इतना गहरा है कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद तक ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी थी. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के मुताबिक़, महिला आरक्षण का लाभ केवल उंची जातियों के महिलाओं को ही मिलेगा. दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति के महिलाओं को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए उनके लिए अलग से आरक्षण दिया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इस आरक्षण में केवल शिक्षित शहरी महिलाओं का क़ब्ज़ा हो जाएगा. चूंकि यह एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है, इसलिए इस बिल का दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से पास होना आवश्यक था, जो अब तक नहीं हो पाया है. बिल को लेकर मायावती को आपत्ति थी कि इस बिल को पेश करने से पहले उनकी पार्टी के सुझावों को विधेयक के मसौदे में शामिल नहीं किया गया. इसलिए उनकी पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ममता बनर्जी ने इस बिल का विरोध एक बड़े कारण को लेकर किया था. उनका कहना था कि इस बिल को जिस प्रकार राज्यसभा में पेश किया गया, वह तरीक़ा सही नहीं था. उनके मुताबिक़, इस बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की बात नहीं है.

हैरानी की बात यह है कि सोनिया गांधी जैसी सशक्त महिला, जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं. वह खाद्य सुरक्षा बिल पास कराने में सफल तो हो गईं, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं करा पाईं.

अगर महिला आरक्षण विधेयक पास हो जाता, तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 61 से बढ़कर 181 के क़रीब हो जाती. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी

लोकसभा	वर्ष	महिला सांसदों का प्रतिशत
1	1952	4.4 %
2	1957	4.5 %
3	1962	6.7 %
4.	1967	5.8 %
5.	1971	4.9 %
6.	1977	3.8 %
7.	1980	5.7 %
8.	1985	7.9 %
9.	1989	5.2 %
10.	1991	7.6 %
11.	1996	7.4 %
12.	1998	8.1 %
13.	1991	9.2 %
14.	2004	8.7 %
15.	2009	10.7%

15वीं लोकसभा

फिर खाली हाथ रह गए अल्पसंख्यक

ए यू आसिफ़

2001 की जनसंख्या के अनुसार, भारत में लगभग 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक (सरकारी मान्यता प्राप्त) हैं, जिनमें मुसलमान 13.4 प्रतिशत, ईसाई 2.3 प्रतिशत, सिख 1.9 प्रतिशत, बौद्ध 0.8 प्रतिशत, जैन 0.4 प्रतिशत एवं पारसी .006 प्रतिशत हैं. इस लिहाज़ से मुसलमान देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं, लेकिन विकास की दौड़ में सबसे पीछे हैं. यह बात सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से भी साबित होती है, जिसकी रोशनी में विभिन्न सरकारी योजनाएं बनाई गईं, लेकिन नतीजे अभी भी निराशाजनक हैं. प्रश्न उठता है कि यह निराशाजनक स्थिति है क्या? इसके लिए असल ज़िम्मेदार कौन है? हाल में अपना कार्यकाल समाप्त कर चुकी 15वीं लोकसभा के दौरान राष्ट्र के 543 संसदीय क्षेत्रों में से क़ाबिले ज़िक्र मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में विकास के काम क्या-क्या हुए एवं कितनी धनराशि किस सांसद द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पाई? मुस्लिम सांसद संसद सत्र के दौरान कितने सक्रिय रहे और उन्होंने सदन में कितने मुद्दे उठाए?

ज़ाहिर है कि इस पूरे मामले में नौकरशाहों के साथ-साथ सांसद सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं. सरकारी वेबसाइट्स के आंकड़े बताते हैं कि 15वीं लोकसभा के दौरान क़ाबिले ज़िक्र मुस्लिम आबादी वाले लोकसभा क्षेत्रों में 13 फरवरी, 2014 तक विभिन्न सांसदों के 292.97 करोड़ रुपये इस्तेमाल नहीं किए जा सके. इन क्षेत्रों के कांग्रेसी सांसदों द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई धनराशि 93 करोड़ रुपये रही, जबकि भाजपा सांसद के पास 79 करोड़ रुपये. स्मरण रहे कि सांसद निधि को इस्तेमाल न करने के मामले में दरभंगा (बिहार) के भाजपा सांसद कीर्ति आज़ाद पहले नंबर पर हैं. उन्होंने अपनी निधि के 7.43 करोड़ रुपये इस्तेमाल नहीं किए, जो उन्हें मिली धनराशि का लगभग 60 प्रतिशत है. दूसरे एवं तीसरे नंबर पर हैं राजमहल (झारखंड) से भाजपा सांसद देवीधन बेश्रा और धुबड़ी (असम) से असम डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसद मौलाना बदरूद्दीन अजमल क़ासमी, जिनके पास अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक फंड पड़ा हुआ है.

में भी मौजूद हैं. धुबड़ी जैसे पिछड़े क्षेत्र की जनता ने भरोसा करके उन्हें लोकसभा भेजा था, लेकिन मायूसी ही उसके हाथ लगी. क़ासमी अपनी सांसद निधि का 50 फ़ीसद हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर पाए और न संसद में क्षेत्र के विकास के लिए कोई आवाज़ उठा सके.

इस मामले में भाजपा एवं कांग्रेस, दोनों के सदस्यों की स्थिति सोचनीय है. इन 70 से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रतिनिधि भाजपा या कांग्रेस से संबंध रखते हैं. इन क्षेत्रों में भाजपा के सदस्य कुल 28.5 प्रतिशत और कांग्रेस के सदस्य 24.8 प्रतिशत फंड इस्तेमाल नहीं कर सके, जबकि मौलाना क़ासमी (एयूडीएफ) द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई धनराशि सांसद निधि का 56.8 प्रतिशत है. यही स्थिति कमोबेश दो स्वतंत्र सांसदों की है. जयनगर (पश्चिमी बंगाल) के सांसद तरुण मंडल 40 प्रतिशत और लद्दाख के सांसद हसन खान 30 प्रतिशत धनराशि इस्तेमाल नहीं कर पाए. वैसे यह बात भी कम चौंकाने वाली नहीं है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र गोड्डा (झारखंड) के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड बनाया है. अपनी-अपनी सांसद निधि का

कीर्ति आज़ाद

मौलाना बदरुद्दीन अजमल क़ासमी

फ़ारूक़ अब्दुल्लाह

ई अहमद

जाफ़र अली नाकामी

क़ादिर राणा

अब्दुल मन्नान हुसैन

मौलाना असरारुल हक़ क़ासमी

स्मरण रहे कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रत्येक सांसद को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट (एमपीएलएडी) के अंतर्गत मिला फंड सांसद निधि कहलाता है. 20 से 95 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या वाले क्षेत्र दरभंगा में भाजपा सांसद कीर्ति आज़ाद द्वारा सांसद निधि का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल न करके सूची में सबसे ऊपर होना आश्चर्यजनक है, क्योंकि दरभंगा वही क्षेत्र है, जहां राजद के पूर्व सांसद एवं पूर्व मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री मुहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी ने अपनी सांसद निधि के ज़्यादातर पैसों का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड कायम किया था. उनसे पूर्व 1971 में कांग्रेस के स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने भी यहां से निर्वाचित होकर इस क्षेत्र को विकास की दौड़ में शामिल किया था. दरभंगा की जनता को आशा थी कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्रिकेट खिलाड़ी कीर्ति आज़ाद के सांसद बनने से क्षेत्र और अधिक विकास करेगा, लेकिन उसे निराशा मिली. इसी तरह धुबड़ी से एयूडीएफ के मौलाना बदरूद्दीन अजमल क़ासमी द्वारा 56.8 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल न करना भी बहुत निराशाजनक है. मौलाना क़ासमी एयूडीएफ के इकलौते सांसद हैं और उनकी पार्टी के 18 सदस्य असम विधानसभा ठीक से इस्तेमाल करने वाले सांसदों में संभल (उत्तर प्रदेश) से बहुजन समाज पार्टी के शफीकुर्रहमान बर्क, हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लेमीन के असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली उत्तर-पूर्व से कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल और क़ैसरगंज (उत्तर प्रदेश) से समाजवादी पार्टी के बृजभूषण शरण सिंह के नाम शामिल हैं. अब आइए देखते हैं कि 15वीं लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि क्या करते रहे? उनकी इसके विभिन्न सत्रों में उपस्थिति क्या रही? उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं के अलावा मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मुद्दे कितने और किस तरह उठाए? 15वीं लोकसभा में कुल 30 मुस्लिम सांसद थे, जो उस सदन में निश्चय ही चर्चा के पात्र नहीं हैं, जहां 1980 में 49 सांसद निर्वाचित होकर पहुंचे हों. आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न मुस्लिम प्रतिनिधियों में बहुजन समाज पार्टी के शफीकुर्रहमान बर्क़ 15वीं लोकसभा में 350 दिनों में 344 दिन उपस्थित होकर सूची में सबसे ऊपर रहे, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लेमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने 1046 प्रश्न उठाकर रिकॉर्ड बनाया. इसी प्रकार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सईदुल हक़ ने 95 और कांग्रेस सांसद एवं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने 60 बहसों में भाग लेकर सुर्खियां हासिल कीं. वहीं खीरी (उत्तर प्रदेश) से कांग्रेस के सांसद ज़फ़र अली नकवी ने 280 दिन, बहुजन समाज पार्टी की कैराना (उत्तर प्रदेश) से सांसद बेगम तबस्सुम हसन ने 252 दिन, बहुजन समाज पार्टी के सांसद क़ादिर राणा ने 202 दिन, कांग्रेस के इस्माइल हुसैन ने 329 और कांग्रेस के अब्दुल मन्नान हुसैन ने 212 दिन उपस्थित रहकर भी किसी बहस में हिस्सा नहीं लिया. क़ाबिले जिक्र है कि लक्ष्यद्वीप के कांग्रेस सांसद मुहम्मद हमदुल्लाह सईद को छोड़कर किसी ने भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की. उन्होंने प्रधानमंत्री से 2 प्रश्न पूछे. भाजपा के इकलौते मुस्लिम सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन ने 642 प्रश्न पूछे, लेकिन उनमें से मात्र 3 प्रश्न (0.5 प्रतिशत से भी कम) अल्पसंख्यकों की समस्याओं से संबंधित थे. श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) से नेशनल कांफ्रेंस के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉ. फारुक़ अब्दुल्ला सिर्फ़ एक प्रश्न उठा पाए. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सर्वेसर्वा, मल्लपूरम (केरल) से सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री ई अहमद अपनी सांसद निधि के 3.09 करोड़ रुपये इस्तेमाल नहीं कर सके और संसद में एक भी प्रश्न नहीं उठा पाए. किशनगंज (बिहार) से कांग्रेस के सांसद एवं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के उपाध्यक्ष मौलाना असरारुल हक़ क़ासमी 331 दिन उपस्थित रहे और उन्होंने 56 प्रश्न भी पूछे, लेकिन अपनी सांसद निधि के 3.20 करोड़ रुपये इस्तेमाल नहीं कर सके.

15वीं लोकसभा से संबंधित यह विवरण निश्चय ही निराशाजनक है. सवाल पैदा होता है कि धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर उठकर क्या ये सांसद अपने-अपने क्षेत्र में कामकाज की बुनियाद पर प्रतिनिधित्व के योग्य हैं? क्या इलाकाई जनता 16वीं लोकसभा के लिए उन्हें एक बार फिर चुनेगी? दरअसल, मतदाता अब जाग उठे हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब-तलब कर रहे हैं. विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के लिए यह रिपोर्ट कार्ड ख़तरे की घंटी है और जो राजनीतिक पार्टियां उन्हें टिकट देती हैं, उनके लिए भी यह सोचने की बात है. ऐसे में स्वतंत्र उम्मीदवारों की ज़िम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्षेत्र में अपने विकास कार्यों की बुनियाद पर जनता की आवाज़ बनना चाहिए और उनके प्रतिनिधि भी. इसी में सबकी भलाई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> महिला आरक्षण बिल की कहानी तो बेहद अफ़सोसनाक बन गई है. वह भी ऐसी लोकसभा में, जहां सत्तारूढ़ यूपीए सरकार की अध्यक्ष एक महिला हैं, लोकसभा की अध्यक्ष एक महिला हैं और विपक्ष की नेता भी महिला हैं. ऐसे में महिलाओं के लिए अहम माने जाने वाले इस विधेयक का पारित न हो पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

15वीं लोकसभा के सत्र का समापन

अधर में लटके महत्वपूर्ण विधेयक

लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद देश की करोड़ों जनता का प्रतिनिधित्व करती है. सदन की शोभा सांसदों से नहीं, बल्कि उनके कार्यों और आचरण से बढ़ती है. इसे पंद्रहवीं लोकसभा के सत्र का स्याह पक्ष ही कहा जाएगा कि जिस अनुपात में विधेयक पारित होने चाहिए, वह हंगामे और वॉकआउट की वजह से नहीं हो पाए. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या संसद राजनेताओं के लिए अपनी पार्टी का प्रचार और अनावश्यक रूप से शोर-शराबा करने का एक केंद्र बन गई है?

पास होने वाले महत्वपूर्ण विधेयक

- भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना विधेयक 2011
- लोकपाल विधेयक-2011
- शिक्षा का अधिकार क़ानून
- खाद्य सुरक्षा क़ानून
- रजिस्ट्रेशन एमेंडमेंट बिल-2013
- बैंकिंग लॉ एमेंडमेंट बिल-2011

लंबित महत्वपूर्ण विधेयक

- महिला आरक्षण विधेयक-2008
- शत्रु संपदा (एनेमी प्रॉपर्टी) एमेंडमेंट बिल-2010
- बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एमेंडमेंट बिल-2011
- न्यूक्लियर सेफ्टी रेग्युलेरिटी अथॉरिटी विधेयक-2011
- दिल्ली रेंट एमेंडमेंट बिल-1997
- मोटर व्हीकल्स कोड बिल-2010
- उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार और शोध विधेयक-2011
- टेलीकॉम रेग्युलेरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एमेंडमेंट बिल-2008

लैप्स होने वाले विधेयक

- नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल-2009
- पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना विधेयक-2007
- दामोदर घाटी निगम विधेयक-2007
- मेट्रो रेल एमेंडमेंट बिल-2009
- नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एमेंडमेंट बिल-2008

अभिषेक रंजन सिंह

पंद्रहवीं लोकसभा के सत्र का समापन पिछले दिनों हो गया, लेकिन संसदीय कामकाज और राजनीतिक शुचिता के लिहाज़ से इसे सबसे निराशाजनक कहा जाएगा. जहां तेरहवीं और चौदहवीं लोकसभा में कार्य निष्पादन की दर 91 और 87 प्रतिशत थी, वहीं मौजूदा लोकसभा में यह घटकर 72 प्रतिशत पर आ गई. पिछले साल शीतकालीन और मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गए. पिछले 25 वर्षों में पंद्रहवीं लोकसभा पहली ऐसी लोकसभा रही है, जिसकी कार्यवाही न सिर्फ़ सर्वाधिक बाधित हुई है, बल्कि इसकी कार्यक्षमता में भी भारी गिरावट आई. पंद्रहवीं लोकसभा के विभिन्न सत्रों में कुल 177 विधेयक पारित हुए, जिनमें लोकपाल क़ानून और भूमि अधिग्रहण विधेयक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे. हालांकि, दर्जनों ऐसे विधेयक हैं, जो अभी भी लंबित पड़े हुए हैं और क़ानून बनने की बाट जोह रहे हैं.

लोकसभा सचिवालय में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक़, पंद्रहवीं लोकसभा में पारित किए गए कुल विधेयकों में 17 प्रतिशत विधेयक ऐसे थे, जिन पर सदन में पांच मिनट से भी कम वक्त चर्चा की गई. उल्लेखनीय है कि पंद्रहवीं लोकसभा का विस्तारित सत्र का समापन 21 फरवरी को हुआ, जिसमें तेलंगाना विधेयक को किसी तरह पारित कराया जा सका, लेकिन इसे पारित कराने के लिए सदन में जिस तरह अमर्यादित आचरण किया गया, उसे किसी भी सूरत में जायज क़रार नहीं दिया जा सकता. हालांकि, पंद्रहवीं लोकसभा में व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक और सिटीजन चार्टर जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, लेकिन काफी कम समय में सरकार ने इतने सारे महत्वपूर्ण बिल पारित कराने की हड़बड़ी क्यों की? क्या पिछले नौ सालों में उसे इनकी सुध नहीं आई, जबकि इन विधेयकों को पारित कराने की मांग काफी पुरानी है?

पंद्रहवीं लोकसभा वाकई यादगार रहेगी. न सिर्फ़ इसलिए कि इसमें सबसे कम काम हुआ, बल्कि इसलिए भी कि हमारे माननीय सांसदों ने सर्वोच्च सदन की गरिमा को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. पिछली लोकसभा में परमाणु बिल पर मतदान के समय नोटों की गड्डियां सदन के भीतर लहराए जाने की घटना हम सबके जेहन में क़ायम है. इस बार तेलंगाना विरोधी माननीय सांसदों ने लोकसभा में मिर्ची स्प्रे करके अमर्यादित आचरण की एक नई इबारत लिख दी. पंद्रहवीं लोकसभा में महज 177 विधेयक ही पास हुए, जबकि तेरहवीं लोकसभा में 297 और चौदहवीं लोकसभा में 248 विधेयक पास किए गए थे. दूसरी तरफ़ इस लोकसभा में 40 विधेयक लेप्स हो गए. इनमें मेट्रो रेल एमेंडमेंट बिल-2008, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल-2009, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एमेंडमेंट बिल-2008, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना विधेयक- 2007, लघु वित्तीयकरण विधेयक, न्यायिक सुधार संबंधी विधेयक जैसे अहम विधेयक शामिल हैं.

महिला आरक्षण बिल की कहानी तो बेहद अफ़सोसनाक बन गई है. वह भी ऐसी लोकसभा में, जहां सत्तारूढ़ यूपीए सरकार की अध्यक्ष एक महिला हैं, लोकसभा की अध्यक्ष एक महिला हैं और विपक्ष की नेता भी महिला हैं. ऐसे में महिलाओं के लिए अहम माने जाने वाले इस विधेयक का पारित न हो पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. जहां तक लंबित विधेयकों का सवाल है, इस लोकसभा से 128 लंबित बिल अगली लोकसभा को सौगात में मिलेंगे. हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि नई लोकसभा में इनकी सुध लेने में माननीय सांसद रुचि दिखाते हैं या नहीं. ■

arsingh@chauthiduniya.com

सत्ता और विपक्ष दोनों ज़िम्मेदार

इसमें कोई दो राय नहीं कि पंद्रहवीं लोकसभा में न्यूनतम कामकाज हुआ, लेकिन इसके लिए किसी एक पक्ष को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. सत्तारूढ़ यूपीए विधेयक पेश करने के बावजूद, उन्हें पारित कराने में विफल रहा, क्योंकि विपक्ष संसद चलने देने के लिए ही तैयार नहीं था. विपक्षी पार्टियों ने सदन की कार्यवाही के समय काफी हंगामा किया, क्योंकि यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई एवं अन्य मुद्दों को उभारने का यही एक बेहतर तरीका था. पक्ष और विपक्ष दोनों इस स्थिति में थे कि वे हंगामे को किसी अवरोध की दृष्टि से नहीं देख रहे थे. यह संसदीय कार्यवाही का सामान्य हिस्सा बन गया था. जैसे हर दिन की कार्यवाही पहले से ही तय थी. हंगामा होगा और कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हो जाएगी. फिर हंगामा होगा और कार्यवाही 2 बजे तक टल जाएगी और अंतिम बार हंगामा होने पर पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही निलंबित कर दी जाएगी. राजनीतिक दलों ने इसे एक परिपाटी बना दिया, जिस वजह से संसदीय परंपरा तार-तार होती रही और जनता चुपचाप अपने जनप्रतिनिधियों की नकारात्मक भूमिका देखती रही. इसी बहाने यूपीए सरकार को भी अपनी नाकामियां छिपाने का एक बेहतरीन मौक़ा मिल गया. संसद में हो रहे हंगामे को देखकर कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि यह सब कुछ पक्ष और विपक्ष की मिलीभगत से हो रहा है.

पंद्रहवीं लोकसभा में हुए हंगामे को इतिश्री मान लेना जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में संसद सदस्यों का आचरण काफी बदला है. उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनकी हरकतों से संसद की मर्यादा और जनता की उम्मीदें टूटने लगी हैं. ऐसे में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगली लोकसभा भी पंद्रहवीं लोकसभा के ही नक्शे क़दम पर चलेगी. ■

जिसे भुलाया नहीं जा सकता

तमाम खामियों के बावजूद पंद्रहवीं लोकसभा में कुछ अच्छे काम ज़रूर हुए. समाजसेवी अन्ना हजारे को जिन सांसदों ने पानी पी-पीकर कोसा, उन्हें मिले अपार जन-समर्थन को अनदेखा करना सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के लिए संभव नहीं हो सका. साझा हितों की सुरक्षा के लिए उन्होंने लोकपाल विधेयक पास करा लिया. दिल्ली में निर्भया के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद एक कठोर क़ानून बनाया गया. तमाम विरोध के बावजूद बहु-प्रतीक्षित तेलंगाना विधेयक पास कराया गया. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक, शिक्षा का अधिकार क़ानून भी इसी लोकसभा में पारित हुआ. बहरहाल, मोटे तौर पर यह लोकसभा हमारे सांसदों के अमर्यादित आचरण के लिए जानी जाएगी. जिस संसद में कभी डॉ. राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, राजनारायण, लाडली मोहन निगम जैसे सांसद अपने व्यवहार और कार्य से लोकतंत्र की प्रतीक संसद का मान बढ़ाया करते थे, अब वैसी बात संसद में देखने को नहीं मिलती. संसद की मर्यादा कैसे क़ायम रहे और सांसदों के व्यवहारों में कैसे सुधार हो, इसे लेकर गंभीर विमर्श करने की ज़रूरत है. हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि लोकतंत्र सिर्फ़ चुनावी राजनीति से ही मजबूत नहीं होता.

फोटो-सुनील मल्होत्रा

संसद के एक सत्र के आयोजन में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. इसके एक–एक मिनट की क़ीमत लाखों रुपये होती है. ऐसे में अगर विपक्ष सदन की कार्यवाही न चलने दे, सदन की कार्यवाही बाधित करे, सदन से वाकआउट करे, तो आख़िर नुकसान किसका होता है? जाहिर है, पैसा जनता का बर्बाद होता है.

15वीं लोकसभा में विपक्ष

सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना जिनका मकसद था

शशि शेखर

संसदीय लोकतंत्र में नेता विपक्ष को पीएम इन वेटिंग कहा जाता है यानी विपक्ष की भूमिका को भी सरकार से कमतर नहीं माना गया है. सरकार के कामों में विपक्ष से रचनात्मक सहयोग एवं समर्थन की अपेक्षा की जाती है. संसद सुचारू रूप से काम करे, इसकी ज़िम्मेदारी जितनी सरकार की होती है, उतनी ही विपक्ष की भी. सही मायनों में संसद के भीतर जनता की आवाज़ उठाने का काम भी विपक्ष का ही होता है. इस हिसाब से अगर देखें, तो 15वीं लोकसभा में विपक्ष जनता की आवाज़ और आकांक्षा को संसद के भीतर उठाने में नाकाम रहा. लोकपाल का मुद्दा हो या महंगाई का, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका न तो रचनात्मक रही और न ही सकारात्मक विरोध वाली. 2जी और कोल ब्लॉक आवंटन मसले पर शोर–शराबे और सदन न चलने देने के अलावा भाजपा ने कुछ भी नहीं किया.

2010 में 2जी मामले पर जेपीसी के गठन के लिए विपक्ष ने क़रीब–क़रीब पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान काम नहीं होने दिया. यह सही है कि विपक्ष के दबाव का ही नतीजा था कि 2जी मामले में आगे कुछ कार्रवाई भी हुई, जीपीसी भी बनी, लेकिन यह पूरा सत्र, जिसमें जनता से जुड़े कई और विधेयकों पर चर्चा हो सकती थी, विधेयक पास हो सकते थे, विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया. 15वीं लोकसभा को इसलिए भी याद रखा जाएगा कि ऐसे कई अहम मौक़े आए, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष जन भावनाओं के विपरीत जाकर एक साथ खड़ा हो गया. 2011 में लोकपाल के मसले पर सदन ने सेंस ऑफ हाउस जारी करके अन्ना हजारे का अनशन तुड़वाया, लेकिन जब उस सेंस ऑफ हाउस को लागू करने की बारी आई, तब भाजपा समेत तमाम विपक्ष सरकार के पाले में खड़ा नज़र आया. 2012 में कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर विपक्ष ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के इस्तीफ़े की मांग करते हुए मॉनसून सत्र में कोई काम नहीं होने दिया.

इसी तरह 2014 में संसद के अंतिम सत्र में तेलंगाना बिल पास करने के लिए सरकार ने जो हथकंडे अपनाए, उनका विरोध विपक्ष के नाते भाजपा नहीं कर पाई, बल्कि उसे सरकार से अधिक चिंता इस बिल को पास कराने की थी, जबकि इसके लिए असंसदीय रास्ता भी अपनाया गया. 16 सांसदों को निलंबित करने के बाद भी जब सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाई, तो बंद दरवाजे के भीतर, टीवी प्रसारण बंद करके तेलंगाना बिल पास किया गया. सवाल यह है कि ऐसे मौक़े पर एक सशक्त विपक्ष को क्या करना चाहिए था? ऐसे मुद्दों पर सरकार का सहयोग किया जाना चाहिए था या विरोध? भाजपा ने बजाय इस असंसदीय एवं अलोकतांत्रिक तरीके का विरोध करने के, सरकार के साथ हाथ मिला लिया. वाड्रा मामले पर जब भाजपा ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो खुद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग गए. ऐसे में उसे अपने क़दम पीछे खींचने पड़े.

2010 में 2जी मामले पर जेपीसी के गठन के लिए विपक्ष ने क़रीब-क़रीब पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान काम नहीं होने दिया. यह सही है कि विपक्ष के दबाव का ही नतीजा था कि 2जी मामले में आगे कुछ कार्रवाई भी हुई, जीपीसी भी बनी, लेकिन यह पूरा सत्र, जिसमें जनता से जुड़े कई और विधेयकों पर चर्चा हो सकती थी, विधेयक पास हो सकते थे, विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया. 15वीं लोकसभा को इसलिए भी याद रखा जाएगा कि ऐसे कई अहम मौक़े आए, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष जन भावनाओं के विपरीत जाकर एक साथ खड़ा हो गया.

भाजपा के अलावा, वामपंथी पार्टियां भी एक सशक्त विपक्ष का रोल निभाने में नाकामयाब रहीं. महंगाई और नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर शायद ही कभी ऐसा मौक़ा आया, जब वामपंथियों ने संसद के भीतर या बाहर सड़क पर कभी कड़ा रुख दिखाया हो. इसके कुछ सदस्यों (गुरुदास दासगुप्ता) को छोड़कर किसी ने भी सदन के भीतर किसी भी मसले पर जोरदार आवाज़ नहीं उठाई. गुरुदास दासगुप्ता ने ज़रूर कामगार यूनियन और गैस प्राइसिंग पर संसद के भीतर कई बार जोरदार बहस की, लेकिन विपक्ष एवं खुद अपनी पार्टी की ओर से मजबूत समर्थन न मिलने के कारण वह कुछ खास नहीं कर पाए. 2009 के शीतकालीन सत्र में सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी ने लोकसभा एवं राजग के हिस्से के रूप में जद (यू) सांसद अली अनवर अंसारी ने राज्यसभा के भीतर रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट (अल्पसंख्यक आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट, जिसे सबसे पहले चौथी दुनिया ने प्रकाशित कर सार्वजनिक किया था) को पेश करने के लिए ज़रूर आवाज़ उठाई. लोकसभा में मुलायम सिंह के नेतृत्व में सपा सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, तब कहीं जाकर सालों से पड़ी यह रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गयी. लेकिन, इसके बाद इस रिपोर्ट का क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम. खुद समाजवादी पार्टी ने भी कभी इस रिपोर्ट पर बहस कराने के लिए संसद के भीतर या बाहर कुछ नहीं किया.

बहरहाल, संसद के एक सत्र के आयोजन में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. इसके एक–एक मिनट की क़ीमत लाखों रुपये होती है. ऐसे में अगर विपक्ष सदन की कार्यवाही न चलने दे, सदन की कार्यवाही बाधित करे, सदन से वाकआउट करे, तो आख़िर नुकसान किसका होता है? जाहिर है, पैसा जनता का बर्बाद होता है. और अगर विपक्ष का अर्थ यही सब रहा, तो अगले कुछ सालों में इस देश का विपक्ष खुद इस देश की जनता होगी. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

15वीं लोकसभा और पूर्वोत्तर

उपेक्षा का सिलसिला जारी है

एस. बिजेन सिंह

पूर्वोत्तर के लोग सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी एवं रोज़गार के मामले में आज भी सौ साल पीछे हैं. गांवों में 24 घंटों में दो घंटे बिजली, पीने का अच्छा पानी नहीं. बारिश में पोखर का जमा हुआ पानी पीना. स्कूलों में अध्यापक नहीं. उच्च शिक्षा पाने के लिए पलायन की मजबूरी, क्योंकि यहां के राज्यों में अच्छे विश्वविद्यालय नहीं हैं. पूर्वोत्तर इतने दुर्गम पहाड़ों से भरा है कि आने–जाने का मार्ग नहीं है. बीमार होने पर लोग सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते. ऐसी स्थिति में, यह देखना काफी ज़रूरी है कि यहां के सांसदों ने संसद के भीतर क्या किया? जनसमस्याओं के समाधान के लिए क्या किया? उनकी आवाज़ ने सरकार का ध्यान यहां की ओर खींचा या नहीं या फिर वे केवल कोरम पूरा करने के लिए संसद में बैठे रहे?

15वीं लोकसभा में नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल जैसे कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए. कई बिल पेंडिंग भी हैं. पूर्वोत्तर के लिए मिजोरम यूनिवर्सिटी एमेंडमेंट बिल 2007, द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज (रिऑर्गेनाइजेशन) एमेंडमेंट बिल 2011 आदि महत्वपूर्ण बिल पास हुए और द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (एमेंडमेंट) बिल 2013 पेंडिंग रहा. पूर्वोत्तर के कुल 25 सांसद हैं, जिन्होंने संसद के भीतर पूर्वोत्तर की मूलभूत समस्याओं पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए. अपने क्षेत्र की आवाज़ बुलंद की और दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों पर हुए अत्याचार का एक स्वर से विरोध किया. हाल में दिल्ली में अरुणाचल के छात्र नीडो तानिया की हत्या पर अरुणाचल प्रदेश (पूरब) के कांग्रेसी सांसद निनोंग इरिंग ने संसद में आवाज़ उठाई. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में गैस आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने की मांग करते हुए कहा कि इंडस्ट्रियल जोन में भी गैस पहुंचाने के लिए पाइप लाइन बिछाई जाए. पूर्वोत्तर भारत में उल्फा जैसे संगठनों ने कई बार पाइप लाइन को क्षति पहुंचाई है.

त्रिपुरा (पश्चिम) के सीपीआई (एम) के सांसद खगेन दास ने रियांग शरणार्थियों के पुनर्वास, त्रिपुरा में एक स्वतंत्र हाईकोर्ट की स्थापना, रोजमर्रा की ज़रूरत की वस्तुओं की क़ीमतों में वृद्धि, रेल, बिजली, पानी एवं परिवहन संबंधी मुद्दे संसद में उठाए. सबसे अहम सवाल उन्होंने संसद में किया कि 2005 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया हुआ नेशनल हाईवे–44 अभी तक अधूरा पड़ा है. यह त्रिपुरा के लिए लाइफलाइन है, लेकिन 10 सालों से अभी तक काम चल ही रहा है. मेघालय (तुरा) से एनसीपी की युवा सांसद अगाथा संगमा जब लोकसभा में पहली बार चुनकर आईं, तब उन्होंने

लोगों को खूब आकर्षित किया. केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री भी बनीं. अपने कार्यकाल में उन्होंने पूर्वोत्तर के ग्रामीण विकास को लेकर काम किया, लेकिन कई काम अधूरे रह गए. अगाथा ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफसपा) को लेकर सवाल उठाया था कि यह क़ानून पूर्वोत्तर में लागू न हो. उन्होंने यह एक्ट हटाने के लिए कई वर्षों से भूख हड़ताल कर रहीं इरोम शर्मिला से मुलाकात कर उनकी मांग का समर्थन किया.

मणिपुर (इनर) के कांग्रेसी सांसद थोकचोम मैन्य ने भी अफसपा जैसे सवाल संसद में उठाए, भले ही उन्हें मीडिया के सामने तीखी आलोचना झेलनी पड़ी. ग़ौरतलब है कि जब नेशनल हाईवे–39 दो महीने से ज़्यादा समय तक बंद रहा, तब लोगों का जीना दुश्वार हो गया था. एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, दवाइयों एवं खाद्य पदार्थों के दाम दोगुने हो गए थे. उन्होंने फर्जी मुठभेड़, आतंकी संगठनों, एनएससीएन (आईएम) प्रमुख मुइवा की जन्मस्थल वापसी, नेशनल हाईवे (इंफाल–जीरी), ऑटोनोमस डिस्ट्रिक काउंसिल आदि मामलों पर आवाज़ बुलंद की. लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार और पूर्वोत्तर से जुड़ने वाला रोडमैप तैयार कराने की बात कही. इंफाल तक रेल पहुंचने से रोज़गार बढ़ेगा, इसलिए वहां जल्द से जल्द रेल पहुंचाने की मांग की. नगालैंड के नगालैंड पीपुल्स फ्रंट के सांसद सीएम चांग नगा राजनीतिज्ञ हैं. वह नगाओं की समस्याएं संसद में उठाते रहे.

असम से पूर्वोत्तर के सबसे ज़्यादा यानी कुल 14 लोकसभा सदस्य हैं, जिनमें डिब्रूगढ़ से इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) के पवन सिंह घटोवार प्रमुख हैं. वह डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री हैं. उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल संसद में उठाए. उन्होंने असम में बाढ़ की स्थिति में लोगों की सहायता की मांग उठाते हुए संसद में बहस भी की. स्वतंत्रता सेनानियों, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, असम चाय अनुसंधान, झूम कल्टीवेशन एवं पूर्वोत्तर के नेशनल हाईवे को 4 लेन करने संबंधी मुद्दे उन्होंने संसद में उठाए. पूर्वोत्तर के सांसदों ने सदन के भीतर स्थानीय समस्याएं उठाने का काम ज़रूर किया, लेकिन उनकी आवाज़ पर 15वीं लोकसभा ने कितना ध्यान दिया, सरकार उनकी मांगों के प्रति कितनी गंभीर रही, यह तब पता चलता है, जब हम पूर्वोत्तर की लगातार बदतर हो रही स्थिति को देखते हैं. प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी रस्मी तौर पर पूर्वोत्तर की यात्राएं करते रहे, लेकिन उनकी घोषणाओं एवं आश्वासनों पर अमल नहीं हुआ. ज़ाहिर है, पूर्वोत्तर के सांसदों को अब पार्टी लाइन से ऊपर उठकर न सिर्फ़ संसद के भीतर आवाज़ उठानी होगी, बल्कि अपनी मांगें पूरी कराने के लिए उन्हें सड़क पर आने से भी परहेज नहीं करना चाहिए. ■

sbijensngh@gmail.com

राज्य	सांसद	पार्टी	संसद में उपस्थिति (प्रतिशत)
मणिपुर	थांगसो बाइते	इंडियन नेशनल कांग्रेस	98%
मणिपुर	थोकचोम मैन्य	इंडियन नेशनल कांग्रेस	99%
मेघालय	अगाथा संगमा	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	49%
मेघालय	विंसेंट एच पाला	इंडियन नेशनल कांग्रेस	83%
त्रिपुरा	बाजु बान रियान	माकपा	85%
त्रिपुरा	खगेंद दास	माकपा	74%
मिजोरम	सीएम रौला	इंडियन नेशनल कांग्रेस	95%
नगालैंड	सीएम चांग	नगालैंड पीपुल्स फ्रंट	78%
सिक्किम	प्रेमदास राय	सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट	87%
अरुणाचल प्रदेश	निनोंग इरिंग	इंडियन नेशनल कांग्रेस	88%
अरुणाचल प्रदेश	टकम संजय	इंडियन नेशनल कांग्रेस	63%
असम	बद्रूडिन अजमल	असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	48%
असम	विजोय कृष्ण हनडिक	इंडियन नेशनल कांग्रेस	92%
असम	विजोया चक्रवर्ती	भारतीय जनता पार्टी	84%
असम	विरेन सिंह इंगटी	इंडियन नेशनल कांग्रेस	95%
असम	दीप गोगोई	इंडियन नेशनल कांग्रेस	79%
असम	इस्माइल हुसैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस	94%
असम	जोसेप टोप्पो	असम गण परिषद	76%
असम	कार्बिद्र पुरकायस्थ	भारतीय जनता पार्टी	89%
असम	ललित मोहन सुक्लवैद्य	इंडियन नेशनल कांग्रेस	95%
असम	पवन सिंह घटोवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस	91%
असम	राजेन गोहैन	भारतीय जनता पार्टी	54%
असम	रामेन डेका	भारतीय जनता पार्टी	84%
असम	रानी नराह	इंडियन नेशनल कांग्रेस	83%
असम	संसुमा खंगर बासुमतारी	बोडोलैंड पीपुल फ्रंट	63%

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

आख़िरकार, चुनाव पांच सालों के लिए होते हैं और जनता स्थायित्व चाहती है. जनता चाहती है कि क़ानून और व्यवस्था की समस्या न हो. जनता तेज विकास चाहती है. राजनीतिक दल रामराज्य लाने की बात कर रहे हैं, फिर भी पिछले साठ सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ. वे जनता को केवल बेवक़ूफ बना रहे हैं. दो या तीन सालों में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, तब तक कि, जब तक एक अलग तरह की आर्थिक नीति नहीं अपनाई जाती. दुर्भाग्य से, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. ये दोनों प्रो-अमेरिकन, प्रो-रिच पॉलिसी अपना रहे हैं, जो जनता के लिए ठीक नहीं है.

कांग्रेस को रणनीति बदलनी चाहिए

चुनाव प्रक्रिया वास्तव में शुरू हो चुकी है. हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी समय और तिथि की घोषणा नहीं की है. आचार संहिता लागू नहीं हुई है, लेकिन इस सबसे पहले ही राजनीतिक दल चुनाव के मोड में चले गए हैं. भाजपा, राकांपा आदि ने तो अपने लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है. इधर राम विलास पासवान ने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है. ध्यान देने की बात यह है कि राम विलास पासवान एनडीए से गुजरात दंगों की वजह से ही अलग हुए थे. आज उन्हें महसूस हो रहा है कि हालात ऐसे हो गए हैं, जिससे मोदी के साथ हाथ मिलाया जा सकता है. 2002 में जिस बात (दंगा) की अनदेखी नहीं की थी, आज उसकी अनदेखी कर सकते हैं. यही राजनीति है. बिहार में स्थिति यह है कि राम विलास पासवान को शायद यह महसूस हुआ कि भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए यही सबसे अच्छा मौक़ा है और इसीलिए उन्होंने सभी विकल्पों के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई.

आजकल राजनीति में नीतियों और सिद्धांतों की बात करना एक अपराध की तरह है. यह केवल चुनावी नीति है और सिद्धांतों, विचारधारा या राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. यहां हर कोई लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने और उसी के अनुसार कार्य करने के लिए कोशिश कर रहा है. अधिकतम सीटें प्राप्त करने के लिए यह एक सरल गणित है. कांग्रेस पार्टी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है. प्रधानमंत्री पद के लिए जैसे ही भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा की, यह तय हो गया कि प्रतियोगिता मोदी बनाम राहुल है. कांग्रेस भी इससे सहमत हुई, लेकिन उसने कई कारणों और व्यवहारिक परेशानियों की वजह से अपने प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी के नाम की घोषणा नहीं की. उसे यह महसूस हुआ कि इससे झटका लग सकता है.

कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है. यह देश भर में मौजूद है. सचमुच देश भर में. और, इतनी मौजूदगी भाजपा के पास भी नहीं है. कांग्रेस के पास देश के हर हिस्से में क्षेत्रीय नेता हैं, जो कांग्रेस के सिद्धांतों एवं विचारधारा के मुताबिक अच्छी तरह से अभियान दर अभियान चला सकते हैं. दुर्भाग्य से, लोकप्रियता पाने या फिर किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न देखने के लिए ये जो कर रहे हैं, उससे पार्टी और राहुल गांधी, दोनों को नुक़सान हो रहा है. जो मौक़ा पार्टी के पास खुद को प्रोजेक्ट करने का था, उसे पार्टी खो चुकी है, क्योंकि पार्टी के मुख्य प्रचारक के लिए यह काम नया है और वह प्रेस को संबोधित करने में असफल रहे हैं. राहुल गांधी का अर्णब गोस्वामी के साथ इंटर्व्यू, जिसे मैं अधिक बुरा नहीं समझता,

कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है. यह देश भर में मौजूद है. सचमुच देश भर में. और, इतनी मौजूदगी भाजपा के पास भी नहीं है. कांग्रेस के पास देश के हर हिस्से में क्षेत्रीय नेता हैं, जो कांग्रेस के सिद्धांतों एवं विचारधारा के मुताबिक अच्छी तरह से अभियान दर अभियान चला सकते हैं. दुर्भाग्य से, लोकप्रियता पाने या फिर किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न देखने के लिए ये जो कर रहे हैं, उससे पार्टी और राहुल गांधी, दोनों को नुक़सान हो रहा है. जो मौक़ा पार्टी के पास खुद को प्रोजेक्ट करने का था, उसे पार्टी खो चुकी है, क्योंकि पार्टी के मुख्य प्रचारक के लिए यह काम नया है और वह प्रेस को संबोधित करने में असफल रहे हैं.

जनता के बीच कुछ खास संदेश देने में नाकाम रहा.

अब कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव लाना चाहिए और अपने कुछ बेहतरीन नेताओं को देश के अलग-अलग हिस्सों में उतारना चाहिए. वे न सिर्फ़ अपने क्षेत्रों में मजबूत प्रचार करें, बल्कि पूरे क्षेत्र में यह काम करें. उदाहरण के तौर पर दिग्विजय सिंह हिंदीभाषी क्षेत्रों में एक मजबूत प्रवक्ता साबित हो सकते हैं. चिदंबरम दक्षिण में, एंटनी केरल में और इसी तरह अन्य नेता. कांग्रेस अब तक प्रधानमंत्री के क़रीबी लोगों के सहारे सरकार चला रही थी, लेकिन इससे चुनाव में फ़ायदा नहीं होने वाला है. कांग्रेस की दूसरी सबसे बड़ी परेशानी हैं कैग द्वारा उद्घाटित किए गए घपले-घोटाले. अगर कांग्रेस के पास मजबूत प्रवक्ता हों, तो वे इस क्षति को कम कर सकते हैं. वे जनता को यह बता सकते हैं कि कैग के आंकड़े सही नहीं हैं या सरकार ने इस सबके लिए कड़े क़दम उठाए. सुप्रीम कोर्ट में मामला है और आगे से ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा.

आख़िरकार, चुनाव पांच सालों के लिए होते हैं और जनता स्थायित्व चाहती है. जनता चाहती है कि क़ानून और व्यवस्था की समस्या न हो. जनता तेज विकास चाहती है. राजनीतिक दल रामराज्य लाने की बात कर रहे हैं, फिर भी पिछले साठ सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ. वे जनता को केवल बेवक़ूफ बना रहे हैं. दो या तीन सालों में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, तब तक कि, जब तक एक अलग तरह की आर्थिक नीति नहीं अपनाई जाती. दुर्भाग्य से, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. ये दोनों प्रो-अमेरिकन, प्रो-रिच पॉलिसी अपना रहे हैं, जो जनता के लिए ठीक नहीं है.

नई-नई आई आम आदमी पार्टी अभी भी अपनी विचारधारा सामने लाने में संकोच कर रही है. एक समय वे बिजली की उच्च दर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, फिर एक बड़े औद्योगिक घराने द्वारा गैस प्राइसिंग का मामला उठाते हैं और अंत में सीआईआई की मीटिंग में बोलते हैं कि वे पूंजीवाद के ख़िलाफ़ नहीं हैं. मेरे हिसाब से वे अभी भी भ्रमित हैं. वे बीच का रास्ता तलाश रहे हैं. खैर, जो भी उनकी विचारधारा हो, उसे तत्काल सार्वजनिक करना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है.

अभी तक हमारे पास एक बिखरी हुई लोकसभा थी. कोई भी ऐसा दल आगे नहीं आया, जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो. अभी मोदी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अन्य दूसरी पार्टियों के लिए उम्मीद ख़त्म हो गई हो. ये सभी पूरे देश में एक-एक सीट के लिए चुनाव लड़ेंगी. नतीजतन, एक बार फिर हमारे सामने बिखरी हुई लोकसभा होगी. चुनाव के बाद का पूरा माहौल दिलचस्प होने जा रहा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि हम किस तरह की सरकार बनाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

अधिकारों से वंचित महिलाएं

गौहर आसिफ

हर साल आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार दिलाने के साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है. इसमें कोई शक नहीं कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन 21वीं सदी के इस दौर में जहां एक तरफ़ महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, वहीं लाखों महिलाएं आज भी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व की महिलाएं जाति-पांत, रंगभेद, वेशभूषा एवं भाषा से परे एकजुट होकर मनाती हैं. महिला दिवस महिलाओं को अपनी दबी-कुचली आवाज़ अपने अधिकारों के प्रति बुलंद करने की प्रेरणा देता है.

हमारे देश में महिलाओं के साथ भेदभाव की कहानी परिवार से ही शुरू हो जाती है. कई बार तो लड़की को दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझ कर मां के गर्भ में ख़त्म कर दिया जाता है. अगर लड़की परिवार में जन्म ले भी लेती है, तो लड़कों के मुकाबले उसे हर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है. और तो और, लड़कों के मुकाबले लड़कियों को शिक्षा देने में भी कमी की जाती है. इसके पीछे हमारे पुरुष प्रधान समाज की सोच यह होती है कि लड़की पढ़-लिखकर क्या करेगी, उसे तो शादी करके अपने घर जाना है? घर का सारा काम करने के बावजूद आज भी ज़्यादातर परिवारों में महिलाएं पुरुषों के बाद ही भोजन करती हैं.

महिलाओं के साथ भेदभाव की यह दास्तां यहीं नहीं थमती. आज़ादी के 66 वर्षों के बाद भी हम महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली घरेलू हिंसा पर पूरी तरह लगाम नहीं लगा सके. बाल विवाह और दहेज प्रथा की बेड़ियां आज भी हमारे समाज को जकड़े हुए हैं. बलात्कार के मामलों में लगातार इज़ाफा हो रहा है. शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा कि महिलाओं के उत्पीड़न और उनके साथ अत्याचार की दास्तां अख़बारों की ख़बर न बनती हो. महिलाओं के साथ सामाजिक दुर्व्यवहार के बहुत से मामले हैं, जिन्हें अनदेखा करना आम बात हो गई है. कुल मिलाकर हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति खराब है. आज महिलाओं को आरक्षण से ज़्यादा ज़रूरत है उचित सुविधाओं की, उनकी प्रतिभा एवं महत्वाकांक्षा के सम्मान की.

सबसे बढ़कर तो यह कि अगर नारी ही नारी को सम्मान देने लगे, तो समस्या काफी हद तक कम हो सकती है. महिलाएं भी अपनी उस सोच को बदलें कि वे पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा हैं. वे जब तक अपनी यह सोच नहीं बदलेंगी, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगी. सवाल यह है कि जब महिलाओं की दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का भारत में क्या महत्व है? जब तक पुरुष वर्ग महिलाओं को सम्मान से नहीं देखता, तब तक महिलाओं की स्थिति नहीं बदलेगी. पुरुषों को महिलाओं के प्रति अपने नज़रिये में बदलाव लाना होगा. जब तक पुरुषों का नज़रिया नहीं बदलेगा, तब तक महिलाएं अपने हक़ से वंचित रहेंगी. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पुरुषों को महिलाओं के प्रति अपना नज़रिया बदलने की हिदायत भी देता है. ■

(चरखा)

feedback@chauthiduniya.com

हमारे देश में महिलाओं के साथ भेदभाव की कहानी परिवार से ही शुरू हो जाती है. कई बार तो लड़की को दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझ कर मां के गर्भ में ख़त्म कर दिया जाता है. अगर लड़की परिवार में जन्म ले भी लेती है, तो लड़कों के मुकाबले उसे हर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है. और तो और, लड़कों के मुकाबले लड़कियों को शिक्षा देने में भी कमी की जाती है. इसके पीछे हमारे पुरुष प्रधान समाज की सोच यह होती है कि लड़की पढ़-लिखकर क्या करेगी, उसे तो शादी करके अपने घर जाना है?

पाठकों की दुनिया

संवेदनहीन राजनीतिक दल

24 फरवरी-2 मार्च का अंक मिला. कवर स्टोरी-अन्ना का हाथ, ममता के साथ अच्छी लगी. अन्ना ने गांव और ग़रीबों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, सराहनीय हैं, लेकिन दु:ख की बात यह है कि ममता बनर्जी को छोड़कर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया. राजनीतिक दलों के आचरण से लगता है कि वे बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं और गांवों को विकसित नहीं करना चाहते. अन्ना ने सही कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ की खातिर संवेदनहीन हो चुकी हैं. उन्हें ग़रीबों से कोई लेना-देना नहीं है. ग़रीब उनके लिए महज एक वोट बनकर रह गया है. राजनीतिक दलों के संवेदनहीनता का ही नतीजा है कि देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और कुव्यवस्था का बोलबाला है.

–अनुज सिंह, वाराणसी, उत्तर प्रदेश.

कुव्यवस्था के नायक

अपनी बात को साबित न कर पाए मनमोहन (अंक: 24 फरवरी-2 मार्च) शीर्षक तले प्रकाशित लेख पढ़ा. नीरज सिंह ने अपने लेख में विषय से संबंधित हर बिंदु पर बख़ूबी रोशनी डाली. यह सच है कि मनमोहन सिंह ने 1991 में बतौर वित्त मंत्री कहा था कि आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय होगा, भारत अब जाग चुका है, हमें बढ़ना होगा, जीतना होगा. लेकिन, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो उसके उलट काम हुआ. नतीजा यह हुआ कि देश महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और कुव्यवस्था से त्रस्त है.

–राकेश कुशवाहा, दरभंगा, बिहार.

परंपराएं तोड़ते सांसद

24 फरवरी-2 मार्च अंक में अपने संपादकीय में संतोष भारतीय ने जो लिखा है, उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि सांसद अपने स्वार्थों के लिए लोकतंत्र की बलि दे रहे हैं. उन्होंने सही लिखा कि कुछ राजनीतिक दल धर्म एवं संप्रदाय का नाम लेकर लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं. संसद में पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का आचरण एक तरह का नज़र आता है. इस बार शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष के सांसद ही सारे नियमों को तार-तार करते नज़र आए. तेलंगाना पर तो कांग्रेस सांसदों ने हद कर दी. जिस दिन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने तेलंगाना विधेयक लोकसभा में पेश किया, सदन के अंदर मिर्च स्प्रे किया गया और मारपीट तक हुई. यह निस्संदेह शर्मनाक है.

–अजय मौर्य, एटा, उत्तर प्रदेश.

जैसा देश, वैसा वेश

आजकल भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार के दौरान जहां जाते हैं, वहीं रंग में रंग जाते हैं. अभी हाल में उन्होंने कई जगह चुनावी रैलियों में भाग लिया, वह भी स्थानीय वेशभूषा धारण करके. वह असम गए, तो वहां की प्रसिद्ध टोपी पहन ली. पंजाब गए, तो पगड़ी पहन ली. अब देखना है कि उनका यह अंदाज क्या गुल खिलाता है.

–लवकुश यादव, झांसी, उत्तर प्रदेश.

यह कैसी राजनीति है

राजनीतिक स्वार्थों के लिए हत्याओं और आतंकी घटनाओं में शामिल लोगों को भी रिहा किया जा रहा है. जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर हुआ. सुप्रीमकोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी. यह फ़ैसला आए कुछ समय बीता था, तभी तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उन्हें रिहा करने का निर्णय ले लिया. केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उनकी रिहाई रुक पाई. जब एक प्रधानमंत्री के हत्यारों को राजनीतिक फ़ायदे के लिए रिहा किया जा सकता है, तो आम आदमी को न्याय मिलने की आशा भला कैसे की जा सकती है.

–गौरव सिंह, ग्वालियर, मध्य प्रदेश.

फ़ैसले की घड़ी

चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को रिझाने लगती हैं. वे उन्हें आरक्षण देने का वादा करती हैं, सुरक्षा देने का वादा करती हैं, जो केवल वादा बनकर रह जाता है. राजनीतिक पार्टियां अपने वादों पर अमल नहीं करतीं. उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है और केंद्र में कांग्रेस की, लेकिन दोनों ही दंगा रोकने में नाकाम रहीं. दंगा पीड़ितों को न्याय तो दूर, छत तक नसीब नहीं हो सकी. अब भाजपा भी इस दौड़ में शामिल हो गई है. राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, तो हम सिर झुका कर माफी मांगने को तैयार हैं. अब मुसलमानों को खुद अपने विवेक से फ़ैसला करना चाहिए कि कौन उनका असली रहनुमा है और कौन उन्हें महज वोट बैंक समझता है.

–फिरोज, समस्तीपुर, बिहार.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

एक नई आर्थिक नीति इस देश की ज़रूरत है

नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लोग, जिन्हें किसी भी क़ीमत पर लोकसभा में जाना है या जो समझते हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी, वे लोग मोदी के साथ चले गए हैं. राम विलास पासवान एवं जगदंबिका पाल दो अलग-अलग पार्टियों के सांसद हैं. राम विलास पासवान अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और लालू यादव ने उन्हें 2009 के चुनाव में हार जाने पर राज्यसभा में भेजा था. जगदंबिका पाल कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और उन्हें गुस्सा है कि उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया या उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया. दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए. यह अलग बात है कि दोनों देश के अधिकांश लोगों की तरह विचारों को तिलांजलि देकर नरेंद्र मोदी के साथ गए हैं. राम विलास पासवान के बयान सांप्रदायिकता के साथ कहीं मिलते नहीं दिखाई देते. जगदंबिका पाल ने सारी ज़िंदगी सांप्रदायिकता का विरोध किया, लेकिन अब इस चुनाव में उन्हें नरेंद्र मोदी में सांप्रदायिकता नज़र नहीं आती. और हो सकता है कि ये दोनों जल्दी ही यह बयान दें कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक नहीं हैं.

राम विलास पासवान ने तो बड़ी सफाई से सांप्रदायिकता और 2002 का गुजरात दंगा, दोनों को मिला दिया और उन्होंने कहा कि चूंकि अदालत ने नरेंद्र मोदी को सजा नहीं दी है, इसलिए मोदी सांप्रदायिक नहीं हैं. सांप्रदायिक विचारधारा होती है और उस विचारधारा को मानने वाले सांप्रदायिक होते हैं. जो धर्मनिरपेक्ष होते हैं या सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ होते हैं, वह भी विचारधारा ही होती है. पर अब हमारे देश में विचारधारा का कोई मतलब ही नहीं है.

दरअसल, सांप्रदायिकता से भी एक और ख़तरनाक चीज है, वह है नव-उदारवादी बाज़ार व्यवस्था, जिसे 1991 में नरसिम्हाराव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में मनमोहन सिंह ने लागू किया था. मजे की बात यह है कि इस अर्थ व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी भी मानती है और तीसरे सवार अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं. बिना संविधान को बदले संविधान को बदलने की कोशिश करने वाली कांग्रेस का समर्थन भारतीय जनता पार्टी यह कहकर करती है कि कांग्रेस ने उदारवादी बाज़ार व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं किया, वह इसे ठीक से लागू करेगी. अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि सरकार का काम उद्योग या व्यापार चलाना नहीं है, सरकार का काम शासन करना है. उन्होंने यह भी कहा कि नौकरियां सरकार के पास नहीं हैं, नौकरियां तो उद्योगपति दे सकते हैं. हमारे देश में लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना संविधान में की गई है और सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे लोगों को भूख, प्यास, बेरोज़गारी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार से निजात दिलाएंगी, क्योंकि यह लोगों की सरकार है, यह पूंजीपतियों का मैनेजमेंट स्टेबलिसमेंट नहीं है. हिंदुस्तान के लोगों की चुनी हुई सरकार है. और जिस देश में 70 प्रतिशत लोग महंगाई, बेरोज़गारी एवं भ्रष्टाचार से परेशान हैं, जहां विकास नहीं है, जहां विकास जा नहीं रहा है. सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह इन सारी समस्याओं का हल निकालेगी और इसकी ज़िम्मेदारी निभाएगी. लेकिन, अब सरकारें ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही हैं और भारत की जनता को बाज़ार के भरोसे छोड़कर निश्चिंत हो गई हैं. कालाहांडी में मौत से जूझ रहे बच्चे इस देश में चिंता का विषय बनते थे, अब कोई कालाहांडी जैसी जगहों की बात नहीं करता. ग़रीब, आदिवासी, दलित एवं कमजोर वर्ग के लोग, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, के बारे में अब सरकारें चिंता नहीं करतीं, क्योंकि नव-उदारवादी बाज़ार व्यवस्था इन्हें अपने दायरे में मानती ही नहीं है.

नव-उदारवादी बाज़ार व्यवस्था सौ प्रतिशत लोगों की ज़िंदगी में कैसे विकास की रोशनी आए, इसके बारे में योजना नहीं बनाती, बल्कि किस तरह से 7 से 10 प्रतिशत लोगों की ज़िंदगी आराम से चले और बाकी सारे लोग उन 7 से 10 प्रतिशत लोगों की ज़िंदगी को आराम से चलाने का पुर्जा बन जाएं, इसके लिए काम करती है. आने वाला चुनाव बहुत समझदारी के साथ इस देश की जनता कैसे लड़े, यह एक करोड़ रुपये का सवाल है. इसे अंग्रेजी में मिलियन डॉलर का सवाल कहते हैं.

आगे आने वाले चुनाव के बाद यह देश दो तरह के रास्तों पर चलने के बारे में सोचेगा. पहला रास्ता भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी, शोषण और विकास से अलगाव की पीड़ा झेलते हुए किसी तरह जीना और जब न जी सको, तो आत्महत्या करके मर जाओ. जैसे आज किसान कर रहे हैं. इस बाज़ार व्यवस्था ने भारतीय कृषि की कमर तोड़ दी है और किसानों को मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया है. अब किसानों की आत्महत्या समाचारपत्रों और टेलीविजन में जगह नहीं पाती. किसानों के लड़के ही सेना में हैं और किसानों के लड़के ही नौकरशाही में हैं, लेकिन वे लड़के इस बाज़ार व्यवस्था की वजह से अपने ही परिवार की दुर्दशा का कारण बन रहे हैं और किसानों के लिए, खेती के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं. किसानों की जमीन छीनी जा रही है, अधिग्रहीत की जा रही है और सस्ते दामों में बिल्डर्स को बेची जा रही है. किसान का उत्पाद लागत के हिसाब से घाटे का सौदा हो गया है. इसके बावजूद देश के 60 से 70 प्रतिशत लोगों के पास खेती के अलावा कोई चारा नहीं है. सरकार खेती को उत्पादक बनाने के बारे में नहीं सोच रही है, इसलिए यह डर पैदा हो गया है कि किसान कहीं पर इतना न निराश हो जाए कि वह भी असंवैधानिक रास्ते अपनाने के बारे में सोचने लगे. और जब तक नहीं सोचेगा, तब तक 2014 के बाद इसी सिस्टम में, जो उसकी दुर्दशा का कारण है, शायद वह जीने के लिए विवश रहेगा.

और दूसरा रास्ता है कि अभी से इसके ख़िलाफ़ लड़ने की कोशिश की जाए. जो लोग नव-उदारवादी आर्थिक नीतियां चाहते हैं, वे समझें कि यह आर्थिक नीति उनके हित में नहीं है, क्योंकि इस आर्थिक नीति ने महंगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोज़गारी बढ़ाई है और यह आर्थिक नीति इन चीजों को आगे बढ़ाएगी ही, क्योंकि इसमें महंगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोज़गारी बढ़ाने के तत्व अंतर्निहित हैं. इसका मतलब है कि जो लोग बदली हुई आर्थिक नीतियों की बात करते हैं, उनका समर्थन करने की बात देश के लोग सोचें. खासकर वे लोग, जो आर्थिक नीतियों को समझते हैं, उन्हें इसके बारे में लोगों को समझाना चाहिए. हमारे देश में जानबूझ कर लोगों को वैचारिक जानकारी से अलग रखा गया है और उन्हें यह कहा गया है कि उनके लिए वैचारिक जानकारी कोई ज़रूरी चीज नहीं है. उन्हें समस्याओं के जाल में उलझा कर, समस्या कैसे हल हो सकती है, उससे अलग कर दिया गया है. इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बहुत सफाई के साथ, वैचारिक तौर पर किस तरह से देश बदल सकता है, इसके बारे में देश के सामान्य लोगों को शामिल किया जाए.

मुझे मालूम है कि यह काम करने वाले लोग भी अब नहीं बचे हैं, लेकिन अगर लोग यह काम नहीं करेंगे, तो उन्हें उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब वे सड़क पर जा रहे हों, तो निराश एवं ग़रीब लोग आएं और दिनदहाड़े उनका सामान छीन लें. यह स्थिति आने में देर सबेर जैसी भाषा का इस्तेमाल अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अब यह स्थिति सामने दिखाई दे रही है. वंचित या विकास के दायरे से बाहर के लोग एक वर्ग को, उसकी वेशभूषा को, रहन-सहन को इस भ्रष्ट व्यवस्था के सिंबल के तौर पर मानने लगे हैं और यह ख़तरा अब दरवाजे पर आ गया है. इसलिए समझदार लोगों को चाहिए कि अर्थव्यवस्था के बदलने की बात और जो बदली हुई अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, उनका स्वागत करने की कोशिश हर हालत में समर्थन के योग्य है. यह करना ज़रूरी है. अगर आप और हम साथ देते हैं, तो हम देश के हित में काम करेंगे.

नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, देश में जीतने का माद्दा रखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, भाषा है, तकनीक है और छलावा है. लेकिन, ये सारे लोग देश के लोगों की समस्याएं हल करने में इसलिए कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि 23 साल, 1991 से लेकर आज तक, यह साबित कर गए हैं कि यह अर्थ नीति, जिसे हम नव-उदारवादी बाज़ार व्यवस्था कहते हैं, देश को न एक रख सकती है, न देश की समस्याएं हल कर सकती है, न देश से महंगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोज़गारी ख़त्म कर सकती है. इन्हें ख़त्म करने के लिए इस आर्थिक नीति का बदलना और बदली हुई आर्थिक नीति लोगों के सामने लाना एक उपाय है, जिसे करने में लोगों को शामिल होना चाहिए. ■

editor@chauthiduniya.com

दरअसल, सांप्रदायिकता से भी एक और ख़तरनाक चीज है, वह है नव-उदारवादी बाज़ार व्यवस्था, जिसे 1991 में नरसिम्हाराव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में मनमोहन सिंह ने लागू किया था. मजे की बात यह है कि इस अर्थ व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी भी मानती है और तीसरे सवार अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं. बिना संविधान को बदले संविधान को बदलने की कोशिश करने वाली कांग्रेस का समर्थन भारतीय जनता पार्टी यह कहकर करती है कि कांग्रेस ने उदारवादी बाज़ार व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं किया, वह इसे ठीक से लागू करेगी.

क्या संसद ज़रूरी है?

मेघनाद देसाई

किसी भी सांसद के लिए अपनी असहमति जताने का सिर्फ़ एक उपाय है कि वह संसद की कार्रवाई में बाधा पहुंचाए. कई बार ऐसा होता है कि सांसद, कई पार्टी के सांसद व्हिप के कारण ही अभद्र व्यवहार करते हैं, क्योंकि यह बात तय है कि अगर बड़ी पार्टियों ने एक बार किसी बिल को पेश कर दिया, तो वह पास हो ही जाएगा. यही कारण था कि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उस समय हंगामा कर दिया था, जब प्रोन्नति में दलितों को आरक्षण दिए जाने वाला बिल पेश किया जाना था. यह भी हो सकता है कि उन्होंने यह उपद्रव किसी सौदेबाजी, चाल के तहत अपनी पार्टी के लिए किया हो या सत्ताधारी पार्टी के लिए. जब सांसदों की पार्टी ही सत्ताधारी पार्टी हो, तो उनके पास उपद्रव ही एकमात्र रास्ता बचता है, जैसा कि आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी सांसदों ने किया.

तेलंगाना बिल को लेकर चल रही बहस के दौरान लोकसभा के सजीव प्रसारण को रोक दिया जाना इस पूरे घटनाक्रम का सबसे कम चौंकाने वाला पहलू है. पृथक तेलंगाना और संयुक्त आंध्र के समर्थक सांसदों का व्यवहार भी चौंकाने वाला नहीं था और न पेपर स्प्रे का छिड़काव. वास्तविकता में यहां पर एक व्यवहार दूसरे व्यवहार की व्याख्या करता है. किसी भी बड़े लोकतंत्र की संसद में बिना किसी अच्छी बहस के, ऐसा बिल नहीं पास हुआ होगा, जिसमें इतनी सारी चीजें दांव पर लगी हों और जिसमें 110 संशोधन प्रस्ताव हों. एक ऐसा बिल, जिस पर कमीशन बैठाने की आवश्यकता पड़ी, लोगों ने आत्महत्याएं कीं, सार्वजनिक संपत्ति का नुक़सान हुआ, कभी पास नहीं हो पाता, अगर एक आम सदन चल रहा होता.

सच तो यह है कि भारत की संसद को ग़ैर-कार्यात्मक इन उपद्रवी सांसदों ने नहीं बनाया, बल्कि उस कार्यकारी शक्ति ने बनाया है, जिसने पूरी शक्ति अपने हाथों में ले रखी है. ये ही कार्यकारी शक्तियां बिजनेस को कंट्रोल करती हैं और विधायिका की प्रक्रिया को भी. जब मामला किसी बिल पर बहस को लेकर आता है, तो सब कुछ ऑफ द फ्लोर होता है और बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच ही तय होता है. इसलिए तेलंगाना बिल जैसे ही आया, संशोधनों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच में ही फ़ैसला गुप्त रूप से हुआ. जो लोकसभा में पेश किया गया, वह पहले से ही तैयार और पकाया गया बिल था और जिसके पास हो जाने की पूर्व तैयारी थी. इसी वजह से संशोधनों पर सिर्फ़ मौखिक वोटिंग ही काफी थी और जिन संशोधनों को नहीं पास किया जा सकता था, उन्हें बिना किसी बहस के दरकिनार कर दिया गया.

आख़िर सिर्फ़ उसी दिन क्यों लोकसभा के सजीव प्रसारण को रोका गया? अगर किसी और दिन भी ऐसा किया जाता, तो कोई ज़्यादा नुक़सान होने वाला नहीं था. संसद अब क़ानून पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं करती. होता यह है कि बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेता संसद के बाहर ही मिलकर आपसी फ़ायदों के आधार पर यह तय कर लेते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं. दरअसल, संसद किसी भी व्यवस्थित बहस के लिए नपुंसक और अप्रासंगिक हो चुकी है.

लेकिन, ऐसी अवस्था हमेशा नहीं रही है. आज़ादी के बाद अपने शुरुआती 24 सालों के दौरान यह ब्रिटिश संसद की तरह ही काम करती थी. उस दौरान संसद में बड़ी बहसें और ऐतिहासिक भाषण हुआ करते थे. भारत की चीन को लेकर नीतियों पर हुई बहसों को सुनिए या अन्नादुरई के 1962 के उस भाषण को सुनिए, जिसमें उन्होंने उत्तर भारतीयों से कहा था कि दक्षिण भारत अलग होने जा रहा है. सदस्य अपनी पार्टी की नीतियों से असहमत भी हो सकते थे, जैसा कि ब्रिटिश संसद में अक्सर करते हैं. किसी भी राज्य के विभाजन के लिए लाया गया बिल पास करने के लिए ब्रिटेन के दोनों सदनों में कम से कम तीन महीने का समय लगता है. भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था का दिखावा करता है, लेकिन अब यहां इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं बचा है.

इस अवस्था की शुरुआत उसी समय हो गई थी, जब इंदिरा गांधी ने 1971 के दोबारा चुनावों के बाद कार्यकारी शक्तियों को प्रधानमंत्री के हाथों में समेटना शुरू कर दिया था. बाद में जब दलबदल एक समस्या बन गया, तब दलबदल विरोधी क़ानूनों को पास किया गया और नौवीं अनुसूची बैक बेंच के सांसदों के लिए ताबूत में आख़िरी कील की तरह लगने लगी. एक भारतीय सांसद को अपने पार्टी अध्यक्ष के व्हिप कमांड को मानना होता है. ज़्यादातर समय उसे अपनी बात कहने की इजाजत भी नहीं होती है, चाहे वह पार्टी से सहमत न भी हो. बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में संशोधित किया जाता है और उसके बाद संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. ऐसी अवस्था में सांसद के पास सिर्फ़ शारीरिक रूप से उपस्थित होने से अधिक कोई उपाय नहीं बचता है.

किसी भी सांसद के लिए अपनी असहमति जताने का सिर्फ़ एक उपाय है कि वह संसद की कार्रवाई में बाधा पहुंचाए. कई बार ऐसा होता है कि सांसद, कई पार्टी के सांसद व्हिप के कारण ही अभद्र व्यवहार करते हैं, क्योंकि यह बात तय है कि अगर बड़ी पार्टियों ने एक बार किसी बिल को पेश कर दिया, तो वह पास हो ही जाएगा. यही कारण था कि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उस समय हंगामा कर दिया था, जब प्रोन्नति में दलितों को आरक्षण दिए जाने वाला बिल पेश किया जाना था. यह भी हो सकता है कि उन्होंने यह उपद्रव किसी सौदेबाजी, चाल के तहत अपनी पार्टी के लिए किया हो या सत्ताधारी पार्टी के लिए. जब सांसदों की पार्टी ही सत्ताधारी पार्टी हो, तो उनके पास उपद्रव ही एकमात्र रास्ता बचता है, जैसा कि आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी सांसदों ने किया. इसकी बेहतरीन शुरुआत कांग्रेस ने की और भाजपा ने आख़िरी वक्त पर उसका बेहतर साथ दिया. कोई भी सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहती कि संसद की कार्रवाई बेहतर तरीके से चलती रहे. उपद्रव चलता रहे और कोई क़ानून न बनाना पड़े, यही मूलमंत्र है. ■

feedback@chauthiduniya.com

थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ (आईओएस) के अध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री डॉ. मंजूर आलम कहते हैं कि भारतीय संविधान की रक्षा के लिए टैक्टिकल वोटिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि फासीवादी एवं सांप्रदायिक तत्वों के उभार के कारण राष्ट्र का भविष्य ख़तरे में पड़ गया है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो इन तत्वों का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा. सेक्युलरिज्म का नाम लेने वाली पार्टियों के उम्मीदवारों को सफल बनाने का आइडिया जारी रहना चाहिए.

टैक्टिकल वोटिंग

...और घटता गया मुसलमानों का असर

ए यू आसिफ

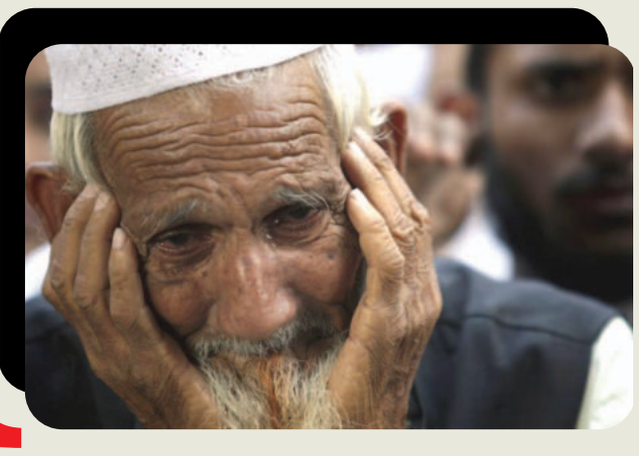

विकीपिडिया की परिभाषा के अनुसार, जब एक मतदाता अपनी पसंद से हटकर किसी न चाहने वाले नतीजे को टालने के लिए चुनाव के दौरान विभिन्न उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार के हक़ में अपना मत देता है, तो उसे टैक्टिकल वोटिंग कहते हैं. आज़ादी के बाद टैक्टिकल वोटिंग की आवाज़ पहली बार 1991 के संसदीय चुनाव के दौरान सुनने को मिली और वह भी मुस्लिम समुदाय में. दरअसल, इससे पूर्व बाबरी मस्जिद मुद्दे पर भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने पर स्वर्गीय वी पी सिंह की नेतृत्व वाली नेशनल फ्रंट सरकार सिद्धांत की बुनियाद पर 7 नवंबर, 1990 को गिर गई थी. फिर जब 1991 के चुनाव हुए, तो उसमें भाजपा उम्मीदवारों को पराजित करने के लिए सेक्युलरिज्म का नारा देने वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों को सफल बनाने की अपील की गई. इसीलिए सेक्युलरिज्म का नारा देने वाली पार्टियों में से कई ने पीवी नरसिम्हाराव के नेतृत्व में अल्पसंख्यक सरकार का समर्थन कर दिया, जो 1996 तक सत्ता में रही.

इसके बाद 1996 में संसदीय चुनाव के समय मुस्लिम संगठनों एवं नुमाइंदों ने टैक्टिकल वोटिंग के लिए अपने-अपने तौर पर अपील की. यह वह समय था, जब 1992 में केंद्र में कांग्रेस एवं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में भड़के सांप्रदायिक दंगे को लेकर दोनों पार्टियों के विरुद्ध वातावरण गर्म था. टेक्टिकल वोटिंग की अपील के फलस्वरूप सेक्युलरिज्म का नारा देने वाली दीगर पार्टियों के उम्मीदवार बड़ी संख्या में सफल हुए, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. ऐसे में भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई, जो मात्र तेरह दिनों तक क़ायम रही. तत्पश्चात ग़ैर कांग्रेसी एवं ग़ैर भाजपा यूनाइटेड फ्रंट सरकार पहले एचडी देवगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में अस्तित्व में आई. ये दोनों सरकारें कुल मिलाकर 2 वर्ष तक कायम रहीं.

1998 के संसदीय चुनाव के समय भी टेक्टिकल वोटिंग की अपीलें की गईं. मुसलमानों ने देश के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में भाजपा के उम्मीदवारों के विरुद्ध एवं सेक्युलरिज्म का नारा देने वाली पार्टियों के हक़ में वोट दिए, बावजूद इसके भाजपा, जो 1996 में अन्य पार्टियों का समर्थन पाने में असफल रही थी, वह इस बार नेशनल डेमोक्रेटिक एलाएंस (एनडीए) के अंतर्गत विभिन्न पार्टियों का समर्थन पाने में सफल हो गई. 1999 में वाजपेयी सरकार एक वोट, वह भी सैफुद्दीन सोज़ का, न मिलने के कारण गिर गई और फिर चुनाव हुए. तब भाजपा ने वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए के अंतर्गत फिर से सरकार बनाई, जो 2004 तक चली. 2004 के संसदीय चुनाव में भी टेक्टिकल वोटिंग का सुर बजता रहा. यह वह समय था, जब दो वर्ष पूर्व गुजरात में गोधरा कांड के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए और लोग भाजपा, विशेषकर नरेंद्र मोदी से काफी नाराज थे. 2004 के चुनाव के बाद मनमोहन सिंह की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलाएंस (यूपीए) सरकार सत्तासीन हुई. यही स्थिति 2009 में रही और मुसलमानों ने एक बार फिर टेक्टिकल वोटिंग की. इस बार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार पुन: सत्ता में वापस आई.

1991 में भाजपा के विरुद्ध मुसलमानों में जो वातावरण बना और उसके फलस्वरूप टेक्टिकल वोटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह 2009 के संसदीय चुनाव तक चलता रहा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान भी आजमाया जाता रहा. आज 23 वर्षों बाद आवश्यकता महसूस होती है कि विश्लेषण किया जाए कि टेक्टिकल वोटिंग वास्तव में कितनी प्रभावी और लाभदायक रही? सामूहिक रूप से इस अनुभव ने मुसलमानों के राजनीतिक सशक्तिकरण में क्या भूमिका निभाई? क्या साधारण मुस्लिम मतदाता मुस्लिम संगठनों एवं नुमाइंदों की टेक्टिकल वोटिंग की अपील में अब भी आकर्षण महसूस करते हैं? टैक्टिकल वोटिंग की चर्चा होते ही सबसे पहले इसके उद्देश्य की तरफ़ ध्यान जाता है. प्रश्न उठता है कि आख़िर 1991 में शुरू की गई टैक्टिकल वोटिंग का उद्देश्य क्या था. क्या यह आइडिया किस और के दिमाग़ की पैदावार था? क्या मुसलमानों का यह सामूहिक तौर पर सोचा-समझा मंसूबा था या उनकी दुखती रग पर हाथ रखकर किसी पार्टी, समूह या शख़्स ने अपना उल्लू सीधा किया?

ज़ाहिर सी बात है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में एक फरवरी, 1986 को बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद देश का वातावरण सांप्रदायिक होने लगा था और उससे दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, विशेषकर मेरठ आदि बुरी तरह प्रभावित हुए थे. यह वही समय था, जब मई 1987 में हाशिमपुरा एवं मलियाना में पुलिस दस्ते रक्षक से भक्षक बन गए, जिसके फलस्वरूप मुरादनगर (उत्तर प्रदेश) में गंगनहर के किनारे हाशिमपुरा में 41 लोगों को गोलियों से भूनकर बहते हुए पानी में फेंक दिया गया था, जिनमें से 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल तो हुए, लेकिन बच गए और दर्दनाक इतिहास के जीवित प्रभावित ही नहीं, बल्कि गवाह भी बन गए. उस समय चौथी दुनिया (हिंदी) ने मलियाना एवं हाशिमपुरा की घटनाओं का खुलासा किया था. इस संवाददाता ने भी मुरादनगर के घटनास्थल पर सड़क और झाड़ियों में खून के धब्बे देखे थे. स्थानीय पुलिस द्वारा वहां सड़क पर लगाए गए पीले रंग के क्रॉस चिन्ह को भी कैमरे में कैद कर लिया था, जिसे चौबीस घंटे बाद मिटा दिया गया था. हमने वहां 26 घंटे तक निकटवर्ती थाने के सामने स्थित पेशाबघर में छिपे रहे और फिर मुरादनगर के प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय हकीम जाकिर हुसैन एवं उनके स्वर्गीय पुत्र हकीम खालिद हाशमी के सहयोग से पनाह लिए बदनसीब जुल्फिकार नासिर से मिलकर उनका इंटरव्यू भी लिया था. पूर्व केंद्रीय विधि राज्यमंत्री एवं पूर्व गवर्नर मुहम्मद यूनुस सलीम और पूर्व विधि मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने हिंडन नदी में बहती लाशों के सामने खड़े होकर इसे सरकार प्रायोजित घटना कहा था.

वास्तव में ऐसी विशेष परिस्थितियों में हिंदुत्ववादी ताकतें भी सक्रिय हो गईं एवं राम जन्मभूमि आंदोलन ज़ोर पकड़ने लगा. इसी दौरान वी पी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार, जो भाजपा के बाहरी समर्थन पर कायम थी, उसके द्वारा समर्थन वापस लेने पर गिर गई. यह निश्चय ही बहुत नाजुक स्थिति थी, परंतु क्या ऐसे में 1991 के चुनाव के समय टैक्टिकल वोटिंग का निर्णय उचित था? नहीं, क्योंकि भाजपा को सत्ता में आने और प्रभाव डालने से रोकने के लिए यह जो रणनीति बनाई गई, इसका अब कोई लाभ होता दिखाई नहीं पड़ता. वास्तव में यह रणनीति स्वयं मुसलमानों की नहीं थी, बल्कि इसे उन पर कुछ राजनीतिक तत्वों द्वारा थोपा गया था. 1991 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए, उनमें भाजपा का कुल मिलाकर मत प्रतिशत बढ़ा और इस रणनीति के बावजूद उसने केंद्र में एनडीए के अंतर्गत छह वर्षों तक शासन किया. इस कटु सत्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम संगठन एवं विशिष्ट लोग टैक्टिकल वोटिंग का नारा लगाते और भाजपा उम्मीदवारों को पराजित करने के लिए सेक्युलरिज्म का नाम लेने वाली किसी भी पार्टी के उम्मीदवारों को सफल बनाने की अपील करते रहे, लेकिन उनका प्रभाव खुद घनी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों, चाहे वे संसदीय हों या विधानसभाई, में कहीं भी नहीं पड़ा. वे इस मामले में बेबस थे कि उन क्षेत्रों में विभिन्न पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतरने से रोक सकें, जिसके फलस्वरूप घनी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों से भाजपा के उम्मीदवार क़ाबिले ज़िक्र संख्या में कामयाब हुए और यह सिलसिला अभी भी जारी है.

थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ (आईओएस) के अध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री डॉ. मंजूर आलम कहते हैं कि भारतीय संविधान की रक्षा के लिए टैक्टिकल वोटिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि फासीवादी एवं सांप्रदायिक तत्वों के उभार के कारण राष्ट्र का भविष्य ख़तरे में पड़ गया है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो इन तत्वों का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा. सेक्युलरिज्म का नाम लेने वाली पार्टियों के उम्मीदवारों को सफल बनाने का आइडिया जारी रहना चाहिए. घनी मुस्लिम आबादी वाले किसी क्षेत्र में एक साथ कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होने को वह सेक्युलर वोट में विभाजन तो मानते हैं, मगर यह कैसे रुके, इसकी उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है. शायद यह विभाजन तभी रुक सकता है, जब मुस्लिम समुदाय के विभिन्न विचारों के लोग एवं संगठन विभिन्न पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवारों एवं स्वतंत्र मुस्लिम उम्मीदवारों के बजाय किसी एक मुस्लिम उम्मीदवार पर सहमत हो जाएं, जो इस समय संभव नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि अपनी उम्मीदवारी की वापसी का निर्णय कोई उम्मीदवार स्वयं नहीं कर सकता, वह तो अपनी पार्टी के निर्णय का पाबंद होता है. अन्य मुस्लिम संगठनों एवं लोगों का कमोबेश यही हाल है. सबके सब टेक्टिकल वोटिंग के जाल से बाहर निकलने की स्थिति में हरगिज़ नहीं हैं. शायद इसलिए, क्योंकि इनमें से अधिकतर की राजनीतिक पार्टियों में किसी न किसी से निकटता, वफ़ादारी, यहां तक कि कमिटमेंट भी है. ये देश भर में भाजपा और उसकी समर्थक पार्टियों को पराजित करने के नाम पर शेष तमाम पार्टियों को ऑब्लाइज करके अपने-अपने स्वार्थ साधते हैं. टैक्टिकल वोटिंग का असल निशाना तो शुरू में लालकृष्ण आडवाणी एवं भाजपा थे, लेकिन 2002 में गुजरात के सांप्रदायिक दंगों के बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा हो गए. वाजपेयी के रहते आडवाणी तो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन इसमें मुसलमानों की टैक्टिकल वोटिंग की कोई भूमिका नहीं थी और अब मोदी के प्रधानमंत्री बनने या न बनने में भी कोई भूमिका नहीं होगी.

आज 23 वर्षों बाद आवश्यकता महसूस होती है कि विश्लेषण किया जाए कि टैक्टिकल वोटिंग वास्तव में कितनी प्रभावी और लाभदायक रही? सामूहिक रूप से इस अनुभव ने मुसलमानों के राजनीतिक सशक्तिकरण में क्या भूमिका निभाई? क्या साधारण मुस्लिम मतदाता मुस्लिम संगठनों एवं नुमाइंदों की टैक्टिकल वोटिंग की अपील में अब भी आकर्षण महसूस करते हैं? टैक्टिकल वोटिंग की चर्चा होते ही सबसे पहले इसके उद्देश्य की तरफ़ ध्यान जाता है. प्रश्न उठता है कि आख़िर 1991 में शुरू की गई टैक्टिकल वोटिंग का उद्देश्य क्या था. क्या यह आइडिया किस और के दिमाग़ की पैदावार था? क्या मुसलमानों का यह सामूहिक तौर पर सोचा-समझा मंसूबा था या उनकी दुखती रग पर हाथ रखकर किसी पार्टी, समूह या शख़्स ने अपना उल्लू सीधा किया?

आज मुस्लिम समुदाय टूट-फूट का शिकार है. चौथी दुनिया उर्दू (17-23 फरवरी, 2014 के अंक) में मुस्लिम नेतृत्व: राष्ट्र प्रेम से प्रेरित, मगर टूट-फूट का शिकार शीर्षक से प्रकाशित विश्लेषण से इसे समझा जा सकता है. जाहिर है कि इस स्थिति में वे एकमत होकर कैसे कोई निर्णय ले सकते हैं? क्या यह उचित नहीं होता कि टैक्टिकल वोटिंग का नारा देने के बजाय मुस्लिम समुदाय अपने बुनियादी मुद्दों एवं एजेंडे पर गंभीर होता और फिर यह मांग करता कि जो पार्टी उसके एजेंडे पर जितना अधिक अमल करेगी, मुसलमानों का वोट सामूहिक रूप से उसी को जाएगा. यह अचंभे की बात है कि टैक्टिकल वोटिंग ने मुसलमानों को ठोस एजेंडे एवं बुनियादी मुद्दों के बजाय मात्र भाजपा उम्मीदवारों को पराजित करने के लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया और उन्हें कोई सफलता भी हाथ नहीं लगी.

सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में चुनावी परिसीमन जनसंख्या के लिहाज़ से करने की सिफारिश की है, लेकिन विडंबना यह है कि आम तौर पर चुनाव पूर्व किसी क्षेत्र का परिसीमन करके उसे आरक्षित कर दिया जाता है और जनता को उस निर्णय की जानकारी बाद में अचानक मिलती है. 5 दिसंबर, 2013 को राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति द्वारा बताया कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद से इन राज्यों के ढांचे में आवश्यक परिवर्तन नहीं किया जा सका था, जो अब किया जा रहा है. आयोग ने अपने प्रस्ताव में यह भी शामिल किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया जाए. ज़ाहिर है कि अगर 43 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या वाला सहारनपुर आरक्षित क्षेत्र बन जाता, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुसलमानों के लिए अपनी पसंद का एक और प्रतिनिधि भेजने का अवसर समाप्त हो जाता, लेकिन मुस्लिम संगठन ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के परिसीमन विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई से यह ख़तरा टल गया. संगठन के अध्यक्ष डॉ. सैयद ज़फ़र महमूद ने चौथी दुनिया को बताया कि उनके इस विभाग की पिटीशन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने सहारनपुर का दौरा किया, जहां उन्हें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होने के कारण आरक्षित किए जा सकते हैं, जबकि सहारनपुर में घनी मुस्लिम आबादी है. लोगों की दलील से चुनाव आयोग संतुष्ट हो गया और उसकी नई विज्ञप्ति में लिखा गया कि उसने सहारनपुर को आरक्षित करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन इस संबंध में आई आपत्तियों एवं दस्तावेजों की बुनियाद पर उसने अपना इरादा बदल दिया है. इस उचित समय पर हुई कार्रवाई से अंदाजा होता है कि अगर मुस्लिम संगठन एवं अन्य नेतृत्व परिसीमन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देते, तो यह भी मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने का एक प्रभावी क़दम होता. इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन दु:ख की बात यह है कि इन संगठनों एवं लोगों में से अधिकतर को इन सबसे कोई मतलब नहीं है. इनका तो मात्र यह शग़ल हो गया है कि किसी भी घटना या मुद्दे पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दें, इस नेक काम में एक-दूसरे से बाज़ी मार ले जाएं और फिर उर्दू समाचारपत्रों में इसे प्रकाशित कराने की कोशिश करें. वर्षों से यही हो रहा है. उर्दू समाचारपत्र किसी भाषा के शायद अकेले समाचारपत्र हैं, जिनमें ऐसी विज्ञप्तियां ज्यों की त्यों प्रकाशित हो जाती हैं. यदि मुस्लिम समुदाय को स्वयं का विकास और सशक्तिकरण करना है, तो उसे टैक्टिकल वोटिंग के इस खेल से बाहर निकल कर एक ध्येयपूर्ण समुदाय बनना और व्यवहारिक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा, तभी मुस्लिम सांसदों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात के अनुरूप हो पाएगी. स्मरण रहे कि 1952 से लेकर अब तक मुस्लिम सांसदों की सबसे अधिक संख्या 1980 में 49 से आगे नहीं बढ़ पाई है.■

feedback@chauthiduniya.com

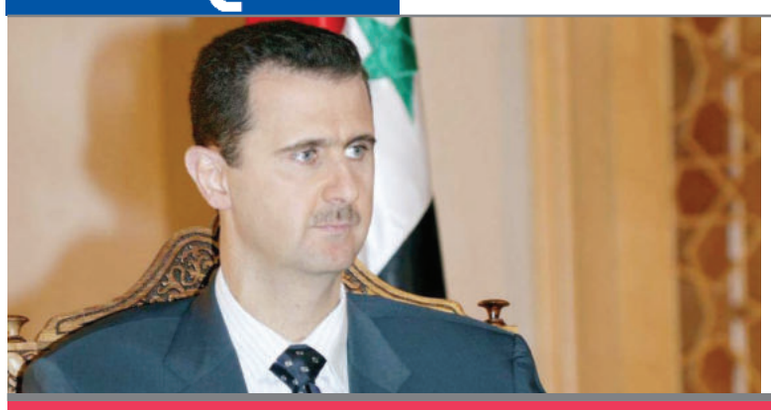

> अरब देश भारतीयों पर बहुत भरोसा करते थे और उनके साथ बिना झिझक के कारोबार साझा करते थे, लेकिन इसमें पिछले कुछ सालों में कमी हुई है, जिसकी वजह से अब अरब के शेख़ और वहां रहने वाले भारतीयों के बीच कारोबार साझीदारी का औसत तेज़ी से कम हुआ है. पहले अरब के बाज़ारों में बहुत से भारतीय कपड़े, जूते और छोटी–छोटी अन्य दुकानें चलाते मिल जाते थे, लेकिन अब उनकी जगह अफगानी और पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं.

भारत की कमज़ोर विदेश नीति

मुस्लिम देशों से दूरी विकास में बाधा

प्रत्येक देश की अपनी विदेश नीति होती है. शांति प्रधान भारत की भी अपनी विदेश नीति है, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत अपनी अकर्मण्य विदेश नीति के चलते न तो अरब एवं मुस्लिम देशों से दोस्ताना संबंध बनाए रख सका और न अमेरिकी एवं यूरोपीय देशों को अपने क़रीब ला सका. मतलब यह कि हाल के वर्षों में भारत की विदेश नीति लगभग नाकाम रही.

वसीम अहमद

भारत शुरू से ही एक शांतिप्रिय देश रहा है. इसकी नीति शांति एवं समझौते पर आधारित रही है. यूरोपीय देश हों या अरब देश, सभी के साथ मधुर संबंध रखना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. जब दुनिया दो सुपर पॉवर रूस और अमेरिका के ख़ेमों में बंटी हुई थी, उस समय भी भारत एक संतुलित नीति पर क़ायम था और इसीलिए भारत को दोनों ख़ेमों में बेहद सम्मानजनक दृष्टि से देखा जा रहा था. पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक भारत की विदेश नीति इसी प्रकार क़ायम रही. विशेष रूप से इस्लामी और खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत ही नज़दीकी और भावनात्मक रहे हैं. हालांकि भारत का झुकाव रूस की ओर था, जबकि अरब के अधिकांश देश अमेरिकी ख़ेमे में शामिल थे. फिर भी भारत के साथ उनका रिश्ता अपनों जैसा था. हालांकि अमेरिकी लॉबी का मज़बूत समर्थक सऊदी अरब जैसा देश भी भारत से दोस्ती रखने में दिलचस्पी लेता था और ओमान के प्रमुख सुल्तान क़ाबुस भारत को अपना दूसरा वतन कहते थे, क्योंकि उन्होंने पुणे में स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा से प्राथमिक शिक्षा ली थी, फिलिस्तीन के प्रमुख एवं आलिम अरब के हीरो यासिर अराफ़ात जब भी इंदिरा गांधी से मिलते थे, तो उन्हें अर्लख्त कहकर संबोधित करते थे. यहां तक कि दोनों प्रमुखों में भाई–बहन का रिश्ता था और इराक, जो अरब का सबसे ताक़तवर देश था, ने भारत को नसीहत देते हुए कश्मीर मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाने का समर्थन किया था. हाफिज़ उल असद भारत को एक वफ़ादार दोस्त के नाम से याद करते थे और यह उनकी भारत से दोस्ती का ही परिणाम था कि जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनके अंतिम संस्कार में मुरली मनोहर जोशी विशेष रूप से शामिल हुए थे. उर्दन उन देशों में से है, जिसके प्रमुख स्वर्गीय शाह हुसैन भारत को दिलों में बसने वाला मुल्क कहते थे.

अरब से भारत का यह लगाव केवल राजनीतिक, राजनयिक और नेताओं के स्तर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि जन स्तर पर भी अरब और भारतीयों के बीच एक विशेष लगाव था. यही कारण है कि 1991 से पहले जो लोग इराक, ओमान जैसे देशों में रह चुके हैं, उन्हें मालूम होगा कि वहां की जनता दक्षिण एशिया के देशों की तुलना में बेहतर सोच रखती थी. स्वयं लेखक का अनुभव है कि 1995 में जेद्दाह एयरपोर्ट पर जब पड़ोसी देश पाकिस्तान की फ्लाइट आई थी, तो उससे उतरने वाले यात्रियों के जूते–मोज़े उतरवा कर जांच की गई थी, जबकि भारतीय फ्लाइट के यात्रियों को रूटीन इंक्वायरी के बाद जाने दिया जाता था. कई बार के अनुभव ने मुझे हैरान कर दिया और एक बार मैंने रियाज़ एयरपोर्ट पर एक सऊदी से, जो मेरे पास बैठा था और मदीना के लिए फ्लाइट की प्रतीक्षा कर रहा था, इस बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया, अलहिंदी केस यानी भारतीय लोग बड़े अच्छे होते हैं.

अरब देशों में भारत को लेकर यह सकारात्मक प्रभाव कोई एक–दो दिन में पैदा नहीं हुआ. नेहरू के दौर से लेकर इंदिरा गांधी के ज़माने तक इस पर निरंतर मेहनत होती रही और उसी मेहनत का नतीजा था कि यूरोप समेत अरब देशों में भारत एक शांतिप्रिय देश के रूप में पहचाना गया, लेकिन पिछले दस सालों में भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, वह अस्पष्टता का शिकार रही. इसके चलते अरब की जनता और भारतीय जनता में जो भावनात्मक लगाव था, उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया है और इसी का नतीजा है कि कल तक अरब के वे देश, जो कश्मीर मुद्दे पर भारत के ख़िलाफ़ बयान देने से गुरेज़ करते थे, आज खुलकर बोल रहे हैं. यहां तक कि ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामी कंट्रीज़ (ओआईसी), 57 मुस्लिम देश जिसके सदस्य हैं, की ओर से बयान जारी कर दिया गया है कि कश्मीर मुद्दा एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है. इसका साफ़ मतलब यह है कि कल तक अरब देश जिस मुद्दे पर भारत के पक्ष में बोलते थे या फिर ख़ामोश रहते थे, आज वही देश भारत के विरोध में खुलकर बोल रहे हैं. इस प्रकार देखा जाए, तो अरबों से राजनयिक संबंध बेहतर बनाने में भारत पूरी तरफ़ असफल हो चुका है और सभी मुस्लिम देश भारत से दूर होते जा रहे हैं.

वाजपेयी सरकार ने मुस्लिम देशों को क़रीब लाने के लिए पाकिस्तान से बेहतर संबंधों की बुनियाद क़ायम की थी. आशा थी कि मनमोहन सिंह की सरकार उसे और अधिक आगे ले जाएगी, लेकिन उन संबंधों को पिछले दस वर्षों में जो नुक़सान हुआ है, वह बेहद अफसोसजनक है. अब न तो इराक हमारे साथ है और न वह कश्मीर मुद्दे पर हमारा समर्थन कर रहा है. न फिलिस्तीन के साथ हमारे संबंधों में वह गर्मजोशी रही और न अब शेख़ क़ाबूस भारत में उतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जितनी कभी दिखाते थे. सीरिया भी अब हमारा उतना अच्छा दोस्त नहीं रहा. यहां तक कि विदेश नीति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत इतना प्रभावहीन और कमज़ोर कभी नज़र नहीं आया, जितना पिछले 10 सालों में मनमोहन सिंह की सत्ता में रहा. इस कमज़ोर विदेश नीति के कारण जहां विश्व स्तर पर हमारी पहचान ख़राब हुई है, वहीं आर्थिक दृष्टि से भी हमारा ज़बरदस्त नुक़सान हुआ है.

अब सवाल यह पैदा होता है कि पिछले 10 वर्षों में अरबों से दोस्ती कमज़ोर होने का बुनियादी कारण क्या रहा? अगर इस पर ध्यान दें, तो पता चलता है कि मनमोहन सिंह के सत्ता में रहते हुए वैश्विक संबंधों को एक विशेष दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया. वह विशेष दृष्टि थी कि देश को रक्षात्मक रूप से मज़बूत किया जाए और इस उद्देश्य के लिए यूरोप एवं इजरायल से दोस्ती बढ़ाई गई. अमेरिका और इजरायल से अरबों डॉलर के हथियारों का समझौता हुआ. यह बात पहली नज़र में अच्छी लगती है और ऐसा महसूस होता है कि देश मज़बूत हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूरोप और इजरायल की दोस्ती ने देश को रक्षा के नाम पर मज़बूत तो नहीं किया, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल नाकारा बना दिया, क्योंकि अगर हम रक्षात्मक दृष्टि से भी देखते हैं, तो भी खाड़ी देशों का पलड़ा भारी है. अगर हम बात ईरान की करें, तो वहां से तेल के आयात में भारत ने 2013 में जबरदस्त कटौती की है, जो ईरान से कुल तेल आयात का 38 फ़ीसद है. यह कटौती 1,95,600 बैरल प्रतिदिन के आसपास है. 2013–14 में ईरान से तेल आयात में कटौती के लिए भारत ने 15 फ़ीसद का लक्ष्य रखा है. इसके लिए भारत को अपने तेल आयात में प्रतिदिन 9–9.5 मिलियन बैरल की कटौती करनी होगी.

> **अरब देशों से भारत का लगाव केवल राजनीतिक, राजनयिक और नेताओं के स्तर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि जन स्तर पर भी अरब और भारतीयों के बीच एक विशेष लगाव था. यही कारण है कि 1991 से पहले जो लोग इराक, ओमान जैसे देशों में रह चुके हैं, उन्हें मालूम होगा कि वहां की जनता दक्षिण एशिया के देशों की तुलना में बेहतर सोच रखती थी.**

यूरोप एवं अमेरिका जो तकनीक और हथियार आपूर्ति करते हैं, वैसे हथियार दुनिया में हर विकासशील देश में उपलब्ध है, लेकिन जो पेट्रोल, गैस, रोज़गाार और ग्राहक हमें मुस्लिम एवं खाड़ी देश देते हैं, उसका विकल्प हमारे पास नहीं है. मतलब यह है कि अमेरिका और इजरायल से दोस्ती के बदले हमें जो कुछ मिला है, वह कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है, जो हमें औरों से अलग करती है, जबकि अरबों से दूरी ने हमारी बुनियाद यानी अर्थव्यवस्था को ही कमज़ोर बना दिया है और इसी कारण देश में बेरोज़गारी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार चरम पर है.

ताजा आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है. पिछले चार दशकों से रूस भारत को हथियार आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश था, लेकिन पिछले साल अमेरिका ने यह बाजी अपने हाथ कर ली. 2013 में भारत ने 1.9 बिलियन डॉलर के अमेरिकी हथियारों की खरीद की थी. यह सर्वविदित है कि भारत अमेरिका से अपनी दोस्ती को न तो अपने पक्ष में कर पाया है और न किसी अंजाम तक पहुंचा पाया है. जब अमेरिका चाहता है, भारत को धौंस दे देता है. इसके अतिरिक्त अमेरिका अपने हितों का ख्याल रखते हुए भारत की बलि चढ़ाता रहा है. अमेरिका पहले भारत, पाकिस्तान एवं अन्य देशों में अशांति फैलाता है, फिर इन देशों को तथाकथित शांति स्थापना के लिए हथियारों की आपूर्ति करता है. ऐसा करके अमेरिका अपना उल्लू सीधा करता है. यह सब अमेरिका बहुत ही सुनियोजित तरीके से करता है. इजरायल और अमेरिका हमें जो हथियार देते हैं, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, जो हमें मुस्लिम देशों से आसानी के साथ मिल सकता था, लेकिन भारत ने इजरायल से दोस्ती बढ़ाने के लिए अरबों को ख़ुद से बहुत दूर कर दिया. इसका नुक़सान एक ओर यह हुआ कि हमें तेल के आयात में कठिनाइयां आ रही हैं, साथ ही खाड़ी देश, जो एक बड़ी मंडी की हैसियत रखते हैं, वहां भारतीय उत्पादों की खपत कम हो गई, जिसका नकारात्मक असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं. इसके बावजूद उन्होंने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते हमने अपने उत्पादों के लिए एक बड़ा बाज़ार गंवा दिया. वर्ष 2000 तक अरब की मंडियों में भारतीय उत्पादों की भरमार हुआ करती थी, लेकिन धीरे–धीरे भारतीय उत्पाद उनके बाज़ारों से ख़त्म होते गए और उनकी जगह चीनी, लेबनानी एवं पाकिस्तानी उत्पादों ने ले ली. ज़ाहिर है, गलत विदेश नीति के कारण इन दस वर्षों में हमने जो मंडियां अरब देशों में गंवा दी हैं, उनका विकल्प हमें न तो अमेरिका दे सकता है और न इजरायल. कुल मिलाकर देखा जाए, तो मुस्लिम देशों से दूरी का सबब यह हुआ कि एक ओर हमारे उत्पादों की खपत के लिए बाज़ार कम हो गए और दूसरी ओर भारतीयों के लिए अरब में कारोबार के अवसर भी कम हुए. हालांकि 2.8 मिलियन भारतीय सऊदी अरब में आज भी काम कर रहे हैं. सऊदी भारत का चौथा व्यापारिक देश है. वर्तमान में भारतीय उत्पादों के निर्यात के लिए सऊदी छठा बड़ा बाज़ार है. अपने कुल वैश्विक निर्यात का सऊदी 8.3 फ़ीसद भारत से निर्यात करता है. भारत सऊदी अरब का सातवां आयातक देश है, जो अपने कुल आयात का सऊदी से 3.4 फ़ीसद आयात करता है. भारत अपने कुल कच्चे तेल के आयात का पांचवा भाग सऊदी से आयात करता है.

अरब देश भारतीयों पर बहुत भरोसा करते थे और उनके साथ बिना झिझक के कारोबार साझा करते थे, लेकिन इसमें पिछले कुछ सालों में कमी हुई है, जिसकी वजह से अब अरब के शेख़ और वहां रहने वाले भारतीयों के बीच कारोबार साझीदारी का औसत तेज़ी से कम हुआ है. पहले अरब के बाज़ारों में बहुत से भारतीय कपड़े, जूते और छोटी–छोटी अन्य दुकानें चलाते मिल जाते थे, लेकिन अब उनकी जगह अफगानी और पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं. अब पहले की तरह भारतीय प्रवासियों के प्रति अरबों के दिलों में वह भावना और सहानुभूति देखने को नहीं मिलती है, जो दो दशक पहले थी. इससे पता चलता है कि भारत और खाड़ी देशों के बीच जो भरोसा और भावनात्मक लगाव था, वह इन दस वर्षों में तेज़ी से कम हुआ है, जिसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई

साई बाबा की भक्ति करने से आध्यात्म की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त करके शांति एवं सुख की प्राप्ति हो जाती है. साई बाबा की लीलाओं का श्रवण करके उनका मनन करें. यदि आप इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे, तो उन्हें अपने जीवन–ध्येय और परमानंद की सहज प्राप्ति हो जाएगी. सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, लेकिन हास्य का पात्र स्वयं कोई नहीं बनना चाहता.

एक बार...

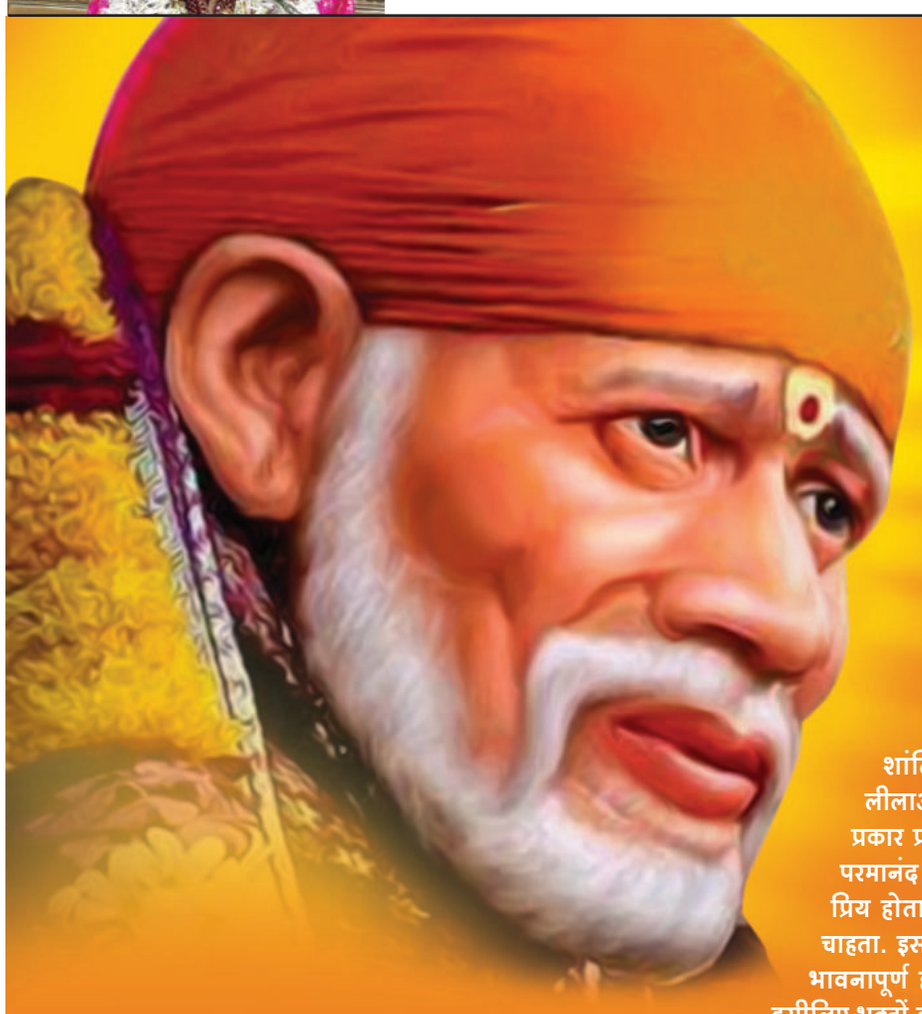

सद्गुरु का सानिध्य

शिरडी में प्रत्येक रविवार को बाज़ार लगता है. निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहां रास्तों पर दुकानें लगाते और सौदा बेचते हैं. मध्यान्ह के समय मस्जिद लोगों से भर जाती थी, लेकिन रविवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती थी कि प्राय: दम ही घुटने लगता था. एक रविवार हेमाड पंत साई बाबा की चरण-सेवा कर रहे थे. शामा बाबा के बाई ओर एवं वामनराव बाबा के दाहिनी ओर थे.

साई बाबा दु:ख दूर करने वाले हैं. वह भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखते हैं. पहले हम साई बाबा के चरणों में प्रणाम करें, उनकी कृपादृष्टि मात्र से ही समस्त पाप भस्म होकर नष्ट हो जाएंगे. वह अपने मन में किसी के लिए कोई भेद नहीं रखते. उनके लिए सभी बराबर हैं. भेदभाव उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होता. साई बाबा मूलत: निराकार थे, लेकिन भक्तों के प्रेमवश ही वह साकार रूप में प्रगट हुए. शिरडी में जब आरती समाप्त हो जाती थी, तब साई बाबा मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा एवं प्रेम के साथ भक्तों को उदी वितरित करते थे. बाबा के भक्त भी उनके समक्ष खड़े होकर चरण छूते और उदी वृष्टि का आनंद लेते थे. बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर उदी का टीका लगाते थे. बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था. वह भक्तों को प्रेम से संबोधित करते, ओ भाऊ, अब जाओ, भोजन करो. इसी प्रकार वह प्रत्येक भक्त से संभाषण करते और उन्हें घर लौटाया करते थे.

जब तक अहंकार गुरु-चरणों में अर्पित न कर दिया जाए, तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है. यदि हम निर्भीक हो जाएं, तो सफलता प्राप्त होना निश्चित है. साई बाबा की भक्ति करने से आध्यात्म की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त करके शांति एवं सुख की प्राप्ति हो जाती है. साई बाबा की लीलाओं का श्रवण करके उनका मनन करें. यदि आप इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे, तो उन्हें अपने जीवन-ध्येय और परमानंद की सहज प्राप्ति हो जाएगी. सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, लेकिन हास्य का पात्र स्वयं कोई नहीं बनना चाहता. इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी. जब वह भावनापूर्ण होती, तो अति मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होती थी. इसीलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था, तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति नहीं होती थी.

शिरडी में प्रत्येक रविवार को बाज़ार लगता है. निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहां रास्तों पर दुकानें लगाते और सौदा बेचते हैं. मध्यान्ह के समय मस्जिद लोगों से भर जाती थी, लेकिन रविवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती थी कि प्राय: दम ही घुटने लगता था. एक रविवार हेमाड पंत साई बाबा की चरण-सेवा कर रहे थे. शामा बाबा के बाई ओर एवं वामनराव बाबा के दाहिनी ओर थे. इस अवसर पर बाबा के भक्त बूटी साहेब और काका साहेब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे. भक्त शामा ने हंसकर अण्णा साहेब से कहा, देखो, तुम्हारे कोट की बांह पर कुछ चने लगे हुए-से प्रतीत होते हैं.

ऐसा कहकर शामा ने उनकी बांह स्पर्श की, जहां कुछ चने के दाने मिले. जब हेमाड पंत ने अपनी बाई कुहनी सीधी की, तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने बीनकर उठाए. भक्तों को हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति-भांति के अनुमान लगाने लगे, लेकिन कोई भी यह नहीं जान सका कि चने केदाने वहां आए कहां से और इतने समय तक उसमें कैसे रहे? इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, लेकिन इस रहस्य का भेद जानने के लिए प्रत्येक भक्त उत्सुक था. तब बाबा कहने लगे, इन महाशय (अण्णा साहेब) को एकांत में खाने की बुरी आदत है. आज बाज़ार का दिन है और यह चने चबाते हुए यहां आए हैं. मैं तो इनकी आदतों से भलीभांति परिचित हूं और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं. इसमें आश्चर्य की बात क्या है.

हेमाड पंत बोले, बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं. अभी तक मैंने शिरडी के बाज़ार के दर्शन भी नहीं किए और आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाज़ार नहीं गया. फिर आप ही बताइए कि मैं ये चने भला कैसे खरीदता और जब मैंने खरीदे ही नहीं, तब इन्हें खाने की बात तो दूर की है. भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं, उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी ग्रहण नहीं करता. बाबा, तुम्हारा कथन सत्य है, लेकिन जब तुम्हारे समीप ही कोई न हो, तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं. अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है, क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूं, क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो?

साई बाबा के प्रश्नों का अण्णा साहब ने उत्तर दिया और फिर उनके चरणों पर गिर पड़े. साई बाबा सब कुछ जान लेते थे. जिन भक्तों ने बाबा के उपदेशों का पूर्णत: पालन किया, वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए. साई बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान-चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा देने में समर्थ हैं. विषय-वासनाओं से आसक्ति नष्ट करके वह भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान एवं वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है. यह सब केवल उसी समय संभव है, जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो और सेवा के पश्चात हम उनका प्रेम प्राप्त कर सकें. वह हमें कष्टों एवं दु:खों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं. यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो स्वयं ईश्वर के प्रतीक हैं. इसीलिए हमें सद्गुरु के सानिध्य में सदैव रहना चाहिए. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

प्रथम ज्योर्तिलिंग सोमनाथ

भक्तों की हर मुराद होती है पूरी

धर्मेंद्र सिंह

भगवान शिव दुनिया के रखवाले हैं और कण-कण में उनका वास है. उन्हें औघड़ दानी भी कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि भोले भंडारी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं. शिवलिंग को धरती पर भगवान शिव का साक्षात रूप माना जाता है. शिवलिंग पर मात्र गंगाजल के अभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं. पूरे भारत में भगवान शिव के प्रसिद्ध बारह ज्योर्तिलिंग हैं, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं. भगवान शिव के बारह ज्योर्तिलिंगों के नाम हैं:-सोमनाथ, मल्किार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी-विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर एवं घृष्णेश्वर महादेव. ये द्वादश ज्योर्तिलिंग भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में विख्यात हैं. इन बारह ज्योर्तिलिंगों के दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु जैसे दोष दूर हो जाते हैं. इस बार हम आपको सोमनाथ ज्योर्तिलिंग के बारे में बताते हैं.

सोमनाथ हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर (तीर्थस्थल) है, जो बारह ज्योर्तिलिंगों में सर्वप्रथम है. शिव महापुराण में कहा गया है कि प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था, लेकिन चंद्रमा केवल अपनी पत्नी रोहिणा से अधिक प्रेम करते थे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे. चंद्रमा के इस आचरण से उनकी 26 पत्नियां दु:खी रहती थीं. दक्ष प्रजापति को जब अपनी पुत्रियों के दु:ख के बारे में पता चला, तो उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि उन्हें सभी 27 पत्नियों से एक समान प्रेम करना चाहिए, लेकिन चंद्रमा पर इसका कोई असर नहीं हुआ. कुपित होकर और क्रोध में आकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया. चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए, जिससे चारों तरफ़ आकाश-पाताल में हर जगह हाहाकार मच गया. तब सभी देवगण और ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए. ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को शिवलिंग की स्थापना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप और भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी. चंद्रमा ने भगवान शिव की छह महीने तक कठोर तपस्या कर आराधना की और 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया. भगवान शिव चंद्रमा के कठोर तप को देखकर प्रसन्न हो गए. उन्होंने चंद्रमा को क्षय के श्राप से मुक्त कर दिया और शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए. चंद्रमा के नाम पर ही शिवलिंग का नाम सोमनाथ रखा गया.

भगवान सोमनाथ की पूजा, उपासना और दर्शन करने से भक्तों के क्षय एवं त्वचा संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं. सोमनाथ में एक चंद्रकुंड भी है. मान्यता है कि यहां भगवान शिव और ब्रह्मा सदा निवास करते हैं. इस कुंड में छह माह तक लगातार स्नान करने से असाध्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं. यहां देश-विदेश से करोड़ों भक्त बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए पूरे वर्ष आते हैं. महाशिवरात्रि को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है और मंदिर पूरी रात खुला रहता है. सावन माह में सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. सुबह जैसे ही सूरज की किरणें अपनी यात्रा शुरू करती हैं, अनंत सागर देवाधिदेव महादेव के चरण पखारने के लिए व्याकुल हो उठता है.

गुजरात के सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में प्रवेश करते ही दूर से ही दिखाई देने लगता है वह ध्वज, जो हजारों वर्षों से भगवान शिव के यश का गुणगान करता आ रहा है. यहां आने वाले हर शिवभक्त के मन में यह अटूट विश्वास होता है कि उसकी हर मुसीबत का अंत हो जाएगा. मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी के. सुबह सबसे पहले पंचामृत से शिव जी को स्नान कराया जाता है. स्नान के बाद शृंगार किया जाता है और शिवलिंग पर चंदन से ऊं लिखा जाता है. इसके बाद भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित किया जाता है. शृंगार के बाद पुजारी शिव के हर रूप की आराधना करते हैं. अंत में महासागर की आरती होती है. यहां आने वाले शिवभक्त अपनी मन्नतों की सिफारिश नंदी जी से करना नहीं भूलते. मान्यता है कि भक्तों की प्रार्थना उनके आराध्य तक नंदी जी ही पहुंचाते हैं.

कैसे जाएं

भगवान सोमनाथ का मंदिर जिस स्थान पर है, उसे वेरावल, सोमनाथपाटण, प्रभास और प्रभासपाटण आदि नामों से जाना जाता है. जहां राजकोट-वेरीवाल एवं खिजड़िया, वेरावल रेल लाइनें हैं. देश के किसी भी प्रमुख रेलवे स्टेशन से यहां पहुंचने के लिए पहले राजकोट जाएं और उसके बाद राजकोट से वेरावल जाएं. वहां से प्रभासपाटण पांच किलोमीटर दूर है, जहां बस अथवा टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है. यदि आप हवाई रास्ते जाना चाहते हैं, तो अमरेली एयरपोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद वहां से सोमनाथ मंदिर के लिए टैक्सी ले सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

शिवा जी को सीख

एक बार छत्रपति शिवा जी मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ रहे थे. एक दिन रात को वह थके-मांदे एक वनवासी बुढ़िया की झोंपड़ी में जा पहुंचे और उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा. बुढ़िया के घर में केवल चावल था, सो उसने प्रेमपूर्वक भात पकाया और उसे ही परोस दिया. शिवा जी बहुत भूखे थे, सो झट से भात खाने की आतुरता में उनकी उंगलियां जल गईं. हाथ की जलन शांत करने के लिए वह फूंकने लगे. यह देखकर बुढ़िया ने उनके चेहरे की ओर गौर से देखा और बोली, सिपाही, तेरी सूरत शिवा जी जैसी लगती है और साथ ही यह भी लगता है कि तू उसी की तरह मूर्ख है. शिवा जी स्तब्ध रह गए. उन्होंने बुढ़िया से पूछा, भला शिवा जी की मूर्खता तो बताओ और साथ ही मेरी भी.

बुढ़िया ने उत्तर दिया, तूने किनारे-किनारे से थोड़ा-थोड़ा ठंडा भात खाने की अपेक्षा बीच के सारे भात में हाथ डाला और उंगलियां जला लीं. यही मूर्खता शिवा जी करता है. वह दूर किनारों पर बसे छोटे-छोटे किलों को आसानी से जीतते हुए शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा बड़े किलों पर धावा बोलता है और हार जाता है. शिवा जी को अपनी रणनीति की विफलता का कारण विदित हो गया. उन्होंने बुढ़िया की सीख मानी और पहले छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने की रीति-नीति अपनाई. इस प्रकार उनकी शक्ति बढ़ी और अंतत: वह बड़ी विजय पाने में समर्थ हुए. शुरुआत हमेशा छोटे-छोटे संकल्पों से होती है, तभी बड़े संकल्प पूरे करने का आत्मविश्वास जागृत होता है. ■

शिक्षा- बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए पहले छोटे-छोटे संकल्प पूरे करें.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

मैरी कॉम मानती हैं कि खेल ही सबको प्यार में बांध सकता है. वह अपनी जाति कोम और जन्मस्थल मणिपुर को बेहद प्यार करती हैं. एक मां होने की ज़िम्मेदारियां, पति के साथ ईमानदार रिश्ते, खेल में राजनीतिक दबाव, मणिपुर का अशांत माहौल एवं समस्याएं उनकी आत्मकथा के हिस्से हैं. यह किताब पढ़कर पता चलता है कि उनके अंदर कितना साहस, सकारात्मक सोच और धैर्य है. वह विश्व महिला बॉक्सिंग में पांच बार चैंपियन रहीं और लंदन ओलंपिक 2012 में उन्हें कांस्य पदक मिला.

युवा लेखकों की धूम

अनंत विजय

दिल्ली के प्रगति मैदान में नौ दिनों तक चला विश्व पुस्तक मेला ख़त्म हो गया. दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला और लंदन बुक फेयर के बाद सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है. दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में देश के कोने-कोने से लेखकों का जत्था पहुंचता है. किताबों के इस महाकुंभ में लेखकों के साथ-साथ पाठकों की भी भागीदारी होती है. विश्व में पुस्तक मेलों का एक लंबा इतिहास रहा है. पुस्तक मेलों का पाठकों की रुचि बढ़ाने, समाज में पुस्तक संस्कृति बनाने और उसे विकसित करने में एक अहम योगदान रहा है. भारत में बड़े स्तर पर पुस्तक मेले सत्तर के दशक में लगने शुरू हुए. दिल्ली और कोलकाता में पुस्तक मेला शुरू हुआ. 1972 में भारत में पहले विश्व पुस्तक मेले का दिल्ली में आयोजन हुआ. उसके बाद से हर दूसरे साल दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता था. 2012 में जब एम ए सिकंदर ने नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक का पद संभाला, तो इसे हर साल आयोजित करने का ऐलान किया. तबसे यह विश्व पुस्तक मेला प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है.

इस बार का पुस्तक मेला पहले के आयोजनों से कई मायनों में अलग और व्यवस्थित रहा. पाठकों से लेखकों के संवाद से लेकर हिंदी महोत्सव तक आयोजित हुए, जिसमें लेखक-पाठक संवाद सुकून से संभव हुआ. इस बार लोकार्पण को लेकर भी मारामारी नहीं हुई, क्योंकि उसके लिए भी व्यवस्था थी. कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विश्व पुस्तक मेला इंतजाम के लिहाज से विश्वस्तरीय होने की राह पर चल पड़ा है. लेकिन, एक बात खास तौर पर रेखांकित करने योग्य है, वह यह है कि इस बार पुस्तक मेले में सोशल मीडिया पर सक्रिय लेखकों की जबरदस्त उपस्थिति रही. इसका परिणाम यह रहा कि इस बार पुस्तक मेले की ख़बरें लगातार फोटो समेत फेसबुक पर अपडेट होती रहीं. फेसबुकिया लेखकों में अपनी और साथी लेखकों की फोटो लगाने की होड़ दिखाई दे रही थी. सोशल मीडिया पर सक्रिय लेखकों ने हिंदी के वरिष्ठ और कनिष्ठ लेखकों के साथ अपनी दर्जनों फोटो लगाईं. अब इसके पीछे की मानसिकता अपनी प्रसिद्धि की चाहत भी हो सकती है. इस बात को लेकर भी चर्चा रही कि फेसबुक पर लिखने वालों ने पैसे देकर अपनी किताबें न केवल छपवाईं, बल्कि उन्हें विमोचित कराकर उनकी दर्जनों तस्वीरें फेसबुक पर लगाईं.

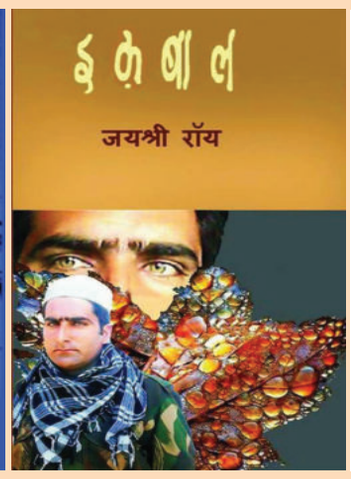

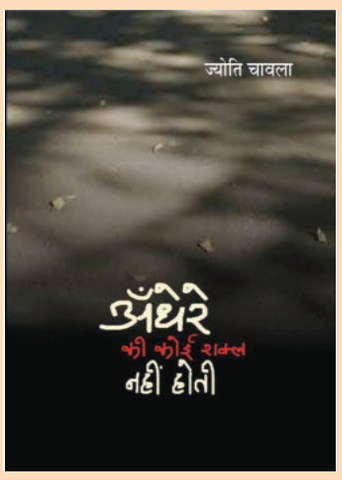

पुस्तक मेले में सामयिक प्रकाशन ने भी कई युवा लेखकों की किताबें जारी कीं. इसमें पूर्व पत्रकार एवं कवयित्री वर्तिका नंदा की किताब-ख़बर यहां भी.. के अलावा कहानीकार विवेक मिश्र का कहानी संग्रह-पार उतरना धीरे से और निर्मला भुराड़िया की किताब-गुलाम मंडी भी जारी हुई. गुलाम मंडी में निर्मला भुराड़िया ने देह व्यापार को केंद्र में रखा है.

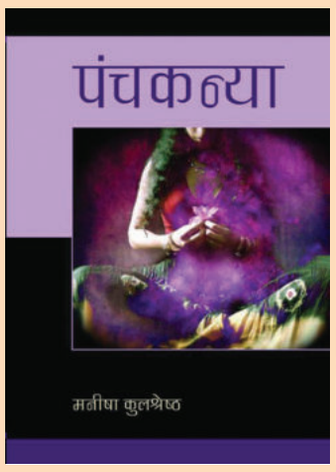

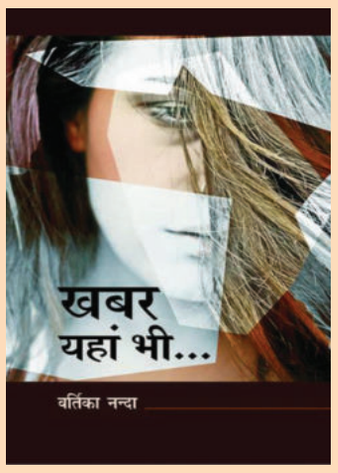

पुस्तक मेले में सामयिक प्रकाशन ने भी कई युवा लेखकों की किताबें जारी कीं. इसमें पूर्व पत्रकार एवं कवयित्री वर्तिका नंदा की किताब-ख़बर यहां भी.. के अलावा कहानीकार विवेक मिश्र का कहानी संग्रह-पार उतरना धीरे से और निर्मला भुराड़िया की किताब-गुलाम मंडी भी जारी हुई. गुलाम मंडी में निर्मला भुराड़िया ने देह व्यापार को केंद्र में रखा है. ज्ञानपीठ प्रकाशन से छपकर विमोचित हुआ. कविता के लिए यही पुरस्कार अरुणाभ सौरभ को उनके काव्य संग्रह-दिन बनने के क्रम में को दिया गया. इस मौक़े पर एक और नए लेखक आशुतोष का कहानी संग्रह-मरें तो उम्र भर के लिए भी विमोचित किया गया.

इस मौक़े पर बोलते हुए वरिष्ठ लेखकों एवं आलोचकों का मानना था कि इन युवा लेखकों ने अपनी रचनाओं से एक उम्मीद जगाई है. ज्ञानपीठ के अलावा आधार प्रकाशन, पंचकुला ने भी विश्व पुस्तक मेले में कई युवा लेखक-लेखिकाओं की किताबें जारी कीं. आधार प्रकाशन से प्रकाशित नई किताबों में मशहूर लेखिका जयश्री राय का नया उपन्यास-इकबाल भी है. कश्मीर की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास अपनी भाषा और शैली के जरिये हिंदी साहित्य में एक ताजा हवा के झोंके की तरह आता है. जिया और इकबाल के प्रेम संबंधों में एक अजीब तरह की कशमकश और छटपटाहट है. आधार प्रकाशन से ही कहानीकार अल्पना मिश्रा का नया उपन्यास-अन्हियारे तलछट में चमका, कविता का उपन्यास-ये दिये रात की ज़रूरत थे, वंदना शुक्ल की मगहर की सुबह और विमलचंद पांडे का उपन्यास भी प्रकाशित हुआ. इसके अलावा कहानीकार ज्योति चावला के कहानी संग्रह-अंधेरे की कोई शक्ल नहीं होती की भी पुस्तक मेले में खासी चर्चा रही.

पुस्तक मेले में सामयिक प्रकाशन ने भी कई युवा लेखकों की किताबें जारी कीं. इसमें पूर्व पत्रकार एवं कवयित्री वर्तिका नंदा की किताब-ख़बर यहां भी.. के अलावा कहानीकार विवेक मिश्र का कहानी संग्रह-पार उतरना धीरे से और निर्मला भुराड़िया की किताब-गुलाम मंडी भी जारी हुई. गुलाम मंडी में निर्मला भुराड़िया ने देह व्यापार को केंद्र में रखा है. सामयिक प्रकाशन से ही चर्चित लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ का उपन्यास-पंचकन्या भी जारी किया गया. कहानी संग्रहों और उपन्यासों के कोलाहल के बीच हरियाणा की युवा लेखिका निर्मल सिंह की एक किताब हरियाणा के लोकगीतों पर वाणी प्रकाशन से छपी है. निर्मल ने हरियाणा के 16 जिलों में तीन सौ लोगों से बातचीत करने के बाद यह किताब तैयार की है. किताबों की इस सूची के बीच यह बात भी रेखांकित करने योग्य है कि इन किताबों का प्रोडक्शन काफी अच्छा है. शिल्पायन प्रकाशन से बिंदिया पत्रिका की संपादक गीताश्री की फिल्मों पर संपादित किताब-हिंदी सिनेमा, दुनिया से अलग दुनिया भी छपकर आई. इस किताब में अजय ब्रह्मात्मज, सैबाल चटर्जी, आशुतोष, नम्रता जोशी, फिल्म पत्रिका माधुरी के पूर्व संपादक विनोद तिवारी, रवींद्र त्रिपाठी और दीपक दुआ समेत कई नामचीन हस्तियों द्वारा फिल्मों पर लिखे आलेख हैं. अपने कहानी संग्रह-प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियां से हिंदी साहित्य को झकझोरने वाली लेखिका गीताश्री की इस किताब में सिनेमा के अनेक पहलुओं को गंभीरता से सामने लाया गया है.

उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इन युवा लेखकों की किताबों पर हिंदी में गंभीर चर्चा होगी. दिल्ली के इस पुस्तक मेले में इतनी बड़ी संख्या में युवा लेखकों की किताबों का प्रकाशन आश्वस्तिकारक है. ज़रूरत इस बात की है कि प्रकाशन इन किताबों को पाठकों तक पहुंचाने का यत्न करें. अगर प्रकाशकों ने इन्हें पाठकों तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई, तो इससे साहित्य का बहुत अहित होगा. ■

(लेखक आईबीएन-7 में डिप्टी एडिटर हैं)

anant.ibn@gmail.com

कविताएं

क्या कहें!

बबीता

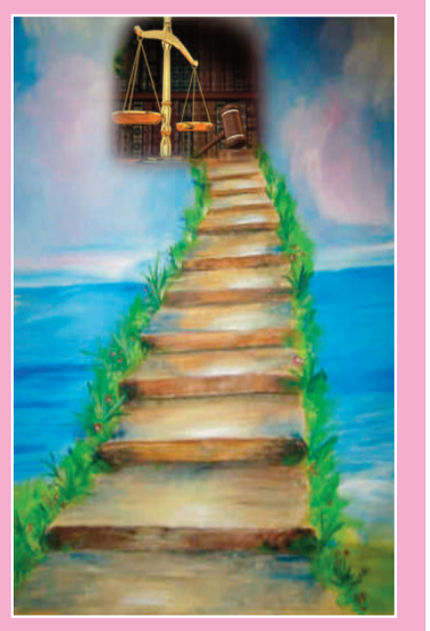

कहीं कोई घटना घटी
बैठक की, समीक्षा हुई
बन गई कमेटी
कड़ी जांच के आदेश मिले
दिन, महीने, साल लगे
जनता को आश्वासन मिला
मिलेगा न्याय.
पर, हाय!
क्या कहें!
यह सिलसिला कभी रुकता
नहीं
निरंतर चलता रहता
पीढ़ी-दर-पीढ़ी
पर मिलती नहीं
घटना रोकने की सीढ़ी.

-समस्तीपुर, बिहार.

feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक	लेखक
...और मेघ बरसते रहे	रंजना जायसवाल
प्रकाशक	**मूल्य**
सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली	मूल्य-250 रुपये

रंजना जायसवाल का यह पहला, किंतु बेहद पठनीय उपन्यास है. यहां स्त्री के दु:खों-तकलीफों के अनेक स्तर कथा में खुलते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुख्य पात्र नोरा एक ऐसा परिपक्व चरित्र है, जो इन दु:खों की कथा में विगलित होकर नहीं रह जाता है. वह उसके कारणों की खोज करते हुए जहां पुरुष समाज पर व्यंजनात्मक टिप्पणी करता है, वहीं स्त्री की महत्ता को रेखांकित भी करता है. निजी दु:ख को विस्मृत कर यह चरित्र स्त्री और दु:ख के क़रीबी रिश्ते की पहचान करते हुए प्रश्न करता है, आख़िर स्त्री अपने हर रूप में पुरुष से दु:ख ही क्यों पाती है? पुरुष आख़िर ऐसा क्यों हो जाता है स्त्रियों के लिए? क्यों पुरुष अहंकारी और शोषक हो गया है? क्यों उसे एक अकेली स्त्री महज एक देह लगने लगती है? नदी की तरह है इस उपन्यास की नायिका नोरा, जिसमें अनेक स्त्री धाराएं सम्मिलित हो गई हैं.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई-मेल: feedback@chauthiduniya.com

किताब समीक्षा

संघर्ष की एक ईमानदार कथा

एस. बिजेन सिंह

32 वर्षीय एम सी मैरी कॉम की आत्मकथा-अनब्रिकेबल:एन ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई. आश्चर्य भी महसूस हुआ, क्योंकि मैरी कोम ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हैं. वह केवल बॉक्सिंग की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कोई लेखिका नहीं, जिसने साहित्य के क्षेत्र में कभी काम किया हो. बावजूद इसके, कई यादगार लम्हों को समेट कर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जो क़ाबिले तारीफ है. इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता ईमानदार लेखन, साहस के साथ अपनी बात कहना, बॉक्सिंग को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करना और उसे आने वाली पीढ़ियों की खातिर लोकप्रिय बनाने की उनकी कोशिश है. एक बॉक्सर बनने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, यह बात किताब पढ़ते समय बखूबी मालूम हुई. उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

मैरी कॉम मानती हैं कि खेल ही सबको प्यार में बांध सकता है. वह अपनी जाति कोम और जन्मस्थल मणिपुर को बेहद प्यार करती हैं. एक मां होने की ज़िम्मेदारियां, पति के साथ ईमानदार रिश्ते, खेल में राजनीतिक दबाव, मणिपुर का अशांत माहौल एवं समस्याएं उनकी आत्मकथा के हिस्से हैं. यह किताब पढ़कर पता चलता है कि उनके अंदर कितना साहस, सकारात्मक सोच और धैर्य है. वह विश्व महिला बॉक्सिंग में पांच बार चैंपियन रहीं और लंदन ओलंपिक 2012 में उन्हें कांस्य पदक मिला. अर्जुन अवॉर्ड एवं पद्मभूषण से सम्मानित मैरी कॉम के जीवन पर आधारित यह किताब युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेगी, उन्हें मेहनत करने की प्रेरणा देगी. मैरी कॉम की सफलता की यह कहानी अभी अंग्रेजी में आई है, इसे अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले.

मैरी कॉम मणिपुर के चुड़ाचांदपुर जिले के सागां नामक स्थान पर 22 नवंबर, 1982 को जन्मी थीं. कोम उनकी जाति है. ईसाई धर्म को मानने वाली मैरीकोम की सफलता का मंत्र है, आई मस्ट विन दिस बाउट, आई मस्ट विन, आई मस्ट विन. इस मंत्र को जपते हुए वह पहले प्रार्थना करती हैं, तब खेलना शुरू करती हैं. हर बार खेलने से पहले वह सोचती हैं कि विरोधी खिलाड़ी भी इंसान है. मेरी तरह उसके भी दो हाथ और दो पांव हैं, इसलिए मैं क्यों डरूं. मैरी कॉम का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा. एक निर्धन परिवार में जन्म होने की वजह से उन्हें अभाव में रहना पड़ता था.

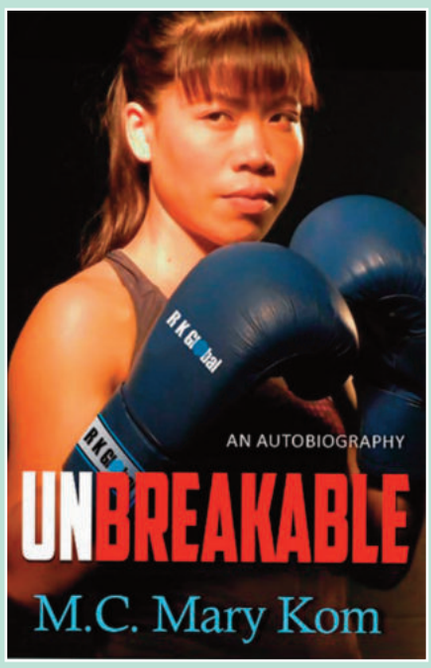

समीक्ष्य कृति:
अनब्रिकेबल:एन ऑटोबायोग्राफी

लेखक :
एम सी मैरी कॉम

प्रकाशक :
हार्पर कॉलिन्स

मूल्य :
199/- रुपये

लेकिन, इंसान अभाव में ही बहुत कुछ कर सकता है, यह बात मैरी कॉम ने साबित कर दिखाई. वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं. उनके पिता मांगते तोनपा कोम एक भूमिहीन किसान हैं. बाद में मैरी कॉम की नौकरी लगने के बाद जमीन खरीदी गई. मैरी कॉम के पिता पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मोइरांग के कांगाथै के मुखिया के पास काम करने आ गए. उस वक्त मैरी कोम केवल पांच महीने की थीं. उनके पिता वहां 10 साल से काम कर रहे थे. मुखिया ने थोड़ी सी जमीन उन्हें दी, जिस पर उन्होंने एक झोंपड़ीनुमा घर बनाया. मैरी कोम खेती-बारी का काम भी करती थीं.

उनके पिता ने लोकताक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल में उनका दाखिला कराया. यह वहां का सबसे अच्छा स्कूल था. रोज एक घंटा पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था. उसके बाद सेंट जेवियर्स स्कूल में सातवीं कक्षा में दाखिला लिया. स्कूल के खेलकूद में हमेशा आगे रहती थीं. खेलों में उनकी विलक्षण प्रतिभा स्कूल के अध्यापकों को पता थी. बाद में 1999 में इंफाल के साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आकर खेलने लगीं. 16-17 की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह खेलना शुरू किया. उस वक्त राज्य में महिलाओं का बॉक्सिंग में आना भी शुरू नहीं हुआ था. मैरी कॉम को शुरुआती शिक्षक मिले इबोमचा, जिन्होंने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी.

मैरी कॉम की शादी ओनलर के साथ मार्च 2005 में हुई. दोनों के रिश्ते और शादी किसी परिकथा से कम नहीं हैं. मैरी तो केवल खेलने में व्यस्त थी. ट्रेनिंग लेने में अधिकतर समय बिताती थी. शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था. लोगों से घुलने-मिलने, दोस्ती करने का भी समय नहीं मिलता था. ट्रेनिंग में शामिल खिलाड़ियों को ही वह अपना दोस्त मानती थीं. ओनलर के साथ दिल्ली में पहली मुलाकात हुई. ओनलर विधि के विद्यार्थी और दिल्ली के कोम-रेम स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं. ट्रेनिंग के दौरान एक दिन ओनलर मैरी से मिलने आए. उसी दिन जान-पहचान हुई. कुछ दिनों बाद ओनलर ने मैरी से शादी का प्रस्ताव रखा. मैरी को आश्चर्य हुआ. ओनलर मैरी के जीवनसाथी बनना चाहते थे. ओनलर ने कहा, आई वांट टू प्रोटेक्ट योर करियर एंड डेट इस वन ऑफ द मेइन रीजन्स फॉर माई प्रोपजल. मैरी अस्वीकार नहीं कर सकती थीं. मैरी ने हां कह दी. दोनों की शादी हो गई. यह शादी एक आदर्श शादी थी. अब तीन बच्चे भी हैं. यही सब कुछ उन्होंने अपनी आत्मकथा में समेटा है.

मैरी कॉम ने अपने खेल के माध्यम से मणिपुर, भारत और अपनी जाति कोम का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया. मणिपुर की एक साधारण महिला का साहस पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा. खेल के क्षेत्र में मैरी कोम का एक बड़ा हिस्सा है. मैरी कॉम का एकमात्र सपना है, उनके द्वारा पूर्वोत्तर के लिए स्थापित बॉक्सिंग एकेडमी (एम सी मैरी कोम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन) को विकसित करना. सरकार ने उन्हें जमीन दी है और देश-विदेश से सहायता भी मिल रही है. इस एकेडमी में ग़रीब खिलाड़ियों को बॉक्सिंग नि:शुल्क सिखाई जाती है. इस समय 30 से ज़्यादा छात्र एकेडमी में हैं. एक छात्र को 600 रुपये महीने वजीफा दिया जाता है. मैरी कोम को 2016 में रिओ (ब्राजील) में होने वाले वर्ल्ड ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलने की उम्मीद है और वह इसके लिए खूब मेहनत भी कर रही हैं. मैरी, हमें तुम्हारी सफलता का इंतजार है. ■

sbijensngh@gmail.com

> जेएम–2400 में 2.4 इंच का रंगीन डिस्प्ले है, जो स्क्रीन पर कंटेट को स्पष्ट और विस्तार से दिखाता है. इसका डिजिटल कैमरा आपको आकर्षित करेगा, जो यादगार पलों को कैद और पिक्चर परफेक्ट शॉट्स के साथ रिकॉर्ड करने की आज़ादी देता है. इसमें एक वीडियो प्लेयर भी है.

माइक्रोमैक्स का नया टैबलेट

माइक्रोमैक्स ने एक नया टैबलेट लॉन्च किया है. इसे ऑनलाइन स्टोर्स से खरीद सकते हैं. यह भारत में लॉन्च हुए सस्ते टैबलेटों को कड़ी टक्कर दे सकता है. फनबुक पी280 में एंड्रॉयड जेलीबीन 4.2.2 ऑपरेटिंग सिस्टम है. अगर आप कम क़ीमत में टैबलेट खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इस टैबलेट में कोर्टेक्स 8 सिंगल कोर प्रोसेसर है, जिसकी स्पीड एक गीगाहर्ट्ज की है. टैबलेट में 512 एमबी रैम है. टैबलेट में 7 इंच की टीएफटी एलसीडी स्क्रीन है. यह टैबलेट 800 गुणा 480 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आता है. अगर आपको अच्छे कैमरे के साथ कोई टैबलेट चाहिए, तो इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते. इस टैबलेट में सिर्फ़ 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो फ्रंट साइड में है. कोई भी रियर कैमरा नहीं है. माइक्रोमैक्स का यह नया टैबलेट 4 जीबी इंटरनल मेमोरी देता है. इसके अलावा मेमोरी 32 जीबी तक कार्ड की मदद से बढ़ाई जा सकती है. इस टैबलेट में यूएसबी पोर्ट, वाई–फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस और 3जी फीचर मौजूद हैं. इसमें सबसे बड़ी खामी है कम बैटरी. टैबलेट में 2400 एमएच बैटरी है. आजकल आने वाले स्मार्ट फोन में भी इससे ज़्यादा पावर वाली बैटरी देखी जा सकती है. कंपनी का दावा है कि यह 250 घंटों का स्टैंडबाय टाइम देती है. ■

पैनासोनिक के फोन

पैनासोनिक ने हाल में ईजेड–180 और ईजेड–240 नामक अपने दो नए फोन लॉन्च किए हैं. इन दोनों फोनों की क़ीमत 2000 रुपये से कम होगी. इनमें से ईजेड–180 की क़ीमत 1350 रुपये है और ईजेड–240 की कीमत 1790 रुपये. इनमें हिंदी फॉन्ट हैं. ईजेड–180 और ईजेड–240 फोन में मोबाइल ट्रैकर एप्लिकेशन भी है. इसके अलावा दोनों फोन अल्फान्यूमैरिक की–बोर्ड सपोर्ट करते हैं. स्क्रीन का अंतर छोड़कर दोनों फोन लगभग एक जैसे दिखते हैं.■

फीचर्स: अल्फान्यूमैरिक की–बोर्ड, प्राइमरी कैमरा, कार्ड की मदद से 16 जीबी तक मेमोरी बढ़ाने की सुविधा, जीपीआरएस, ब्लूटूथ, एलइडी टॉर्च, फोन से अलग हो जाने वाली बैटरी.

ईजेड–240

इस फोन में आपको मिलेगी 2.4 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन. इसी के साथ है 1.3 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा. 1200 एमएच की बैटरी है. यह फोन ग्रे, ब्लू, व्हाइट कलर में उपलब्ध है. एफएम रिकॉर्डिंग और एलइडी टॉर्च जैसे लगभग सभी बेसिक फीचर्स इसमें मौजूद हैं.

ईजेड–180

एन–180 में 1.8 इंच की स्क्रीन है. इसी के साथ है 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा. भारतीय कैलेंडर के साथ इस फोन में 1000 एमएच की बैटरी है, जो काफी देर तक चल सकती है.

सैमसंग की वॉटरप्रूफ स्मार्ट वॉच

बार्सिलोना (स्पेन) में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इवेंट में सैमसंग ने गैलेक्सी गियर–2 और गियर–2 निओ स्मार्ट वॉच लॉन्च की है. ये दोनों स्मार्ट वॉच नए ऑपरेटिंग सिस्टम टाईजेन (ढळशप) पर काम करती हैं, लेकिन यह अचंभित करने वाला है कि सैमसंग की तरफ़ से इस बार एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोडक्ट में नहीं है. ग़ौरतलब है कि पिछले कुछ समय से सैमसंग ने इंटेल के साथ मिलकर नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना शुरू किया था. सैमसंग ने इससे पहले अपनी गैलेक्सी सीरीज के सभी गैजेट्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किए.

सैमसंग की गैलेक्सी गियर–2 और गियर–2 निओ दोनों स्मार्ट वॉच में एक जैसे फीचर्स हैं. इनमें 3000 एमएच की बैटरी है. कंपनी का कहना है कि यह बैटरी 2–3 दिन चलेगी.

सैमसंग की गैलेक्सी गियर–2 और गियर–2 निओ दोनों स्मार्ट वॉच में एक जैसे फीचर्स हैं. इनमें 3000 एमएच की बैटरी है. कंपनी का कहना है कि यह बैटरी 2–3 दिन चलेगी. अगर कम इस्तेमाल करते हैं, तो यह 6 दिनों तक काम करती है. खास बात यह है कि गैलेक्सी गियर–2 में 2 मेगापिक्सल कैमरा और ऑटोफोकस फीचर है. कनेक्टिविटी के मामले में दोनों स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ वर्जन 4.0 के साथ आती हैं. इनमें आईआरलेड भी है. दोनों स्मार्ट वॉच वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ हैं. ब्लूटूथ फीचर की मदद से यूजर को फोन रिसीव करने की सुविधा है. गियर–2 स्मार्ट वॉच ब्लैक, ब्राउन, ऑरेंज कलर में हैं.

खास बातें: 1.63 इंच की सुपर मोलेड स्क्रीन, 320 गुणा 320 पिक्सल का रेजोल्यूशन, 1.0 गीगाहर्ट्ज के डुअल कोर प्रोसेसर, 512 एमबी रैम, 4 जीबी की इंटरनल मेमोरी.

फिटनेस फीचर्स: हार्ट रेट सेंसर, पेडोमीटर, मोड्स ऑफर रनिंग ऐप, साइकिलिंग ऐप, एक्सिलोमीटर. ■

सुजूकी के चार नए मॉडल्स

सुजूकी मोटर्स ने लड़के एवं लड़कियों, दोनों को ध्यान में रखते हुए ऑटो एक्सपो में 3 पावरफुल बाइक्स और एक शानदार स्कूटर लॉन्च किए. कंपनी ने वी स्टॉर्म–1000 नामक बाइक प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च की. दूसरी बाइक को गिक्सर और तीसरी को इनाजुमा नाम दिया गया है. कंपनी ने लड़कियों के लिए खास एक लेट्स (श्रशी) नामक स्कूटर भी लॉन्च किया है.

कंपनी ने वी स्टॉर्म–1000 नामक बाइक प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च की. दूसरी बाइक को गिक्सर और तीसरी को इनाजुमा नाम दिया गया है.

सुजूकी प्रीमियम बाइक वी स्टॉर्म–1000

4 स्ट्रोक वाला लिक्विड कूल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक एग्निशन, पावर–1000 सीसी, फ्रंट ब्रेक, डिस्क ब्रेक, फ्रंट में ट्विन ब्रेक, लंबाई 2.28 मीटर, चौड़ाई 865 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लीयरेंस 165 एमएम, वजन 228 किलो, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 20 लीटर, डिस्प्लेसमेंट 1037 सेमी क्यूब. कंपनी ने यह बाइक भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दी है. इसकी क़ीमत है 14.5 लाख रुपये.

गिक्सर

4 स्ट्रोक का एक सिलेंडर वाला एयरकूल इंजन, क़ीमत लगभग डेढ़ लाख रुपये, डिस्प्लेसमेंट 155 सेमी क्यूब, स्टार्ट इलेक्ट्रिक एवं किक दोनों, पावर 155 सीसी, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक.

इनाजुमा

4 स्ट्रोक 2 सिलेंडर, लिक्विड कूल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक एग्निशन,

पॉवर 50 सीसी, डिस्प्लेसमेंट 248 सेमी क्यूब, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर, फ्यूल कैपेसिटी 13.3 लीटर, 183 किलोग्राम.

स्कूटर लेट्स

4 स्ट्रोक एक सिलेंडर, पावर 110 सीसी, सेल्फ स्टार्ट और मेंटनेंस फ्री बैटरी, वजन 98 किलो, फ्यूल कैपेसिटी 5.2 लीटर, ड्रम ब्रेक, 112.8 सेमी क्यूब का डिस्प्लेसमेंट. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर 63 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है.■

भारत का पहला 150 सीसी ऑटोमैटिक स्कूटर

मल्टी शेड्स के साथ एलएमएल स्टार यूरो सात अलग–अलग रंगों में मौजूद है. इस स्कूटर की क़ीमत 54,014 रुपये से लेकर 59,422 रुपये तक है.

देश की पुरानी टू व्हीलर कंपनी लोहिया मोटर्स लिमिटेड (एलएमएल) ने दुनिया और भारत का पहला 150 सीसी क्षमता वाला स्कूटर लॉन्च किया है. यह भारत का पहला पूरी तरह मेटल बॉडी और यूनिक मल्टी कलर वाला स्कूटर है. मल्टी शेड्स के साथ एलएमएल स्टार यूरो सात अलग–अलग रंगों में मौजूद है. इस स्कूटर की क़ीमत 54,014 रुपये से लेकर 59,422 रुपये तक है.

स्टार यूरो 150 के फीचर्स: लंबाई 1,760 एमएम चौड़ाई 695 एमएम ऊंचाई 820 एमएम, व्हीलबेस 1260 एमएम, रोड क्लियरेंस 160 एमएम, फ्यूल टैंक 7 लीटर, माइलेज 55 किमी प्रति लीटर, सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, फोर्स्ड एयरकूल्ड इंजन–9.38 एचपी पावर, 90 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार,इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ डिस्क ब्रेक का विकल्प, इंजन किल स्विच.

एलएमएल स्टार यूरो–150 ऑटोमैटिक स्टैंडर्ड की क़ीमत 54,014 रुपये, एलएमएल स्टार यूरो–150 ऑटोमैटिक फ्रंट डिस्क ब्रेक सहित क़ीमत 57,918 रुपये और एलएमएल स्टार यूरो–150 ऑटोमैटिक फ्रंट डिस्क ब्रेक और मल्टी कलर शेड्स, क़ीमत 59,422 रुपये. ■

जोश का जेएम–2400

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जोश मोबाइल्स ने अपना जेएम–2400 बार फोन लॉन्च किया है. जोश मोबाइल श्रृंखला की यह नवीनतम पेशकश है. यह अपने 3डी यूजर इंटरफेस एवं प्रभावशाली स्पीकर्स के माध्यम से यूजर्स को रोमांचित करेगा. यह लाइव वॉलपेपर्स इंस्टॉल करने में सक्षम है. इसमें ड्यूल सिम, ड्यूल बैंड सपोर्टिंग डिवाइस है. जेएम–2400 में 2.4 इंच का रंगीन डिस्प्ले है, जो स्क्रीन पर कंटेट को स्पष्ट और विस्तार से दिखाता है. इसका डिजिटल कैमरा आपको आकर्षित करेगा, जो यादगार पलों को कैद और पिक्चर परफेक्ट शॉट्स के साथ रिकॉर्ड करने की आज़ादी देता है. इसमें एक वीडियो प्लेयर भी है. इसका 8 जीबी विस्तार योग्य मेमोरी कार्ड सपोर्ट म्यूजिक फाइल्स, तस्वीरें एवं वीडियो स्टोर करने में सक्षम है, जिसे फोन पर ब्लूटूथ के सिंगल क्लिक से आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है. इसमें 2400 एमएएच की पॉवरफुल बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 600 मिनट का टॉक टाइम और 350 घंटे का स्टैंडबाय देती है. एक बिल्ट इन टॉर्च है, जिसका इस्तेमाल आपात समय में किया जा सकता है. जेएम–2400 अपने बिल्ट इन एफएम के साथ आपका मनोरंजन असीमित करता है. फोन में बिल्ट इन जीपीआरएस सपोर्ट भी मौजूद है. जेएम–2400 काले, सिल्वर एवं लाल रंग में उपलब्ध है और इसकी क़ीमत मात्र 1,499 रुपये है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

7 इंच स्क्रीन वाला टैबलेट आकाश–4

ग़रीब छात्रों एवं अन्य लोगों तक आईटी की पहुंच बनाने के लिए तैयार किया गया स्वदेशी आकाश टैबलेट का नया वर्जन आकाश–4 अगले महीने बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा. इसकी क़ीमत होगी 3,999 रुपये. यह जानकारी देते हुए दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया कि टैबलेट के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं.

खूबियां: 7 इंच की स्क्रीन, स्क्रैच रेसिस्टेंट कैपेसिटी वाली टच स्क्रीन, वाई–फाई, 2जी, 3जी एवं 4जी नेटवर्क से कनेक्टिविटी, 32 जीबी तक एक्सटर्नल मेमोरी वाला स्टोरेज कार्ड, फ्रंट कैमरा.■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

टीम इंडिया का भार

क्या उठा पाएंगे कोहली

क्या भारतीय क्रिक्रेटटीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी से हटाने और विराट कोहली को टीम की कमान सौंपने का सही वक्त आ गया है? क्या कोहली के कंधे इतने मजबूत हो गए हैं कि वह सवा अरब लोगों की आशाओं का बोझ अपने कंधों पर ले कर चल सकें? क्या कोहली खुद को एक सफल बल्लेबाज के साथ-साथ एक सफल कप्तान साबित कर पाएंगे? चूंकि सवाल भारत में धर्म का दर्जा रखने वाले क्रिक्रेट का है, इसलिए इन सवालों का जवाब बेहद जरूरी है.

वर्तमान में भारतीय टीम में धोनी का विकल्प एकमात्र विराट कोहली ही हैं. कोहली के पास जूनियर लेवल पर कप्तानी करने का अनुभव है और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी उम्र भी कप्तान बनने के लिए सही है. वह एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं. साथ ही वह विदेशी पिचों पर भी रन बना रहे हैं. टीम इंडिया के विदेशी पिचों पर और बेहतर प्रदर्शन करने की आशा है. इसके लिए एक ऐसे कप्तान की भी जरूरत है, जो विदेशी पिचों पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर सके. साथ ही गेंदबाजों को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी कर सके.

नवीन चौहान

विदेशी धरती पर मिल रही लगातार हार टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए परेशानी की वजह बन गई है. उनका सिंहासन डोल रहा है. ऊपर से आईपीएल-6 का फिक्सिंग विवाद भी उनके गले की फांस बनता जा रहा है. उन्हें टेस्ट कप्तान के पद से हटाने के लिए चौतरफा दबाव भी बनाया जा रहा है. समर्थक उन्हें टेस्ट कप्तानी छोड़ एकदिवसीय और टी-20 मैचों में ध्यान केंद्रित करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि आलोचक कैप्टन कूल (धोनी) की जगह करेजियस कोहली को तत्काल टीम इंडिया का कप्तान बनाने की पैरवी कर रहे हैं. क्या भारतीय क्रिक्रेट टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी से हटाने और विराट कोहली को टीम की कमान सौंपने का सही वक्त आ गया है? क्या कोहली के कंधे इतने मजबूत हो गए हैं कि वह सवा अरब लोगों की आशाओं का बोझ अपने कंधों पर लाद सकें ? क्या कोहली खुद को एक सफल बल्लेबाज के साथ-साथ एक सफल कप्तान साबित कर पाएंगे? चंकि सवाल भारत में धर्म का दर्जा रखने वाले क्रिक्रेट का है, इसलिए इन सवालों का जवाब बेहद जरूरी है.

टीम इंडिया के कप्तान को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था. इन अटकलों के बीच धोनी के घायल होने और एशिया कप के लिए टीम की कमान कोहली को सौंपे जाने को महज एक संयोग ही कहा जाएगा. यदि एशिया कप जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भारत को जीत की पटरी पर वापस लाने में कार्यकारी कप्तान विराट कोहली सफल होते हैं तो यह उनके लिए भारत का कप्तान बनने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. श्रीलंका और चिर प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तान जैसी टीमों के सामने वह किस तरह की कप्तानी करते हैं. कोहली धोनी की अनुपस्थिति में मैदान में किस तरह के निर्णय लेते हैं, यह देखना बेहद रोचक होगा. एशिया कप के पहले मैच में मेजबान बांग्लादेश के खिलाफ कप्तानी शतक लगाकर कोहली ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह टीम इंडिया की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वह खुद को एक बेहतर कप्तान साबित करने के इस मौके को खाली नहीं जाने देंगे. सचिन, गंभीर, सहवाग जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी में जिस तरह कोहली ने धीरे-धीरे टीम में अपनी जगह बनाई, उसी तरह वह टीम के कप्तान बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. युवा कोहली को टीम में जगह पाने के लिए किसी न किसी सीनियर खिलाड़ी के चोटिल होने का इंतजार करना पड़ता था. चोट और फॉर्म से जूझते सीनियर खिलाड़ियों के टीम से बाहर होते ही कोहली ने अंगद की तरह टीम में अपना पैर जमा लिया और धीरे-धीरे टीम की रीढ़ बन गए. जिस तरह टीम इंडिया नब्बे के दशक में पूरी तरह सचिन तेंदुलकर पर निर्भर हो गई थी, आज टीम इंडिया एक बार फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है. यहां फर्क सिर्फ इतना है कि सचिन की जगह विराट ने ले ली है. टीम की जीत हो या हार, दोनों ही स्थिति में मैदान में केवल विराट का बल्ला ही लगातार हल्ला बोलता दिखाई देता है.

कप्तानी विराट के लिए कोई नया काम नहीं है. विराट ने भारतीय टीम को 2008 में मलेशिया में हुए अंडर-19 विश्व कप में अपनी बल्लेबाजी और बेहतरीन कप्तानी के बल पर खिताब दिलवाया था. इसके बाद आईपीएल के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें खरीदा था. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मालिक विजय माल्या ने विराट को टीम में शामिल करने पर कहा था कि कप्तान टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है, इसलिए उन्होंने कोहली को अपनी टीम में शामिल कर लिया. आईपीएल के पांचवें सीजन में विराट को अस्थाई तौर पर डेनियल विटोरी की जगह कप्तानी सौंपी गई और छठवें सीजन में वह स्थाई तौर पर टीम के कप्तान बन गए. कोहली बहुत ही समझदार और परिपक्व खिलाड़ी हैं. वह मैदान में भले ही बहुत आक्रामक दिखाई पड़ते हों, लेकिन उनके निर्णय बहुत ही सूझ-बूझ भरे होते हैं. विराट की कप्तानी से प्रभावित होकर आरसीबी के कोच रे जेनिंग्स ने उनकी तुलना ऑस्ट्रेलियाई कप्तानों से की थी और कहा था कि विराट आगे चलकर एक बेहतरीन कप्तान साबित होंगे. आम तौर पर भारतीय बहुत ही विनम्र और शांत होते हैं. विराट एक आम भारतीय नौजवान नहीं हैं, वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तरह एग्रेसिव (आक्रामक) हैं और आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना करते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें जिम्मेदारी लेना पसंद है. वह लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूरा करने की जी-तोड़ कोशिश करते हैं. वह इसके लिए अपने साथी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करते हैं. वह कप्तान बनने की राह में भले ही धीमी गति से चल रहे हों, लेकिन उनकी दिशा और दशा सौ फीसद सही है. उन्हें खुद को एक बेहतर कप्तान साबित करने के लिए जो भी मौके मिले हैं, उन्होंने उसे किसी भी सूरत में खाली नहीं जाने दिया. पिछले साल जिम्बाब्वे दौरे के लिए सुरेश रैना के टीम में रहते हुए विराट कोहली को टीम की कमान सौंपी गई, जबकि पिछले जिम्बाब्वे दौरे के लिए रैना को कप्तान बनाया गया था और रैना ने बतौर कप्तान जीत दिलाने में भी सफल रहे थे. बावजूद इसके उनकी जगह कोहली को कप्तान बनाया गया. कोहली ने हाथ आए इस मौके को भी खाली नहीं जाने दिया. जिम्बाब्वे को उनकी जमीन पर 5-0 के अंतर से मात देने वाले कोहली पहले भारतीय कप्तान भी बने. कोहली ने खुद को बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों मामलों में अन्य खिलाड़ियों के मुकाबले बीस साबित किया.

हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयान चैपल ने ईएसपीएन क्रिकेट इनफो वेबसाइट में प्रकाशित हुए अपने एक लेख में कहा कि धोनी को टेस्ट कप्तानी से हटा देना चाहिए. धोनी को वर्ष 2011-12 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे में मिली शर्मनाक हार के बाद ही टेस्ट कप्तानी से हटा दिया जाना चाहिए था. उनकी टीम विदेशी धरती पर लगातार आठ टेस्ट मैंचों में हार चुकी थी और कैप्टन कूल (धोनी) एक आम कप्तान साबित हो रहे थे. उस खराब दौर में बतौर कप्तान वह टीम में उत्साह नहीं भर पा रहे थे. वह एक ऐसे असहाय कप्तान नजर आ रहे थे जो कि बहाव के साथ बहा चला जा रहा था. इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि टीम हार रही हो, तब एक बेहतर से बेहतर कप्तान भी बहुत लंबे समय तक अपने पद पर नहीं बना रह सकता है. धोनी को टेस्ट कप्तानी से हटाने और कोहली को कप्तान बनाने का वक्त आ गया है.

वर्तमान में भारतीय टीम में धोनी का विकल्प एकमात्र विराट कोहली ही हैं. कोहली के पास जूनियर लेवल पर कप्तानी करने का अनुभव है और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी उम्र भी कप्तान बनने के लिए सही है और वह एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं. साथ ही वह विदेशी पिचों पर भी रन बना रहे हैं. टीम इंडिया के विदेशी पिचों पर और बेहतर प्रदर्शन करने की आशा है. इसके लिए एक ऐसे कप्तान की भी जरूरत है, जो विदेशी पिचों पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर सके. साथ ही गेंदबाजों को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी कर सके.

आज कोहली अपने क्रिकेट करियर के चरम पर हैं. वह हर दूसरे दिन क्रिकेट के मैदान पर एक नया धमाका कर देते हैं. नब्बे के दशक में सचिन तेंदुलकर भी कुछ ऐसा ही करते थे. सचिन तेंदुलकर अकेले करोड़ों भारतीयों की आशाओं का बोझ अपने कंधे पर लेकर चल रहे थे. उस वक्त मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय टीम के कप्तान थे. सचिन तेंदुलकर को भारतीय टीम का उपकप्तान बना दिया गया. लोग उन्हें भविष्य के कप्तान के रूप में देख रहे थे. सचिन अपने बल्ले से लगातार आग उगल रहे थे. भारतीय टीम की असफलता और सचिन की सफलता एक साथ आगे बढ़ रही थी. अजहरुद्दीन भारत को सबसे ज्यादा जीत दिलाने वाले कप्तान भी थे. जिस तरह धोनी भारत की सफलता का नया अध्याय लिख रहे हैं, कोहली उनके सबसे महत्वपूर्ण हथियार और उपकप्तान के रूप में उनकी मदद कर रहे हैं. वर्ष 1996 में सचिन तेंदुलकर को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था. सचिन कप्तानी का भार नहीं संभाल सके. उनकी कप्तानी के दौरान टीम इंडिया को आए दिन हार का मुंह देखना पड़ता था. भारतीय टीम घर की शेर बनी रही. वह विदेशी जमीं पर एक अदद जीत के लिए तरस रही थी. जीत नहीं हुई. आखिरकार सचिन ने कप्तानी छोड़ दी. कोई विकल्प नहीं होने की वजह से अजहरुद्दीन को फिर से टीम का कप्तान बना दिया गया. कहीं कप्तानी के बोझ तले कोहली भी सचिन सिंड्रोम से ग्रसित न हो जाएं. हमारे हाथ से एक बेहतर कप्तान की तलाश में एक बेहतरीन खिलाड़ी भी न चला जाए. वह भी तब, जब वह अपने खेल के चरम पर है और शतक दर शतक बनाकर टीम को सशक्त करने में प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है. कोहली पर सचिन की तरह कप्तानी का दबाव नज़र नहीं आता है, बल्कि उनका खेल दबाव में और ज्यादा निखर जाता है. एकदिवसीय मैंचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए उनके द्वारा बनाए गए 13 मैच जिताऊ शतक इस बात की पुष्टि करते हैं.

कोहली की बेहतरीन कप्तानी पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि विराट एक अलग तरह का लीडर है. वह सामने से नेतृत्व करने वालों में से है. वह एक ऐसा खिलाड़ी है, जो बल्ले के साथ-साथ अपनी बेहतरीन फील्डिंग से भी टीम के लिए योगदान करता है. उसमें वह सब कुछ है, जो एक बेहतर कप्तान में होना चाहिए. कोहली ने अब तक जिस तरह की कप्तानी की है, उसमें वह बहुत ही सहज दिखाई दिए. उन्होंने बहुत परिपक्वता दिखाई है. एक कप्तान के रूप में वह और अधिक जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हैं. एशिया कप के लिए कप्तान बनाए जाने के बाद विराट कोहली ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैं कप्तान बनने की जिम्मेदारियां और चुनौतियां समझता हूं. मैं इस टूर्नामेंट में मिली कप्तानी की जिम्मेदारी को लेकर बहुत उत्साहित हूं. इसके बाद यह भी पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूं. उनका यह वकतव्य बहुत ही आत्मविश्वास भरा है और यह दर्शाता है कि वह कप्तान के रूप में टीम इंडिया की जिम्मेदारी संभालने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार हैं. बतौर कप्तान उनका किया गया प्रदर्शन भी उन्हें कप्तान बनाए जाने की ओर ही संकेत करता है. एशिया कप से पहले तक कोहली ने बतौर कप्तान 8 मैचों में 66.4 के औसत से रन बनाए थे, जो उनके एकदिवसीय करियर बल्लेबाजी औसत 51.85 से कहीं ज़्यादा है. अब तक विराट कप्तान की भूमिका में दो शतक भी बना चुके हैं.

महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी के बल पर भारत को दुनिया की नंबर एक टीम बनाने में अहम योगदान दिया. उनकी कप्तानी में भारत टी-20 और एक दिवसीय मुकाबलों में विश्व चैंपियन बना. साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में भी सफल हुआ. शुरुआती दौर में विदेशों में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड थोड़ा बहुत सुधारने में सफल हुए. पिछले 2 सालों से विदेशी सरजमीं पर उनका रिकॉर्ड बद से बदतर रहा है. कोई भी कप्तान ऐसे आकड़ों को याद नहीं करना चाहता है. 2015 के एकदिवसीय विश्व कप के आयोजन में साल भर का समय भी नहीं बचा है. ऐसे में एकदिवसीय कप्तान के रूप में धोनी को हटाना सही निर्णय नहीं होगा. टेस्ट कप्तानी विराट कोहली को दे देनी चाहिए, जिससे कि बतौर कप्तान उन्हें परिपक्व होने में मदद मिल सके. एकदिवसीय मैचों में पिछले साल दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड दौरे को छोड़कर भारतीय टीम को जीत हासिल हुई. सीमित ओवरों के प्रारूप में धोनी अभी भी दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान हैं. ऐसे में उन्हें टीम से निकालना और एकदिवसीय कप्तानी से हटाना चयनकर्ताओं और बीसीसीआई के लिए आत्मघाती कदम होगा. धोनी पहले भी कई बार यह कह चुके हैं कि 2015 विश्व कप के बाद वह अपने करियर को लंबा करने के लिए क्रिकेट के छोटे प्रारूपों पर ध्यान देंगें. टीम के संतुलन को बनाए रखने के लिए अब टीम से ज्यादा छेड़छाड़ करना संभव नहीं होगा. ऐसे भी चयन समिति उन्हें विश्व खिताब बचाने का मौका जरूर देगी. यदि फिक्सिंग मामले में धोनी का नाम नहीं उछलता है, तो फिलहाल धोनी टीम इंडिया के कप्तान बने रहेंगे और कोहली को अपनी बारी का इंतजार करते रहना होगा. निश्चित तौर पर कोहली टीम इंडिया का युवराज बन चुके हैं. एकदिवसीय विश्वकप के बाद उनकी ताजपोशी होना निश्चित है. आगे चलकर वह एक बेहतरीन कप्तान साबित होंगे. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

कोई सरहद ना इन्हें रोके...

प्रियंका प्रियम तिवारी

हिंदुस्तान–पाकिस्तान का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि दोनों देशों के बीच मोहब्बत और नफरत साथ–साथ चलती हैं. कुछ दिनों पहले फ़राज हैदर की एक फिल्म आई थी वार छोड़ ना यार. फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह सीमा पर एक–दूसरे के ख़िलाफ़ बंदूक तान कर खड़े रहने वाले सैनिकों में इतने अच्छे संबंध बन जाते हैं कि वे एक–दूसरे को अपने देश के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं. अंताक्षरी खेलते हैं. सलमान, शाहरुख, ऐश्वर्या, काजोल, लता, आशा के जितने दीवाने हिंदुस्तान में हैं, उतने ही पाकिस्तान में भी. ठीक वैसे ही मेहदी हसन, गुलाम अली, फ़रीदा ख़ानम, मुन्नी बेगम, आबिदा परवीन, बेगम अख्तर जैसे फनकारों के भारत में लाखों–करोड़ों चाहने वाले हैं, पर न चाहते हुए भी आदेश मिलने पर सैनिक एक–दूसरे पर गोलियां चलाते हैं. दोनों देशों

के बीच नफरत का बीज बोने वाले लोगों के अपने फ़ायदे हैं. दोनों देशों में होने वाले आंतकी गतिविधियों और हिंसा के लिए एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप करते हैं. क्रिकेट में जीत–हार पर दोनों देशों में जश्न और मातम मनाया जाता है. किसी और देश से हार या जीत पर इतनी खुशी और दुख नहीं होता, जितना एक–दूसरे से हारने या जीतने पर होता है, पर कला जगत के लिए सरहदों का यह अंतर मिट जाता है. कलाकारों की दोनों देशों में कद्र है. पाकिस्तान के युवाओं में एक तरफ भारत के लिए नफरत के बीज बोए जाते हैं और भारत के ख़िलाफ़ आतंकी गतिविधियों में उनका ब्रेन वॉश कर इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पाकिस्तान के हज़ारों–लाखों युवा बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं. बॉलीवुड में काम करना उनका सपना है. कई पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड में काम कर रहे हैं. उनके परफॉर्मेंस को यहां पसंद किया जा रहा है. कई पाकिस्तानी कलाकारों ने बॉलीवुड में काम किया और कुछ एक फिल्मों के बाद सफलता न मिलने पर वापस चले गए. इन दिनों भी कई पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं. उन्होंने इसे ही अपना घर मान लिया है.

सोमी अली: सोमी का बचपन करांची में बिता. सात साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा शिफ्ट हो गईं. वह भी एक आम पाकिस्तानी की तरह बॉलीवुड फिल्मों की दीवानी थीं. किशोरावस्था में वह सलमान की इस क़दर दीवानी हुईं कि उन्होंने बॉलीवुड में ही करियर बनाने का निर्णय ले लिया. वह सलमान से मिलने का सपना लिए मुंबई आईं, यहां वह मॉडलिंग और फिल्में करने लगीं. उनकी कुछ फिल्में हैं: अंत, कृष्ण अवतार, यार गद्दार, तीसरा कौन, आओ प्यार करें, आंदोलन, माफिया. सोमी की दीवानगी को देखते हुए सलमान भी उनके प्यार में पड़ गए, पर दोनों का रिश्ता किसी मोड़ पर पहुंचता, इससे पहले ही वह ऐश्वर्या की नीली आखों में खो गए. सोमी यह बर्दाश्त न कर सकीं और वापस फ्लोरिडा चली गईं. सोमी अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और वह नो मोर टियर्स नाम से वूमेन वायलेंस के ख़िलाफ़ एक एनजीओ भी चलाती हैं. उन्होंने रिश्ता टूटने के लिए किसी को ज़िम्मेदार न मानते हुए अपने प्यार से नफरत के साथ दूर होने के बजाए दोस्ती का नाम दे दिया. सलमान और सोमी आज भी अच्छे दोस्त हैं.

मोहसीन ख़ान: पाकिस्तानी हसीनाओं को भारत में काफ़ी पसंद किया जाता है, लेकिन बॉलीवुड हसीनाओं के दीवाने भी पाकिस्तान में हैं. तभी पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर मोहसीन ख़ान बॉलीवुड ब्यूटी रीना रॉय के प्यार में पड़े. दोनों सरहदों की दूरियां मिटा कर एक हो गए. रीना मोहसीन संग पाकिस्तान चली गईं तो मोहसीन पत्नी और बॉलीवुड प्रेम की ख़ातिर भारत आ बसे और क्रिकेट छोड़ फिल्मों में काम करने लगे. उन्होंने महानता, घुंघट, बेटा, मैडम एक्स, द एलीफैंट वॉक, जन्नत, लाट साहब, साथी, प्रतिकार, गुनहगार कौन, फतेह, बंटवारा, त्यागी जैसी कुछ फिल्मों में काम किया. बॉलीवुड में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली और रीना के साथ भी उनके संबंध ख़राब होने लगे. रीना से अलगाव के बाद मोहसीन वापस लौट गए. अब वह पाकिस्तान में क्रिकेट कोच और चयनकर्ता हैं.

जावेद शेख: पाकिस्तान के जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्देशक जावेद का सपना था बॉलीवुड में काम करना. 2005 में वह मुंबई आ गए. उन्होंने शिखर, राफ्ता–राफ्ता, जानेमन, नमस्ते लंदन, ओम शांति ओम, अपने, माई नेम इज एंथोनी गोनसाल्विस, जन्नत, हंसते–हंसते, मनी है तो हनी है, युवराज, रोड टू संगम, हम तुम और घोस्ट, सदियां, कजरारे और न जाने कब से, जैसी बॉलीवुड फिल्में कीं. उनके निर्देशन में बनी फिल्म खुले आसमान के नीचे की शूटिंग चार देशों पाकिस्तान, भारत, अरब और ऑस्ट्रेलिया में हुई है. उन्होंने यहां घर भी ले लिया है और अपने नए घर से उन्हें बेहद लगाव है.

सलमा आगा: करांची, पाकिस्तान के एक पठान परिवार में जन्मी सलमा ने बहन सबीना के साथ उर्दू में कुछ सॉन्ग्स निकाले, जो हिट हुए. राजकपूर ने जब ऋषि और नीतू की शादी की रिसेप्शन पार्टी दी तो उन्होंने अपनी कजन सलमा की मां को भी बुलाया. तब बीआर चोपड़ा अपनी फिल्म तलाक तलाक तलाक की नायिका की तलाश में थे. यह बात सलमा को पता चली. वह मुंबई आईं और चोपड़ा ने उन्हें निकाह के लिए साइन कर लिया. उन्होंने निकाह का गाना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए भी गया. उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फिमेल प्लेबैक अवॉर्ड मिला. उनकी कुछ और बॉलीवुड फिल्में हैं: ज्वाला दारू, कसम पैदा करने वाले की, सलमा, ऊंचे लोग, मार्केट, फायर, महावीरा, पांच फौलादी, फोर्स, नंबर वन, पति पत्नी और तवायफ, मीत मेरे मन के, गहरा राज. पर इन फिल्मों से वह कुछ ख़ास मुक़ाम नहीं बना पाईं.

जेबा बख्तियार: पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा की ख़ूबसूरती और मासूमियत को भारत में भी काफ़ी पसंद किया गया. ऋषि कपूर के साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने कमाल का अभिनय किया. क्लर्क, देशवासी, हिना, मोहब्बत की आरजू, स्टंटमैन और संजय दत्त के साथ जय विक्रांता जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन दर्शकों ने उन्हें कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दिया.

मीरा (इर्तिंजा रूआब): लाहौर में जन्मीं मीरा ने शुरुआत मॉडलिंग से की. बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म थी नज़र. सोनी राजदान की इस फिल्म में मीरा के अपोजिट थे अस्मित पटेल. इस फिल्म में उनके बोल्डनेस की काफ़ी चर्चा हुई. कसक, सिमरन, ओम अल्लाह, पांच घंटे में पांच करोड़ जैसे बॉलीवुड फिल्मों में वह दिखीं, पर सभी फिल्में फ्लॉप रहीं. काफ़ी हाथ–पांव मारने के बाद भी मीरा कुछ ख़ास न कर सकीं और पाकिस्तान लौट गईं.

नर्गिस फ़ाख़री: पाकिस्तानी पिता की संतान नर्गिस अमेरिकन मॉडल और अभिनेत्री हैं, पर इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में रणबीर कपूर के साथ काम करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में ही करियर बनाने का फ़ैसला कर लिया. 2013 में वह सुजीत सिरकर की फिल्म मद्रास कैफे में वॉर कॉरेस्पोंडेंट जया साहनी के किरदार में दिखीं. वहीं फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में वह आइटम डांस करती नजर आईं. कम ही फिल्मों से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली है.

अली ज़फ़र: अली ज़फ़र बॉलीवुड में जाना–पहचाना नाम बन चुका है. उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया है. इन दिनों वह यामी गौतम के साथ अपनी फिल्म टोटल स्यापा की सफलता से काफ़ी खुश हैं. यह फिल्म भारत–पाक संबंधों पर आधारित है और रोमांस और हास्य से भरपूर है. उनकी पहली फिल्म 2010 में तेरे बिना लादेन और इसी साल उनकी एक और फिल्म लव का द एंड भी आई. 2011 में कटरीना और इमरान ख़ान के साथ उनकी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन आई. यह फिल्म भी सफल रही थी. 2012 में उनकी दो फिल्में लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क और चश्मेबद्दूर आई थी. सभी फिल्में औसतन ठीक चलीं.

वीना मलिक: रावलपिंडी की वीना ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया. गली गली में चोर है, तेरे नाल लव हो गया, दाल में कुछ काला है, ज़िंदगी 50–50, सुपरमॉडल उनकी फिल्में हैं, पर फिल्मों से ज़्यादा वह कंट्रोवर्सी क्वीन के रूप में मशहूर हुईं.

सारा लोरेन (मोनालिजा): विशेष भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म मर्डर थ्री में पाकिस्तानी अभिनेत्री सारा के अभिनय और ख़ूबसूरती दोनों की तारिफ हुई. फिल्म को कुछ ख़ास सफलता नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म से उन्हें ज़रूर पहचाना जाने लगा. बहुत कम लोगों को पता होगा कि यह सारा की पहली फिल्म नहीं थी. जी हां उनकी पहली फिल्म थी 2010 में पूजा भट्ट की कजरारे. इस फिल्म में उनके अपोजिट थे हिमेश रेशमिया. फिल्म फ्लॉप रही. 2014 में उनकी तीन फिल्में रिलीज होने वाली हैं.

हुमैमा मलिक: क्वेटा, पाकिस्तान की हुमैमा ने 14 साल की उम्र से ही मॉडलिंग शुरू कर दिया था. फिर वह टीवी धारावाहिकों में काम करने लगीं. उनकी पहली फिल्म थी बोल. तभी उन पर विधु विनोद चोपड़ा की नज़र पड़ी. चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म चिट्ठियां में साइन कर लिया. 2014 में हुमैमा इमरान हाशमी के साथ फिल्म शातिर में नजर आएंगी.

मेहरीन सईद: मेहरीन पाकिस्तान में इनफॉर्मेशन फॉर फाइनांशियल ऐड प्रोफेशनल्स की सीईओ हैं. अभिनेत्री एवं मॉडल होने के साथ ही वह 50 हॉटेस्ट एशियन महलाओं की सूची में 16वें नंबर पर हैं और एशिया की सेक्सी महिलाओं की सूची में उनकी रैंकिंग 10 है. मेहरीन एक सफ़ल व्यवसायी और लॉरियल की स्पोक्स पर्सन भी हैं. उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए कई भारतीय फिल्मकार इच्छुक हैं, लेकिन उन्होंने फिल्मकार संजय पूरन सिंह की फिल्म साइन की, पर वीजा न मिल पाने के कारण उन्हें यह फिल्म छोड़नी पड़ी. मेहरीन ने कहा कि उन्हें मलाल है कि वह फिल्म नहीं कर पाईं.

मुस्कान ख़ान: पाकिस्तान की प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका मुस्कान ख़ान कबीर राज की फिल्म जस्ट एसएमएस में राज बब्बर और रवीना टंडन के साथ स्क्रीन स्पेश शेयर करती नज़र आएंगी. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वह बॉलीवुड फिल्मों में काम करने को लेकर काफ़ी उत्सुक थीं. आख़िरकार उनका सपना सच हो ही गया.

साशा आगा. सलमा आगा कई बॉलीवुड फिल्में करने के बाद भी कुछ ख़ास मुकाम नहीं बना पाईं, लेकिन अब उनके अधूरे सपने को पूरा करने की काशिश में लगी हैं उनकी बेटी शासा. शासा आगा 2013 में फिल्म औरंगजेब में अर्जुन कपूर के साथ नज़र आ चुकी हैं. फिल्म तो सफल नहीं हुई, लेकिन साशा ने इस फिल्म में जमकर अंग प्रदर्शन किया. अब उनकी अगली फिल्म है देसी कट्टे. इस फिल्म में उनके साथ हैं सुनील सेट्ठी और टीया बाजपेयी.

मीशा साफ़ी: लाहौर, पाकिस्तान की सिंगर मॉडल और अभिनेत्री मीशा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 में मीरा नायर की हॉलीवुड फिल्म द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट से की. साल 2013 की सबसे ज़्यादा पैसे कमानेवाली बॉलीवुड फिल्म भाग मिल्खा भाग में वह मिल्खा सिंह की दोस्त पेरिजाद की भूमिका में दिखीं. ■

KHARA SAUDA
Issey Behtar Aur Nahin
011-64000222 / 333
6 Double Bed Sheets with 12 Pillow Covers
EXCLUSIVE DEAL
Special Price : Rs.1999/-
Shipping Cost: Rs.200/-

Call/SMS : 011-64000222 & 011-64000333
PAY CASH ON HOME Delivery
Offer open till stock lasts
'Products and warranty by 3rd party vendors. Brands. Logos. Creative, trademarks, copyrights are owned by their respective vendors'
*Terms & Condition Apply

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

10 मार्च–16 मार्च 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार–झारखंड

लुटी या बची लालू की लालटेन

सूबे की राजनीति को समझने वाले सभी लोग काफी दिनों से जान रहे थे कि राजद में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. बार-बार आशंका जताई जा रही थी किसी भी दिन राजद विधायक टूट कर जदयू में जा सकते हैं. बस एक ठीक-ठाक बहाने का इंतजार हो रहा है लेकिन इससे पहले की यह बहाना मिलता सम्राट चौधरी ने हड़बड़ी में या फिर कहिए खुद ही सारा श्रेय लेने के लिए धमाका कर दिया. विधानसभा अध्यक्ष ने भी 13 विधायकों को अलग गुट के तौर पर मान्यता दे दी और कहा कि उन्होंने विधिसम्मत काम किया है. उन्होंने एक पार्टी में विलय व अलग बैठने की इजाजत मांगी थी. अब कई चीजें तो आगे की है इस पर आगे ही कार्रवाई हो सकती है. मेरे पास जो आवेदन आया उनमें विधायकों के ही हस्ताक्षर थे. सम्राट चौधरी भी दावा कर रहे हैं कि सभी 13 विधायक मेरे साथ हैं और सभी ने सोच समझकर दस्तखत किए हैं.

सरोज सिंह

तेरह विधायक गए और नौ लौट आए लेकिन यह लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुई राजनीतिक फिल्म आॅपरेशन राजद का क्लाइमेक्स नहीं है, क्योंकि इस पिक्चर की पटकथा कहती है कि अभी इसमें कई उठा-पटक बाकी हैं और कई ऐसे नए किरदारों को आना है जो अपने हाथों से इस फिल्म का दी इंड लिखेंगे. लालू प्रसाद को भी इस क्लाइमेक्स का पता है इसलिए वह इस कोशिश में हैं कि कम से कम नुकसान हो और जनता के पास यह संदेश चला जाए कि साजिश के तहत राजद को तोड़ने की कोशिश जारी है ताकि लोकसभा चुनाव में लाज बचाई जा सके. राबड़ी देवी के निवास से निकलकर लालू जैसे ही सड़क पर मार्च करने निकले तो उन्होंने अपने इस इरादे को साफ भी कर दिया. स्पीकर उदय नारायण चौधरी को निशाने पर लिया और नीतीश कुमार को मछली के चोइयां की तरह साफ कर देने की चेतावनी दी. अपने वोटरों से कहा कि सामाजिक न्याय और गरीबों के खिलाफ नीतीश कुमार और भाजपा वाले साजिश कर रहे हैं इन लोगों को मुंहतोड़ जबाव देना है. लालू प्रसाद दावा कर रहे हैं कि उनके विधायकों को धोखे में रखा गया पर अब वह वापस आ गए हैं और सब ठीक हो गया है. लेकिन जानकार कह रहे हैं कि कहानी इतनी भी साफ और सीधी नहीं है.

सूबे की राजनीति को समझने वाले सभी लोग काफी दिनों से जान रहे थे कि राजद में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. बार-बार आशंका जताई जा रही थी किसी भी दिन राजद विधायक टूट कर जदयू में जा सकते हैं. बस एक ठीक-ठाक बहाने का इंतजार हो रहा है लेकिन इससे पहले की यह बहाना मिलता सम्राट चौधरी ने हड़बड़ी में या फिर कहिए खुद ही सारा श्रेय लेने के लिए धमाका कर दिया. विधानसभा अध्यक्ष ने भी 13 विधायकों को अलग गुट के तौर पर मान्यता दे दी और कहा कि उन्होंने विधिसम्मत काम किया है. उन्होंने एक पार्टी में विलय व अलग बैठने की इजाजत मांगी थी. अब कई चीजें तो आगे की है इस पर आगे ही कार्रवाई हो सकती है. मेरे पास जो आवेदन आया उनमें विधायकों के ही हस्ताक्षर थे. सम्राट चौधरी भी दावा कर रहे हैं कि सभी 13 विधायक मेरे साथ हैं और सभी ने सोच समझकर दस्तखत किए हैं. अगर इनकार करते हैं तो हस्ताक्षर की जांच होनी चाहिए. नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि इस टूट के लिए खुद लालू ही जिम्मेदार हैं. स्पीकर पर कोई दबाव नहीं है. लोग आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे. इन सब दावों से बढ़कर भी जो बात है वह यह है कि लौट आए विधायकों का मन भी शांत नहीं हैं. संविधान की धाराओं की पेचीदगी और विधानसभा अध्यक्ष के सदन के अंदर के असीमित अधिकार के कारण बहुत सारे राजद विधायक दुविधा की स्थिति में हैं. वह इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं कि राजद में लौटने के बाद उनकी सदस्यता बरकरार ही रहेगी और कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा. लेकिन सदस्यता बरकरार रखने के मामले में इतने सारे पेंच हैं कि कोई भी दावे के साथ यह अभी नहीं कह सकता कि राजद में वापस लौट चुके विधायकों की सदस्यता बरकरार रह ही जाएगी. यह अब विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वह इसको तुरंत खत्म करें या लंबे समय तक खींच कर ले जाएं. अध्यक्ष के फैसले को अगर अदालत में चुनौती दी जाती है तो मामला अपने आप लंबा चला जाएगा. हो सकता है कि यह विधानसभा के अगले चुनाव तक खींच जाए. यह भी हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष उन विधायकों पर कार्रवाई भी कर सकते हैं कि जो यह कह कर बचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी कागज पर उनके हस्ताक्षर धोखे से ले लिए गए. कुछ विधायकों ने यह भी कहा है कि उन्होंने दस्तखत किया ही नहीं. विवाद बढ़ने पर विधायकों के दस्तखत का मिलान किया जाएगा. जांच के बाद अगर साबित हो गया कि दस्तखत संबंधित विधायक का ही है तो इस आधार पर भी सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा फोरेंसिक जांच से भी यह पता चल जाएगा कि किसी विधायक ने सादे कागज पर दस्तखत किया था या नहीं. जांच से यह भी पता चल जाएगा कि सभी विधायकों ने एक साथ दस्तखत किया था या फिर कुछ अंतराल में. जांच में अगर यह बात साबित हो गई कि विधायकों ने एक साथ दस्तखत किया था और बाद में किसी कारण से मुकर रहे हैं तो ऐसे विधायक कार्रवाई के घेरे में आ सकते हैं. जदयू के एक नेता कहते हैं कि यह तो हद हो गई. आप चेक पर दस्तखत कर दें और बैंक से पैसा निकल जाए और बाद में बैंक मैनेजर से क्लेम करें कि मैंने धोखे से साइन कर दिया था. ऐसा कहीं होता है क्या? बैंक मैनेजर ने तो बस साइन का मिलान किया और अगले आदमी को पैसा दे दिया. कल को ऐसे विधायक कहेंगे कि हमलोगों ने लालू के दबाव में आकर राजद में बने रहने का पत्र स्पीकर को सौंपा है तब क्या स्थिति बनेगी? इन्हीं सारी आशंकाओं के कारण राजद के बहुत सारे विधायक सहमे हुए हैं. कुछ विधायक इस पूरे प्रकरण के बाद भी लगातार जदयू नेताओं के संपर्क में हैं. उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं वे न घर के रहें न घाट के. नाम न छापने की शर्त पर कुछ विधायकों ने बताया कि अब तो समय ही हमारे अगले कदम को तय करेगा. हमलोगों का क्या होगा, यह हमलोग अभी नहीं जानते पर हमलोगों का नुकसान तो हो ही गया. हमलोग तो लालू प्रसाद की नजर से भी गिर गए. क्षेत्र की जनता कहती है कि आप लोगों ने लालू प्रसाद को धोखा दिया. जबकि हकीकत है कि हमलोग खुद धोखे के शिकार हो गए. नीतीश लहर में जो राजद विधायक जीत कर आए हैं वे सभी लालू के आधार वोट के ही शुक्रगुजार हैं. ऐसे में अविश्वास की यह स्थिति अगले चुनाव में उनको नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए इन विधायकों के बीच भी मंथन जारी है कि अगला कदम क्या हो? एक तरफ दलबदल की तलवार तो दूसरी तरफ यादव व मुस्लिम वोटों का अविश्वास. करें तो क्या करें? इसी राजनीतिक परिस्थिति ने इन विधायकों के मन को डांवाडोल कर रखा है. जदयू नेताओं के संपर्क में रहना उनकी राजनीतिक मजबुरी हो गई है. इसलिए जिस समय इन विधायकों को लग जाएगा कि जदयू खेमे में जाने में ही उनकी भलाई हैं तो बहुत संभव है कि वे फिर एक पत्र स्पीकर को दे आएं कि लालू प्रसाद ने दबाव डालकर उनसे दस्तखत करवा लिया था. इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि लालू की लालटेन लुटने से बच ही गई. 13 में चार विधायक तो नहीं ही लौटे और जो लौटे हैं उनको लेकर भी तरह-तरह की आशंकाएं हैं. इसलिए अभी बस यही कहा जा सकता है सूबे बिहार की अगले पखवाड़े की राजनतिक तस्वीर बहुत ही दिलचस्प होगी और ऑपरेशन राजद का क्लाइमेक्स शायद इस दौरान शुरू हो जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

लालू के बागवानी मंत्री ने ही उजाड़ दिया इनका चमन

हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए सम्राट

कहते हैं कभी-कभी फुलप्रूफ योजना भी हड़बड़ी या फिर छोटी-मोटी गलतियों के कारण अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है. ऑपरेशन राजद भी कमोवेश एक फुलप्रूफ योजना थी लेकिन सम्राट चौधरी की थोड़ी सी हड़बड़ाहट ने लालू यादव को अपनी राजनीतिक साख बचाने का कुछ मौका दे दिया. राजद के 22 विधायकों में 15 कौन कहे 16 विधायकों का पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाना था. 13 विधायकों का हस्ताक्षर भी करा लिया गया था. तय हुआ था कि कांग्रेस के साथ तालमेल की घोषणा होते ही काम को अंजाम दे दिया जाएगा क्योंकि आशंका थी कि इस तालमेल में आरा, किशनगंज, मधुबनी और खगड़िया की सीटें कांग्रेस व लोजपा के खाते में जा सकती है. लालू प्रसाद को भी इस संभावित खतरे का अहसास था इसलिए

वह गठबंधन को अमली जामा में लंबा वक्त लगा रहे थे जो अमूमन लालू की फितरत नहीं है. इस बीच वह अपने सबसे विश्वासी भोला यादव को अब्दुल बारी सिद्दकी और सम्राट चौधरी को मनाने के लिए लगा चुके थे. सम्राट चौधरी ने तो लालू की एक नहीं सुनी यहां तक कि उन्होंने लालू प्रसाद से फोन पर बात करने से भी मना कर दिया. सिद्दकी साहब कहते रहे कि उन्हें कोई नहीं डिगा सकता लेकिन मैं बहुत ही आहत हूं. जो बात सामने आ रही है इसका लब्बोलुआब यह है कि सिद्दकी साहब दुविधा में थे. वह इस मत के थे कि लालू प्रसाद को समझाया जाए. अगर बात से नहीं मानते तो दबाव की राजनीति के तहत उन्हें मनाया जाए लेकिन बिना किसी ठोस आधार के दल तोड़ने जैसी कार्रवाई के वह पक्ष में नहीं थे.

.....शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

एक नज़र

विधायक ने किया पुलिया का उद्घाटन

पिछले दिनों रुन्नीसैदपुर की जदयू विधायक गुड्डी देवी ने क्षेत्र के महिंदवारा में 3 पीसीसी सड़क एवं बरहेता पंचायत के हजपुरवा में 1 आरसीसी पुलिया का उद्घाटन किया. महिंदवारा में आयोजित कार्यक्रम में मुखिया रामबाबू साह, संतलाल ठाकुर, अरुण सहनी, गौरी सिंह, देवकी सहनी, झिगन सहनी, विपिन कुमार, रमा शंकर सिंह, उमा शंकर सिंह एवं हजपुरवा में राम रतन ठाकुर, लालबाबू साह, विपिन कुमार, गगन सहनी, बइआलाल साह समेत अन्य थे. मौके पर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत कराये गये कार्य से आम आवाम को काफी सहुलियत होगी. उन्होंने कहा कि करीब 45 लाख रुपये की योजना से उक्त कार्य कराया गया है. आने वाले दिनों में अन्य विकास कार्यों को भी कराया जायेगा. जदयू नेता राजेश चौधरी ने आम जनता को बधाई दी.

लोकसभा चुनाव में जीत के लिए राजद की बैठक

लोकसभा चुनाव में राजद की जीत लेकर प्रखंड राजद अध्यक्ष संजीत कुमार छोटू की अध्यक्षता में राजद कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई. रुन्नीसैदपुर स्थित खादी वस्त्रागार परिसर में आयोजित बैठक में पूर्व सांसद सीताराम यादव भी मौजूद थे. बैठक में बूथ कमिटी का गठन के अलावा जन संपर्क अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप राय, प्रदेश सचिव नमोनाथ प्रसाद यादव, पूर्व प्रत्याशी राम शत्रुघ्न राय, महावीर साह, भोला राय, अरुण कुमार सिंह, राज कुमार साह, रमा शंकर राय, नागेंद्र कपूर, शंकर राय, रामदेव राय व सुकेश्वर ठाकुर समेत अन्य नेता मौजूद थे. **–विभा सिन्हा**

हिन्दी उत्सव आयोजित

पटना के बोरिंग रोड स्थित पंकज क्लासेज के सामने सड़क के किनारे कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह की प्रकाशित 40 किताबों पर आधारित आम आदमी के बीच हिन्दी–उत्सव का आयोजन किया गया. उत्सव का उद्घाटन शिवम क्लासेज के निदेशक एवं महंत हनुमान शरण कालेज के प्राचार्य डॉ. विमल नारायण आर्य तथा पंकज क्लासेज के निदेशक प्रो. पंकज कुमार ने संयुक्त रुप से किया. आम आदमी के बीच हिन्दी–उत्सव का आयोजन एवं इसके लिए कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह की जनसुलभ किताबों का चयन शिवम क्लासेज एवं पंकज क्लासेज के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था. उक्त आयोजन में कथाकार डॉ. सिंह की हर किताब को मात्र 30 रुपये में उपलब्ध करवाया गया और खरीदने वाले पाठक को एक औषधीय पौधा,कलम या अन्य कोई ना कोई उपहार दिया गया. आम आदमी के बीच हिन्दी–उत्सव को सफल बनाने के लिए प्रो. बी.के राय, प्रो.सी.डी.सिंह, प्रो.संजय ठाकुर, शैलेन्द्र सिंह, मनोज कुमार, अंशु, उपेन्द्र कुमार, गुड़िया, सिमरन, सीनू, इलीशा, अंकिता, करण कुमार, रौशन, पूजा, धीरज, हेमा, प्रदीप, अखिलेश, मिथिलेश, पिक्की, राजाराम, प्रेम, अजय, प्रीति, डीजू रंजन, दीपक कुमार, संदीप इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ■ **– अमृता कुमारी**

उद्देश्य से भटका अंजुमन इस्लामिया

इन्वेस्टिगेशन हक

हमारे देश में मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है. उनके कल्याण और बेहतरी के लिए केंद्र और राज्य सरकारें योजनाएं भी चलाती हैं. बावजूद इसके इनकी स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती है. [illegible]

[illegible] दो गुट हमेशा इस अंजुमन पर अपना कब्जा जमाने के लिए आमने–सामने रहा है. एक गुट शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. परवेज का है तो, दूसरा डॉ. प्रो. अनवारुल हक व नगर परिषद के उपमुख्य पार्षद मोहिबुल हक

जनता तैयार करेगी घोषणा पत्र

लोकसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिमी चंपारण के स्वयंसेवी व सामाजिक संगठनों ने एक अनोखी पहल शुरू कर दी है. [illegible] व्यक्त करने वालों में प्रो. प्रकाश, पंकज, का. वीरेन्द्र गुप्ता, मनौवर [illegible] चतुर्वेदी, शेख भोला, रविकान्त परासर, तारकेश्वर राम तुफानी, अख्तर मियां, राजेश कुमार, विश्वनाथ, रिजवानुल्लाह, मेंहिलाल, फूलपरी देवी, राजेश कुमार जायसवाल और ई. नौशाद अहमद मुख्य है.

– अवधेश कुमार शर्मा

[illegible] अंजाम पा [illegible] अंतराल पर [illegible] हां आते हैं. [illegible] ई वेतन नहीं [illegible] तमाम हदों [illegible] अनेक मामले सामने आए जिनके कारण मुस्लिम समाज को शर्मिन्दगी झेलनी पड़ी. मामला हाथापाई से होते हुए खून–खराबे तक पहुंच गया. मोतिहारी जामा मस्जिद स्थित अंजुमन के कार्यालय में चल रही चुनाव प्रक्रिया के दौरान पुलिस दस्ते को प्रशासन ने मुस्तैद कर रखा था. इसके अलावा मोतिहारी नगर परिषद के उपसभापति मोहिबुल हक खां के जानपुल स्थित मोहल्ले में चुनाव से पूर्व जमकर मारपीट होना व हंगामा को देख चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव निरस्त कर देना अंजुमन इस्लामिया के इतिहास की पहली घटना थी. चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों द्वारा तमाम नियमों को ताक पर रख दिया गया और समाज के कई योग्य उम्मीदवारों को साजिश रचकर हरा दिया गया जिसकी चर्चा बाद के दिनों तक होती रही. चुनाव जीतकर अंजुमन का सदस्य बनने के लिए जिस तरह का ड्रामा यहां खेला गया इससे साफ जाहिर हो गया कि सदस्यों को समाज व कौम की सेवा में कम व अपनी सेवा में अधिक दिलचस्पी है. यह अलग बात है कि चुनाव जीत कर आने वाले सभी एक जैसे नहीं हैं और इसमें अच्छे लोग भी हैं. किन्तु अभी के समय में चुनाव जीत कर अधिकांश वही लोग अंजुमन में आए हैं जिन्हें समाज व कौम से दूर–दूर तक वास्ता नहीं है. शायर, पत्रकार व संस्कृतिकर्मी गुलरेज शहजाद का कहना है कि अंजुमन मुस्लिम समुदाय की प्रतिनिधि संस्था है. इसे एक कार्ययोजना के तहत मुस्लिम समुदाय की तरक्की और समस्याओं के निदान के लिए कार्य करना चाहिए. इधर के दिनों में अंजुमन का जो चरित्र उभर कर सामने आया है उससे हर ओर एक गलत संदेश गया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है. बड़े मकसद के लिए निजी स्वार्थ को कुर्बान करना पड़ेगा. दूसरी तरफ सचिव अदालत हुसैन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं और कहते हैं कि सभी काम अंजुमन की दुस्तूर के मुताबिक होता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

किसानों को दिया गया पुरस्कार

नन्द किशोर शर्मा

भगवती ट्रैक्टर एजेन्सी बलुआही, खगड़िया के शोरूम में ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन किया गया. समारोह के दौरान एस्कॉट्स कम्पनी के बिहार–झारखण्ड मैनेजर विनोद कुमार यादव, एचडीएफसी के सेल्स मैनेजर मुकेश कुमार एवं भगवती ट्रैक्टर के अधिकृत विक्रेता विकास डारोलिया ने लक्की ड्रॉ निकालकर मधेपुरा जिले के किसान मो. इमरोज आलम, महेश राय एवं मनोरंजन कुमार को 21–21 हजार रुपये के चेक पुरस्कार के रूप में दिया गया. साथ ही अन्य छह किसानों को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित करते हुए एरिया मैनेजर विनोद कुमार यादव ने कहा कि एस्कॉट्स कम्पनी के पावरट्रैक यूरो ट्रैक्टर की गुणवत्ता अन्य किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर से अधिक है. उन्होंने कहा कि यूरो 434 डीएस, 439 डीएस एवं 445 डीएस यूरो ट्रैक्टर की गुणवत्ता माइलेज में नम्बर वन है, जो किसानों को अधिक कंफर्ट एवं लाभदायक मसहूस होता है. वहीं भगवती ट्रैक्टर के विकास डारोलिया ने किसानों से वादा करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण सेवा करना ही उनका धर्म है. उन्होंने कहा कि यह लक्की ड्रॉ दिसम्बर माह का हुआ है, जनवरी माह में जितने भी किसानों ने टैक्टर खरीदे हैं, उनमें तीन में एक किसान को लक्की ड्रॉ के माध्यम से 21–21 हजार का पुरस्कार दिया जाना बाकी है. इस अवसर पर नीतीश डारोलिया, विशाल डारोलिया किसान चरण यादव, बहादुर यादव, भूदेव साह, देवशंकर साह, राकेश रौशन, अफरोज आलम सहित दर्जनों किसान उपस्थित थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए सम्राट

..........पृष्ठ 17 का शेष..........

सिद्दकी साहब ने कई मौके पर कहा कि उन्हें नीतीश कुमार की तरफ से कई तरह के ऑफर हैं लेकिन मैं तो कर्पूरी ठाकुर का विद्यार्थी हूं भला कोई गलत कदम कैसे उठा सकता हूं. लेकिन बताया जा रहा है कि अगर तालमेल में उन्हें मधुबनी सीट नहीं मिलती तो वह फिर कोई भी बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते थे. लेकिन सम्राट चौधरी ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी. 13 विधायकों का हस्ताक्षर वाला पत्र सम्राट चौधरी एक महफूज जगह से यह कह कर ले गए कि इस पर दो विधायकों का और हस्ताक्षर कराना है. लेकिन हस्ताक्षर कराने की बजाए वह इस पत्र को विधानसभा अध्यक्ष को सौंप आए. सम्राट चौधरी को समझाया गया कि अभी जितना है उसे दे दीजिए बाकी के विधायकों का बाद में दे दीजिएगा इसे विभाजन की प्रकिया मान वैध मान लिया जाएगा. सम्राट इस बात को मान गए और बिना अपने साथियों को भरोसे में लिए इस पत्र को विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया और स्पीकर ने भी बिना देर किए 13 विधायकों को अलग गुट की मान्यता देते हुए इनके सदन में अलग बैठने का इंतजाम कर दिया. अगर कम से कम 15 विधायकों का हस्ताक्षर होता तो लालू प्रसाद का पक्ष बेहद कमजोर हो जाता पर अब वह दलबदल कानून को अपनी ढाल बना रहे हैं. सम्राट की हड़बड़ी ने लालू को कुछ राहत दे दी नहीं तो लालू की लालटेन तो लुट ही चुकी थी. गौरतलब है कि कायदे–कानून को ताक पर रखकर किसी जमाने में लालू ने सम्राट चौधरी को बिहार में मंत्री बनाया था. सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं जिन्हें नब्बे के दशक में बिहार में कोइरी जाति का सबसे बड़ा नेता माना जाता था. 1999 में लालू ने शकुनी चौधरी को समता पार्टी (नीतीश की पार्टी) से तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया था. शकुनी खगड़िया से समता पार्टी के सांसद हुआ करते थे. पत्नी तारापुर से विधायक थीं और बेटे सम्राट को राबड़ी मंत्रिमंडल में मंत्री बनवा दिया जो न तो विधायक थे और ना ही विधान परिषद के सदस्य. वो भी कैबिनेट मंत्री. तब बिहार की राजनीति में उम्र को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ कि राज्यपाल ने 16 नवंबर 1999 को सम्राट चौधरी को बर्खास्त कर दिया. आधार बना कि सम्राट अभी पच्चीस साल के भी नहीं हैं.

कोर्ट में दिए एक हलफनामे को आधार माना गया जिसके हिसाब से तब सम्राट सिर्फ 19 साल के थे. और मंत्री बनने के लिए 25 साल कम से कम चाहिए. 19 मई 1999 को सम्राट बगैर किसी सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री बने थे. छह महीने पूरे होने वाले थे लेकिन तीन दिन पहले ही उन्हें बर्खास्त किया गया. उस वक्त बिहार में मंत्रियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सम्राट को बागवानी मंत्री बनाया गया था. भगवान जाने इस मंत्रालय का काम क्या था? लेकिन राज्यपाल ने बर्खास्त करने के साथ ही मंत्री रहते हुए जितने भत्ते वेतन लिए थे सब वापस करवा लिए.

सम्राट के पिता शकुनी चौधरी 31 अक्टूबर 1994 को समता पार्टी में शामिल हुए थे. इसी साल जॉर्ज नीतीश के नेतृत्व में समता पार्टी बनी थी. 31 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में बिहार पुनर्निर्माण रैली में शकुनी शामिल हुए थे. तब वो बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे. मंत्री की कुर्सी को छोड़कर समता पार्टी में शामिल हुए थे. लेकिन पांच साल तक समता पार्टी में रहने के बाद बेटे को मंत्री बनवाकर लालू के पाले में लौट गए थे. सम्राट के पास तीन तरह के उम्र के कागजात हैं. जन्म तिथि में कुछ और है तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में कुछ और लेकिन मंत्री पद से हटाने के लिए 1995 में उस हलफनामे का सहारा लिया गया जिसमें उन्होंने हत्या के केस में आरोपी होने से बचने के लिए अपनी उम्र 15 साल (1 मई 1981) बताई थी. इस हिसाब से मंत्री बनने के समय वो सिर्फ 18–19 साल के ही थे.

2009 के लोकसभा चुनाव में शकुनी चौधरी आरजेडी के टिकट पर भागलपुर से लड़ के शाहनवाज हुसैन के हाथों हार गए थे. 2010 में शकुनी विधानसभा भी हार गए. तब से वो साइड चल रहे थे और विरासत सम्राट के हाथ में है. सम्राट को अपने साथ करके नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा के जाने से जो कोइरी नेतृत्व की कमी हुई थी उसे भी पूरा करने की कोशिश की है. ■

feedback@chauthiduniya.com

शिवहर में दिग्गजों की भरमार

वाल्मीकि/शशांक

लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है. तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारी जोर–शोर से शुरू कर दी है. नए समीकरण के साथ ही दल से नेताओं की अदला–बदली का दौर भी चालू है. बाढ़, अपराध व नक्सली घटनाओं के लिए सूबे में चर्चित रहे शिवहर जिले में भी राजनीतिक गतिविधियां अब जोर पकड़ने लगी हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का परचम लहराने को लेकर सभी प्रमुख पार्टियों के संभावित प्रत्याशियों ने प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं की गणेश परिक्रमा भी शुरू कर दी है. नए राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से गठबंधन को लेकर कई खेमों में खुशी तो कहीं गम का साया भी नजर आने लगा है. साथ ही गठबंधन धर्म के पालन को लेकर टिकट से बेदखल होने वाले नेताओं ने अपने लिए नए आशियाने की तलाश भी शुरू कर दी है. हालांकि अब तक किसी ने भी इस दिशा में साफ संकेत नही दिया है परंतु इतना तो तय है कि ठाकुर राम नंदन सिंह, नवाब सिंह, धरीक्षण मिश्र, कीर्ति नारायण सिंह व श्यामनंदन सिंह सरीखे सेनानियों की जमीन पर कई ऐसे नेता भी मौजूद हैं, जो पार्टी का निर्णय नहीं बल्कि खुद के निर्णय से चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने से बाज नहीं आने वाले हैं.

फिलहाल शिवहर संसदीय क्षेत्र पर एक नजर डालने की जरूरत है. इस क्षेत्र का गठन तीन जिलों के क्षेत्रों को समाहित कर बनाया गया है. जिसमें पूर्वी चंपारण के तीन विधान सभा क्षेत्र मधुवन, चिरैया व ढाका, शिवहर का एक शिवहर और सीतामढ़ी का बेलसंड व रीगा विधान सभा क्षेत्र शामिल है. चुनावी त्रिवेणी का संगम बनी शिवहर लोकसभा सीट से इस बार के चुनाव में जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस, लोजपा व आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट की दावेदारी करने वालों की तादाद ठीक–ठाक बताई जाती है. चुनावी चर्चाओं पर गौर करें तो सूबे की सत्ताधारी पार्टी जदयू से पूर्व में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान का नाम सबसे पहले उभर कर आया था. परंतु हाल में चल रही चर्चाओं के अनुसार मुंबई में बड़े कारोबारी शिवहर जिले के निवासी साबिर अली नामक व्यक्ति को जदयू से टिकट मिलने की चर्चा जोरों पर है. इनके अलावा पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर राणा भी अपनी नजर प्रदेश नेतृत्व पर जमाए हुए हैं. वहीं इसी दल से बेलसंड विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति राणा रंधीर सिंह चौहान भी चुनावी वैतरणी में डुबकी लगाना चाहते हैं. लगातार क्षेत्र में लोगों से संपर्क बना कर अपने लिए जमीन तैयार करने में लगे है. जबकि बेलसंड विधान सभा से पूर्व में भाग्य आजमा चुके जदयू उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह भी लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद पहुंचा चुके हैं तो दूसरी ओर सीतामढ़ी जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन कुमार सिंह भी शिवहर सीट से अपनी उम्मीदवारी को लेकर प्रयासरत हैं. जदयू के उक्त पांच पाण्डवों में बाजी कौन मारेगा, फिलहाल कहना गलत होगा, कारण कि प्रदेश नेतृत्व का फैसला ही सर्वमान्य होगा.

फिलहाल भाजपा में टिकट के दावेदारों की तादाद बहुत ही कम है. वर्तमान सांसद रमा देवी को क्षेत्र से बेदखल करने का मन बना चुकी लोजपा की पूर्व विधायक नगीना देवी ने हाल ही में पार्टी से पाला बदल कर भाजपा का दामन थामने का संकेत दिया है. सबसे कांटे की टक्कर की नौबत पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के राजद में नजर आ रही है. इस दल से दो पूर्व सांसद के अलावा एक पूर्व सांसद के पुत्र भी टिकट की दावेदारी में लगे हैं. शिवहर को पहचान दिलाने में अहम योगदान देने वाले पूर्व सांसद रघुनाथ झा ने जहां पार्टी का टिकट पाने को एड़ी–चोटी एक कर रखी है. वहीं पूर्व सांसद मो. अनवारुल हक भी बाजी हाथ से नहीं जाने देने को लेकर जी जान से लगे हैं. उनके अलावा पूर्व सांसद स्व. सीताराम सिंह के पुत्र रंधीर कुमार सिंह भी शिवहर से अपने पिता के राजनीतिक विरासत को संभालने के प्रयास में हैं. जबकि पिछले कुछ सालों से शिवहर की राजनीति में चर्चित रहे युवा राजद नेता अंगेश कुमार सिंह की दावेदारी की भी चर्चा है. गठबंधन राजनीति के बीच इस बार कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी भी दो–दो हाथ करने को तैयार हैं. इनमें बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक व जेल की सलाखों में कैद पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी व पूर्व सांसद लवली आनंद की नजर कांग्रेस के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ने की है. जबकि एआइसीसी के सदस्य मनीष कुमार के अलावा मो. असद व उपाध्यक्ष सीताराम झा भी कांग्रेस के टिकट पर चुनावी समर में उतरने को तैयार बताए जाते हैं. वही अगर बात बनी तो लोजपा खेमा से दिवंगत संजय पांडेय के भाई विजय पांडेय चुनावी अखाड़े में ताल ठोक सकते हैं. दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी चुनावी तैयारी की चर्चा है.

चल रही चर्चा पर यकीन करें तो शिवहर राज दरबार से ताल्लुक रखने वाले अधिवक्ता सतीश नंदन सिंह सीट से प्रबल दावेदार हैं. जबकि शत्रुघ्न साहू व तनवीर आलम के भी टिकट दावेदारी की चर्चा जोरों पर है. बताते चले कि इन राजनीतिक तैयारियों के बीच शिवहर संसदीय क्षेत्र का चुनाव 2014 में कई मायनों में रोचक होने की संभावना है. अगर संभावित प्रत्याशियों की सूची पर नजर डालें तो कुछ हद तक स्थिति साफ नजर आ रही है. कुल मिला कर देखा जाए तो इस चुनाव में शिवहर से दिग्गजों के बीच राजनीतिक घमासान मचने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है. वैसे सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व से अभी संभावित प्रत्याशियों का सूची जारी नहीं की गई है. देखना है कि अबकी बार शिवहर का प्रतिनिधित्व भाजपा के नमो मिशन का अंग बनता है अथवा फिर कोई नया सारथी इस जिले के विकास की कमान थामता है.■

लवली आनंद, मनीष कुमार, मो. अनवारुल हक, मो. असद, मोहन कुमार सिंह, नगीना देवी, रघुनाथ झा, रमा देवी, राणा रंधीर सिंह चौहान, राणा रत्नाकर

feedback@chauthiduniya.com

शिशुओं में डायरिया

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ चन्द्रकान्त सिंह
शिशु रोग विशेषज्ञ, भागलपुर

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Rabinok-DSR
Entenic Coated Rabeprazole & Domeridone Sustained Release Cap.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
DUCORT
Deflazacort Tab/Sus.
ARISKONZYME Syrup.
For Proper Digestion & Normal gastric functions

डायरिया का सबसे आम कारण पेट में संक्रमण है इस बाबत हमें अवगत कराया भागलपुर के डॉ. चंद्रकांत सिंह से, उन्होंने बताया कि यह वायरल या बैक्टीरियल हो सकता है शिशुओं में दूषित भोजन या पानी के साथ संपर्क के माध्यम से और दूषित सतहों को छूने और फिर मुंह में हाथ रखने से होता है। वायरल संक्रमण आमतौर पर दो दिनों के लिए रहता है फ्लू या पेट फ्लू दस्त भी कारण हो सकता है डायरिया के कई कारण हो सकते है जैसे बैक्टीरिया के संक्रमण , अन्य जीवों द्वारा संक्रमण , पाचन तंत्र में परेशानी, कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी, दवाएं, आदी। दस्त के लक्षणों में चिड़चिड़ापन , पेट में सूजन या ऐंठन, उल्टी, मल में रक्त, बलगम, बुखार, वजन में कमी, सूखा मुंह है। बच्चे के इलाज के लिए आपने बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल करें और ओआरएस दे इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो शरीर में पानी की कमी को पुरा करता है,दाल का पानी,चीनी और पानी का गोल दे, बच्चे को एंटीबायोटिक दे या अधिक परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें । ▪ प्रस्तुति: कुमारी अमृता

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : मेरे ससुर जी के आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है और वे ऑपरेशन से बचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में CINERARIA MARITIMA REPL डालना उचित होगा। रिचा स्वामी, राजस्थान

उत्तर : आप CINERARIA MARITIMA REPL दिन में 2 बार दोनों आँखों में 2-2 बूंद डालें। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चालू रखें। आपको स्थायी निदान मिलेगा। क्योंकि यह बाजार में अन्य आईड्रॉप से अधिक प्रभावशाली व परिष्कृत है।

प्रश्न : डॉ साहब मेरी उम्र 23 वर्ष है, गलत आदतों के कारण अत्यधिक कमजोरी है, इच्छा मात्र से ही असंयमित हो जाता हूँ। मधुरेन्द्र, देहरादून

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी आयु 33 वर्ष है एवं मैं विवाहित हूँ पेशाब में धातक्षीणता की शिकायत है। जिससे मैं कफी चिंतित रहता हूँ। कोई अच्छा और हानिरहित उपाए बतायें। आविद, फिरोजाबाद।

उत्तर : आप निराशा मन से निकाल दें और विगोरा 5000 की 6 शीशी का कोर्स करें एवं विगोरा ऑयल से मालिश करें। यह होमियोपैथिक लिक्यूड दवा है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।

प्रश्न : मेरी उम्र 54 साल है, मैं बाबासीर का मरीज हूँ, पिछले कुछ दिनों से इच्छा होते हुए भी समर्थ नहीं हो पाता हूँ। स्थायी उपचार बतायें। सुधीर सिंह, जयपुर

उत्तर : सुधीर जी! बाबासीर की रोकथाम के लिये आप पाइलेलैक्स लिफलेट के निर्देशानुसार इस्तेमाल करें और विगोरा 5x का 6 शीशी का कोर्स करें और सुबह-शाम हाई पावर मुसली आयल से दो महीने तक लगातार मालिश करें। आपको लाभ होगा।

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 68 वर्ष है। शरीर से बिल्कूल स्वस्थ्य हूँ, लेकिन इच्छाशक्ति के रहते हुये भी शरीर साथ नहीं देता। कोई आयुर्वेदिक तात्कालिक समाधान बतायें। जगदीश प्रसाद, झरिया।

उत्तर : आप सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आयुर्वेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।

प्रश्न : पिछले 7-8 वर्षों से मेरे घुटनों और कमर में बहुत दर्द रहता है। दर्द की वजह से चलना-फिरना मुश्किल हो गया है कोई आयुर्वेदिक उपचार बतायें। देवंती सिंह, दिल्ली

उत्तर : आप ऑर्थोविट कैप्सूल सुबह-शाम एक कैप्सूल लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालिश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 24 वर्ष है। अविकसित सीना के कारण हीन-भाव से ग्रसित हूँ। आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : सीना का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं Breastriim Oil का सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से सीना का विकास आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आएंगी।

प्रश्न : बालों के निरन्तर झड़ते रहने के कारण सिर पर गंजापन हो गया है, मैं इस समस्या से बहुत चिन्तित हूँ, उपाय बतायें । उपेन्द्र सिंह, कानपुर

उत्तर : बालों के झड़ने, टुटने से बचने के लिए आप केशवर्धक तेल का नियमित इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से बाल झड़ना एवं टूटना तत्काल समाप्त हो जायेगा।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें 9304291051

किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।

REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

संकट में झारखंड सरकार

मंगलानंद मिश्र

झारखंड की राजनीति एकबार फिर संकट से घिरती नजर आ रही है. झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री चन्द्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे का निष्कासन हेमंत सरकार पर भारी पड़ने वाला है. लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान भी इस मामले पर फिलहाल तो चुप्पी साधे है लेकिन इसकी चुप्पी तूफान आने से पहले की शांति जैसी है.

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन पर राज्य का अब तक का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाया था. इसी आरोप के मद्देनजर दुबे को मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुबे को अपने मंत्रिमंडल से हटाने की अनुशंसा राज्यपाल सैयद अहमद से की थी जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस आलाकमान ने स्पष्ट रूप से संकेत भी दिया था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी के मामले में श्रम मंत्री ददई दुबे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए लेकिन हेमंत सोरेन के 'इगो टच' ने वो सब करा दिया जिसकी उम्मीद कांग्रेसियों को नहीं थी. इधर, ददई दुबे ने भी कहा था कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया है. दुबे को बचाने के लिए पार्टी में लॉबिंग शुरू हो गई थी. सांसद सुबोधकांत सहाय ने कहा कि समन्वय की कमी के कारण ऐसी स्थिति बनी है. पार्टी का प्रयास है कि समन्वय की कमी को दूर किया जाए. उन्होंने कहा कहा था कि राजनीति में अल्टीमेटम काम नहीं आता. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन पर राज्य का अब तक का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाया था. इधर, पलामू के विश्रामपुर से विधायक व पूर्व मंत्री ददई दुबे ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज से सीएम हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. अगर कांग्रेस आलाकमान उन्हें इजाजत दे तो वे एक दिन में हेमंत सोरेन की सरकार गिरा देंगे.

ऐसी सरकार से प्रदेश के लोगों का भला होने वाला नहीं है. आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा यह तो कांग्रेस के आलाकमान ही तय करेगें लेकिन हेमंत सोरेन के पास अब विकल्प भी नहीं रह गया है. प्रदेश में विकास के कुछ कामों को हेमंत सोरेन ने पटरी पर लाया भी था तो अब राजनैतिक अस्थिरता वाली स्थिति आ चुकी है. कांग्रेस के नेताओं के रहमोकरम पर चल रही सरकार में हेमंत सोरेन सबकुछ कायदे से ही लेकर चल रहे थे लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री के बयान के बाद आए उबाल में प्रदेश को एक बार फिर अस्थिरता की ओर ले जाने का कुचक्र का दौर शुरू हो गया है. लोकसभा चुनाव तक सरकार बनी रहेगी या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान ही सरकार से कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेगी यह बताना फिलहाल मुश्किल हो गया है.■

feedback@chauthiduniya.com

शॉर्ट स्टोरी

आम आदमी पार्टी ने निकाली झाडू मार्च

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की एक बैठक पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में हुई. जिसमें सर्वसम्मति से भ्रष्टाचार का सफाया का निर्णय लिया गया. रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तैयारी समिति का गठन के बाद कार्यकर्ताओं ने शहर में झाडू मार्च निकाली. प्रमुख स्थानों से भ्रमण के बाद मार्च स्थानीय कर्पूरी चौक पहुंची. मौके पर सर्व सम्मति से आगामी 19 मार्च को पुपरी में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का निर्णय लिया गया. कार्यक्रम में तैयारी समिति के संयोजक डॉ गोविंद ठाकुर, प्रो आनंद किशोर, मंसूर अहमद, जितेंद्र कुमार, व निर्भय कुमार समेत अन्य थे. ■ ***– गोविंद कुमार***

औचक निरीक्षण

चतरा जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा के द्वारा बालक उच्च विद्यालय चतरा का औचक निरीक्षण किया गया. इस दौरान उन्हें घोर अनिमितता भी देखने को मिली. पढ़ाई के दौरान डीईओ को शिक्षक मोबाइल पर बात करते दिखे. उन्होंने प्रधानाध्यापक सोमनाथ राम को फटकार लगाई और लापरवाह शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश भी दिया. उन्होंने आदेश दिया कि पचास मिनट की एक घंटी में शिक्षक अपना मोबाइल बंद रखेंगे. साथ ही कहा कि पढ़ाई के वक्त जो शिक्षक मोबाइल पर बात करते पाये जाए जाएंगे उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा. ■

आजसू का दौरा

चतरा लोकसभा के आजसू प्रत्याशी तिलेश्वर साहु इनदिनों हंटरगंज प्रखंड के सघन दौरा पर हैं. साहु यह दौरा पैदल ही कर रहे हैं. इस दौरे में चतरा जिले के दोनो विधानसभा के प्रभारी अशोक गहलोत व मनोज चंद्रा इनके साथ हैं. साथ ही आजसू के कार्यकर्ता भी जगह–जगह दौरे में शामिल हो रहे हैं. कहा जा रहा है कि उनके दौरे के बाद से वैश्य समाज में विखंडन की संभावना बन रही है, और यह भाजपा के लिये संकट है. साहु के इस दौरे से और इसे मिल रहे समर्थन से कांग्रेस और भाजपा दोनो दलों के प्रमुख सकते में हैं. ■ ***– अमरेंद्र प्रताप सिंह***

एक नज़र

मांग पत्र सौंपा

स्थानीय अनुमंडल कार्यालय परिसर में टीईटी अभ्यर्थी 14 फरवरी से अनिश्चित कालीन धरना पर बैठे थे. पिछले दिनों धरना देने वालों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रो. एमपी सिंह के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी अजय कुमार चौधरी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा. टीइटी/एसटीइटी अभ्यर्थियों ने जिला पदाधिकारी से मिलकर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की खामियों को बताते हुए इसे सरल करने की मांग की. वहीं धरना पर बैठे अभ्यर्थियों के द्वार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक मांग पत्र बिहार के मुख्यमंत्री के नाम से भी उनके सचिवालय व आवास पर फैक्स किया गया. जिसकी एक प्रति जिला पदाधिकारी को भी दी गई. मामले को जिला पदाधिकारी ने भी गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसका जल्द निदान होगा. जिला पदाधिकारी ने बताया कि टीइटी अभ्यर्थियों का मामला शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में फेरबदल करने के साथ–साथ नियमों को सरल करने की मांग की गई है जो विधेयक का मामला बनता है. इस मामले को लेकर पटना सचिवालय को एक पत्र जारी किया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार में नियोजन नियमावली को इस प्रकार से उलझा कर रखा गया है जिससे पूर्ण पारदर्शिता कहीं से भी नजर नहीं आ रही है. धरना पर बैठे लोगों में मूख्य रुप से कुंदन मंडल, सुमित आनन्द, आनन्द कुमार वर्मा, दीपरतन राय, मनोज कुमार मेहता, अर्जुन कुमार, बिजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, विवेकानन्द, नीरज कुमार, गोपाल निराला, राधेश्याम सिंह, नतिन राजा, अनिल कुमार, सहित दर्जनों सदस्य मौजूद थे. ***– पुरुषोत्तम प्रियदर्शी***

संदेश लेकर पहुंचे यात्री

पिछले दिनों सीतामढ़ी में मां जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम में 10 सदस्यीय साइकिल यात्रियों का एक दल पहुंचा. श्वेत वस्त्र धारी इन यात्रियों के कपड़े पर श्री सर्वेश्वरी समूह का नाम अंकित था. समूह के अध्यक्ष बाबा गुरूपद संभव राम जी के निर्देशन में समूह के 10 सदस्यीय स्वयंसेवकों का दल साइकिल यात्रा पर है. यात्रा का मकसद परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी द्वारा स्थापित समूह के उद्देश्य व जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को जन–जन तक पहुंचाना है. साइकिल यात्रियों का नेतृत्व कर रहे तेज बहादुर सिंह के अनुसार दल में चन्द्रसेन, कल्लू जी, डॉ राम बिलास, भगवती शरण मिश्रा, बृजेश, संतोष, गोपाल, राजेंद्र व विकास शामिल हैं. इस यात्रा का उद्देश्य जन कल्याणकारी और मानवता की भावना को प्रसार देना हैं. इन यात्रियों के लिए रून्नीसैदपुर की जदयू विधायक गुड्डी देवी व राजेश चौधरी के प्रतिनिधि के रूप में युवा सामाजिक कार्यकर्ता रूपेश कुमार सिंह ने रात्रि विश्राम व भोजन की व्यवस्था की. मां जानकी की पावन जन्म स्थली को स्वयं सेवकों ने संपूर्ण विश्व में अद्वितीय होना बताया. जानकी मंदिर में दर्शन के बाद यात्रियों ने मंदिर के महंथ कौशल किशोर दास से मिथिला के संबंध में वृहद जानकारी ली. इसके बाद जनकपुर धाम के लिए प्रस्थान किया. इस दौरान सीता आराधना मंडल में दिनेशचंद्र द्विवेदी व श्रवण कुमार के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे. ***– वाल्मीकि कुमार***

जमे हैं कर्मचारी

चतरा जिले के विभिन्न विभागों में पांच–सात सालों से दर्जनों कर्मचारी जमे हुए हैं. अबतक चतरा जिले में चार उपायुक्तों का तबादला हो चुका है लेकिन ये कर्मचारी एक ही जगह जमे हुए हैं. नियम यह है कि किसी भी विभाग में कोई भी कर्मचारी एक जगह पर तीन साल से अधिक तक नहीं रह सकता है. चतरा जिले के 23 वे डीसी के रूप में अमित कुमार पदास्थापित हुए हैं. इनके आने के बाद से कर्मचारियों के स्थानांतरण की संभावना प्रबल होती दिख रही है. तीन सालों से अधिक समय से जमे कर्मचारियों में से कृष्णा दास (आपूर्ती शाखा, चतरा), राम किशुन दांगी (एनआरईपी), अमृत पाण्डेय (सहायक ईटखोरी), पौलुस हेम्ब्रम (डीआरडीए), नवल किशोर (राजस्व चतरा), अजय बाड़ा (एलआर चतरा), उमेश यादव (स्टोनो, डीसी चतरा), चंद्रकांत (स्टोनो, डीडीसी चतरा), जन्मेजय (चतरा), पिंकी कुमारी (सामान्य शाखा, चतरा), रामदेव ठाकुर (अंचल चतरा), मदन तिवारी (एसडीओ चतरा), संतोष रजक (एसडीओ चतरा), कमलेश राम (सहायक, कुंदा), पंकज कुमार (नाजिर, लावालौंग), गिरजा शंकर पांडेय (सहायक टंडवा), प्रकाश मिंज (सहायक, टंडवा), परमेश्वर राम (सहायक टंडवा), अशोक कुमार सिंह (सहायक, ईटखोरी), इंद्रनाथ (सहायक, इंटखोरी), सुनील ठाकुर (सहायक सिमरिया) के नाम प्रमुख हैं. ***– अमरेंद्र प्रताप सिंह***

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

16 वीं लोकसभा के लिए होने वाला चुनाव कई मायने में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि देश की जनता कांग्रेसी कुशासन से उब चुकी है. परिवर्तन की इस आकांक्षा को व्यवहारिक रूप देते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्त्ता सुशासन संकल्प, भाजपा विकल्प के उद्घोष के साथ सबका साथ, सबका विकास को अमली जामा पहनाने के लिये कमर कस चुके हैं. देश में होने वाले इस सत्ता परिवर्तन में बिहार के अल्पसंख्यकों की अग्रणी भूमिका होगी. उपरोक्त बातें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री मोतीउर्रहमान उर्फ मोती खान ने कही. वे बिहार भाजपा अलपसंख्यक मोर्चा के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे. उन्होंने बताया कि इस एक दिवसीय बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पार्टी द्वारा किये गये कार्यों पर न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लाये जा रहे दृष्टि पत्र पर भी व्यापक चर्चा की गई. उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में अल्पसंख्यकों के एक बड़े वर्ग का रूझान भाजपा के साथ है, जिसका लाभ अररिया संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी को प्राप्त होगा.

डाक कर्मियों का धरना

अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ नई दिल्ली के आहवान पर ग्रामीण डाक कर्मियों ने संघ की मांगों के समर्थन में फारबिसगंज शाखा के मुख्य डाकघर परिसर में धरना दिया . संघ ने अपने मांगों की समर्थन में कहा कि हमारी मुख्य मांगों में जीडीएस कर्मचारियों को सातवें वेतन कमीशन में शामिल करने, 50 प्रतिशत डीए (टीआरसीए) में मर्ज करने, पोस्टमैन एवं एमपीएस के रिक्त पदों पर जीडीएस लेना सुनिश्चित करने, जीडीएस कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारी घोषित करने, अनुकम्पा के नये नियमों को बंद करने, कैजुअल कर्मचारी को नियमित करना शामिल है. इस धरना में प्रमंडलीय उपाध्यक्ष डाकपाल विदेश्वरी मेहता, मटियारी शाखा डाकपाल कामेश्वर मंडल, गणेश मेहता, सुरेन्द्र पासवान, संजय यादव, वसमतिया शाखा डाकपाल राजीव रंजन, नरेश यादव सहित अन्य ग्रामीण डाक कर्मी उपस्थित थे.■ ***– संतोष झा***

अगर किसी तरह से राजद ,कांग्रेस से दोस्ती कर भी लेती है तो सिद्दीकी को मनाना मुश्किल ही नही नामुमकिन होगा. राजद भी अपने इस कद्दावर नेता को नाराज करना उचित नहीं समझेगी. जबकि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. शकील अहमद भी इसी सीट से मैदान मारना चाहते हैं. पार्टी के अन्दर उनके कद का नेता फिलहाल नजर नही आ रहा है.

मधुबनी में होगी त्रिकोणीय जंग

कपिल कुमार

तमाम सर्वे बता रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा की बढ़त रहेगी. सर्वे के अनुसार भाजपा को बिहार में बीस से भी अधिक सीटें आने जा रही है. लेकिन मधुबनी में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार दिख रहे हैं. मुकाबला भाजपा कांग्रेस और राजद के बीच होगा.

इसके पीछे वजह यह है कि फिलहाल वाम एकता बनती नहीं दिख रही है. दूसरी ओर तीसरे मोर्चे की बात भी अभी तक अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाई है. अगर यह मोर्चा अस्तित्व में भी आता है तो सीट को लेकर भाकपा, जदयू व अन्य दलों के बीच समझौता होना आसान नहीं होगा. भाकपा यहां से अब तक छह बार संसद का रास्ता तय कर चुकी है. यही वजह है कि भाकपा मधुबनी संसदीय क्षेत्र को अपने लिए मुफीद मानकर चल रही है. लेकिन पिछले तीन लोकसभा चुनाव में पार्टी को कुल मतदान के महज दस प्रतिशत वोट से ही संतोष करना पड़ रहा है. बर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार डॉ. हेमचंद्र झा को चौथे स्थान पर ही रुक जाना पड़ा था. इस बार के चुनाव में जहां डॉ. झा के अलावा, हरलाखी के पूर्व विधायक और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्य रामनरेश पाण्डेय भी इस सीट के संभावित उम्मीदवारों में प्रबल दावेदारों में गिने जा रहे हैं. ये अन्दरूनी टकराव पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है. जबकि खालिद अनवर इसी सीट से संसद पहुंचने का अरमान लेकर जदयु का दामन थाम कर अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण कर अपनी जीत पक्की मान रहे हैं. अगर ऐसे में तीसरे मोर्चे की बात नहीं बनी और दलों ने अपने बूते ही चुनाव लड़ने का मन बनाया तो भी वे कुछ खास कर पाएंगे ऐसी संभावना कम ही नजर आ रही है. जानकार बताते हैं कि सत्तारूढ़ दल का यहां कोई खास जनाधार नहीं है. वहीं भाकपा ने जनसरोकार के मामले से दूर रहकर खुद को कमजोर बना लिया है. जहां तक राजद–कांग्रेस के बीच दोस्ती की बात है तो यह दोस्ती भी परवान चढती दिख नहीं रही है. जिस बात को लेकर राजद और लोजपा के बीच दूरी आई है वही शर्त राजद ने कांग्रेस के सामने भी रखकर यह संकेत दे दिया है कि दोनों दलों के बीच यहां दोस्ताना मुकाबला ही होगा. 2009 के चुनाव में भी यही हुआ था. राजद–कांग्रेस ने अलग–अलग चुनाव लड़ा और भाजपा को इस अवसर का लाभ मिल गया, और हुकुमदेव नारायण यादव यहां के सांसद चुने गए. अगर यह मान भी लिया जाए कि राजद कांग्रेस में दोस्ती हो गई तो यहां से उम्मीदवार का चयन करना आसाान नहीं होगा. यहां से राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी 2009 में दूसरे स्थान पर रहे थे. वे किसी भी हाल में पुन: यहीं से चुनावी मैदान उतरने पर अडिग हैं. अगर किसी तरह से राजद ,कांग्रेस से दोस्ती कर भी लेती है तो सिद्दीकी को मनाना मुश्किल ही नही नामुमकिन होगा. राजद भी अपने इस कद्दावर नेता को नाराज करना उचित नहीं समझेगी. जबकि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. शकील अहमद भी इसी सीट से मैदान मारना चाहते हैं. पार्टी के अन्दर उनके कद का नेता फिलहाल नजर नही आ रहा है. 2004 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हुकुमदेव नारायण यादव को उन्होंने 87 हजार से अधिक मत से पराजित किया था. इससे पूर्व 1998 में उनको संसद जाने का अवसर जनता ने दिया था लेकिन जब 2009 के संसदीय चुनाव में राजद ने अपने अलग उम्मीदवार के रूप में सिद्दीकी को मैदान में उतार दिया तो डॉ. अहमद तीसरे स्थान पर खिसक गए थे. जबकि भाजपा के हुकुमदेव नारायण यादव और वर्तमान सांसद को पुन: मैदान में उतरना तय माना जा रहा है. 1953 के बाद से अबतक वे इस सीट से तीन बार संसद का सफर तय कर चुके हैं. पहली बार जब इस सीट पर भगवा लहराया था तब 1999 में वे ही जीते थे. इस से पूर्व 1977 के चुनाव में जब जनता पार्टी के नाम से गोलबंदी हुई थी जिसमें आज की भाजपा, भारतीय जनसंघ के रूप में इस गठजोड़ में शामिल थी तब भी यादव ने गठबंधन के लिए जीत दर्ज की थी. पिछले चुनाव में जनता से पार्टी के नीतियों के आधार पर वोट मांगा था और जीत भी गए. लेकिन क्षेत्र की समस्या जस की तस ही रही. लौहट, सकरी, रैयाम की चीनी मिलें चालू नहीं हो सकीं. किसानों को सिंचाई के लिए पश्चिमी कोशी नहर निमार्ण कार्य पूरा नहीं हो सका. जिस मिथिला पेंटिंग की वजह से क्षेत्र की ख्याति देश–विदेश में रही उसके लिए भी वर्तमान सांसद ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और न ही मधुबनी, कपसिया, रहिका सहित अन्य खादी ग्रामोद्योग के बदहाल स्थिति में कोई बदलाव आया. साथ ही विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभागाछी को पर्यटन के मानचित्र पर कोई जगह नहीं मिली. इतना ही नही संसद के अन्दर एक भी चर्चित और असरदार सवाल उन्होंने नहीं उठाया. हालांकि वे क्षेत्र में भरपूर समय दे रहे हैं और इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता से सारे भेदभाव भूलकर भाजपा को जिताने के लिए आग्रह कर रहें हैं. लेकिन क्षेत्र में जनता से उन्हें कई बार खरीखोटी भी सुनने को मिल रही है. सूत्रों के अनुसार जिलाध्यक्ष भी इनसे नाराज चल रहें हैं इनके द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारणी में भी यादव का विरोध किया जा चुका है. साथ ही पार्टी के अन्दर एक गुट चाहता है कि इसबार यहां से किसी नए चेहरे को उतारा जाए. माना जा रहा हैं इस बात पर जिलाध्यक्ष का समर्थन प्राप्त है. प्रफुलचंद्र झा जैसे कई नेता उम्मीदवारी के लिए लगातार प्रयास में लगे हुए हैं. निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में यादव के लिए परेशानी बढ़ सकती है.■

feedback@chauthiduniya.com

भाकपा ने जनसरोकार के मामले से दूर रहकर खुद को कमजोर बना लिया है. जहां तक राजद–कांग्रेस के बीच दोस्ती की बात है तो यह दोस्ती भी परवान चढती दिख नहीं रही है. जिस बात को लेकर राजद और लोजपा के बीच दूरी आई है वही शर्त राजद ने कांग्रेस के सामने भी रखकर यह संकेत दे दिया है कि दोनों दलों के बीच यहां दोस्ताना मुकाबला ही होगा. 2009 के चुनाव में भी यही हुआ था. राजद–कांग्रेस ने अलग–अलग चुनाव लड़ा और भाजपा को इस अवसर का लाभ मिल गया, और हुकुमदेव नारायण यादव यहां के सांसद चुने गए.

अब्दुलबारी सिद्दीकी

शकील अहमद

हेम चंद्र झा

हुकमदेव नारायण यादव

पिछले चुनाव में जनता से पार्टी के नीतियों के आधार पर वोट मांगा था और जीत भी गए. लेकिन क्षेत्र की समस्या जस की तस ही रही. लौहट, सकरी, रैयाम की चीनी मिलें चालू नहीं हो सकीं. किसानों को सिंचाई के लिए पश्चिमी कोशी नहर निमार्ण कार्य पूरा नहीं हो सका. जिस मिथिला पेंटिंग की वजह से क्षेत्र की ख्याति देश–विदेश में रही उसके लिए भी वर्तमान सांसद ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और न ही मधुबनी, कपसिया, रहिका सहित अन्य खादी ग्रामोद्योग के बदहाल स्थिति में कोई बदलाव आया.

बाहरी का विरोध करेगा बेगूसराय

सुरेश चौहान/संदीप कुमार

बेगूसराय लोकसभा सीट ने इनदिनों भाजपा के लिए परेशानी खड़ी दी है. लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए भाजपा में घमासान मचा हुआ है. स्थानीय नेताओं की दावेदारी से भी पार्टी आलाकमान को पेरशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिला भाजपा के कार्यकर्ता बाहरी व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाए जाने के खिलाफ मुहिम तेज कर चुके हैं. जिले के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी आलाकमान स्थानीय कार्यकर्ता में से ही किसी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाए. फिलवक्त स्थिति यह है कि यदि स्थानीय कार्यकर्ताओं के मान–सम्मान की रक्षा नहीं होगी तो भावी प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ेंगी. एक और जहां बुजुर्ग नेताओं की दावेद–री से भाजपा नेतृत्व पेरशान है वहीं पार्टी के विधान पार्षद रजनीश कुमार सिंह ने लोकसभा चुनाव 2014 के लिए बेगूसराय संसदीय सीट से प्रत्याशी बनने की अपनी दावेदारी पेश कर बुजुर्ग नेताओं की नींद हराम कर दी है.

रजनीश कुमार सिंह की दावेदारी की घोषणा ने नवादा सांसद डॉ. भोला सिंह एवं पूर्वमंत्री, विधानपार्षद गिरिराज सिंह की बैचेनी भी बढ़ा दी है. बेगूसराय लोकसभा सीट पर भाजपा के बुजुर्ग नेता व नवादा सांसद डॉ. भोला सिंह ने अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए कई माह पूर्व से ही क्षेत्र में जनसम्पर्क अभियान तेज कर रखा है. वे आमंत्रण मिलने, न मिलने की परवाह किए बिना हर उस सामाजिक कार्यक्रम या आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जरा भी चूक नहीं करते जहां से उन्हें वोट मिलने की संभावना दिखाई पड़ती है. उनका तर्क होता है कि वे पहले बेगूसराय के नागरिक हैं, बाद में नवादा के सांसद. बेगूसराय के नागरिक होने के नाते किसी भी समारोह में जाने का उनका अधिकार बनता है. कहीं–कहीं उपेक्षा या उलाहना का दंश भी झेलना पड़ता है. वे सार्वजनिक तौर पर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि बेगूसराय की धरती से उन्होंने राजनीति शुरू की थी और बेगूसराय से ही अन्तिम बार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं. लेकिन भाजपा के अन्य जमीनी नेताओं का तर्क है कि आखिर हमेशा भोला बाबू ही चुनाव लड़ेंगे तो क्या अन्य नेता आजीवन दरी–माइक का इंतजाम ही करते रहेंगे. जिला भाजपा के अन्दर का एक दमदार तबका नहीं चाहता है कि भोला बाबू बेगूसराय से लोकसभा का प्रत्याशी बनें. इस तबके का तर्क है कि भोला सिंह नवादा से पार्टी के सिटिंग सांसद हैं इसलिए उन्हें नवादा से ही चुनाव लड़ना चाहिए. इसके लिए यह खेमा पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाए हुए है.

चर्चा के अनुसार सूबे के पूर्व मंत्री, विधानपार्षद गिरिराज सिंह की निगाह भी बेगूसराय लोकसभा सीट पर है. उनकी सक्रियता जिले में काफी बढ़ गई है और सभी प्रखंडों का दौरा भी वे कर चुके हैं लेकिन भाजपा का एक खेमा नहीं चाहता है कि कोई बाहरी व्यक्ति बेगूसराय से प्रत्याशी बने. इस खेमे का तर्क है कि आजतक अधिकांश बाहरी व्यक्तियों के सांसद बनने से बेगूसराय का विकास पूर्णत: ठप हो गया है. विकास की एक भी नई योजना जिले को नहीं मिल पाई है. यदि गिरिराज सिंह को प्रत्याशी बनाया जाता है तो बाहरी व्यक्ति होने का दंश उन्हें झेलना पड़ सकता है.

जिले के भाजपा नेता रजनीश कुमार सिंह उपरोक्त दो मुद्दों को केन्द्र बिन्दु में रखकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है. पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि बेगूसराय जिले का विकास जिले के बाहरी व्यक्ति या बुजुर्ग नेता से संभव नहीं है(उनका इशारा भोला बाबू एवं गिरिराज सिंह की ओर था). जिले के विकास का भार युवाओं के मजबूत कंधों पर डालना चाहिए और वे पार्टी में सबसे कम उम्र के दावेदार हैं. प्रदेश महामंत्री एवं विधान पार्षद रहते हुए उन्हें पार्टी संगठन को चलाने एवं मजबूत बनाने का अनुभव है और जिले की जनसमस्याओं की जमीनी हकीकत का भी उन्हें ज्ञान है. इसलिए वे अगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के प्रबल एवं उपयुक्त दावेदार हैं.

इधर भाजपा प्रदेश परिषद के सदस्य एवं वरिष्ठ नेता ललन प्रसाद सिंह का कहना है कि पार्टी आलाकमान को जमीन से जुड़े स्थानीय कार्यकर्ताओं को तजरीह देना चाहिए. स्थानीय कार्यकर्ताओं को नजर अंदाज कर बाहरी पहलवान को चुनाव लड़ने के लिए खोजना उचित नहीं है. उनका कहना है कि पार्टी आलाकमान व्यक्तिवादी तुष्टिकरण की नीति अपना रहा है. एक ही व्यक्ति को खुश रखने के लिए उसे विधायक, सांसद एवं पार्टी पदाधिकारी बनाकर पुरस्कृत कर रहा है जिससे भाजपा के आम कार्यकर्ताओं में असंतोष पनप रहा है. भाजपा में भी वंशवाद प्रारम्भ हो गया है जिसकी आलोचना हो रही है. वर्तमान में एक ओर पार्टी कार्यकर्ताओं के मान–सम्मान में कमी देखी जा रही है. वहीं दूसरी ओर व्यवसायी एवं ठेकेदारों की पूछ बढ़ती जा रही हैं. जाति के ठेकेदार पटना में बैठकर वोट का मूल्यांकन कर रहे हैं लेकिन बूथ पर तो कार्यकर्ता ही जाएगा. पिछले 45 वर्षों से संघ, जनसंघ एवं भाजपा की सेवा करनेवाला कार्यकर्ता आजतक उपेक्षित है. इसलिए कार्यकर्ताओं के मान–सम्मान की रक्षा हर हालत में होनी चाहिए. हकदार को हवलदार बनाने पर ही भाजपा संगठन चमकेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

रजनीश कुमार सिंह की दावेदारी की घोषणा ने नवादा सांसद डॉ. भोला सिंह एवं पूर्वमंत्री, विधानपार्षद गिरिराज सिंह की बैचेनी भी बढ़ा दी है. बेगूसराय लोकसभा सीट पर भाजपा के बुजुर्ग नेता व नवादा सांसद डॉ. भोला सिंह ने अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए कई माह पूर्व से ही क्षेत्र में जनसम्पर्क अभियान तेज कर रखा है.

ललन प्रसाद सिंह

रजनीश कुमार सिंह

भाजपा प्रदेश परिषद के सदस्य एवं वरिष्ठ नेता ललन प्रसाद सिंह का कहना है कि पार्टी आलाकमान को जमीन से जुड़े स्थानीय कार्यकर्ताओं को तजरीह देना चाहिए. स्थानीय कार्यकर्ताओं को नजर अंदाज कर बाहरी पहलवान को चुनाव लड़ने के लिए खोजना उचित नहीं है. उनका कहना है कि पार्टी आलाकमान व्यक्तिवादी तुष्टिकरण की नीति अपना रहा है.

गर्मियों में नवजात शिशुओं का रखें ख्याल

डॉ. एमके मिश्र मोतिहारी के युवा व प्रसिद्ध बाल विशेषज्ञ हैं. बहुत ही कम समय में इन्होंने मोतिहारी के चिकित्सा जगत में अपना स्थान बनाया है. अपने पेशे में ईमानदार हाने के अलावा डॉ. मिश्र एक बेहद ही सुलझे और मिलनसार व्यक्ति हैं. चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए उन्होंने गर्मी के मौसम में बच्चों को होने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में बताया.

डॉ.एम.के.मिश्रा

डॉ. मिश्र ने बताया कि गर्मी का मौसम आने वाला है और ऐसे मौसम में नवजात शिशुओं का ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता होती है. इस मौसम में शिशुओं में सांस की दिक्कत, ब्रॉन्काइटिस, डायरिया और फ्लू जैसी समस्यायें विशेष रूप से देखी जाती हैं. उन्होंने नवजात शिशुओं को इन बीमारियों से दूर रखने के लिए अभिभावकों के लिए कुछ उपाय भी बताए. उन्होंने कहा कि ऐसे मौसम में बच्चों को गर्म रखें. उनकी साफ–सफाई का विशेष ख्याल रखें. इसके अलावा शिशुओं के टीकाकरण में सावधानी बरतें और सभी टीके समय पर लगवाएं.

उन्होंने कहा कि अगर शिशुओं को डायरिया की शिकायत होती है तो उन्हें ओआरएस का घोल लगातार देते रहें जिससे शिशुओं के शरीर में पानी की कमी न हो. तबीयत खराब होने की अवस्था में उन्होंने तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने की बात भी कही जिससे शिशुओं को गंभीर रूप से बीमार पड़ने से बचाया जा सके. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

10 मार्च–16 मार्च 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश– उत्तराखंड

मुस्लिम वोटों की चाहत में नेता बने मदारी

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं की एकमुश्त वोटिंग करने की प्रवृति तमाम राजनीतिक दलों को लुभाती रहती है. मुसलमान वोटर जिस पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, उस दल का पलड़ा अचानक भारी हो जाता है. जब तक अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ रहे इसकी सभी चुनावों में पौबारह रही. समाजवादी पार्टी के उभार के बाद मुस्लिम वोट धीरे–धीरे कांग्रेस के पाले से खिसक कर सपा की तरफ जाने लगा. अयोध्या में कथित बाबरी मस्जिद गिरने के बाद तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटरों की ठेकेदार ही बन बैठी. बसपा आगे बढ़ी तो इसे भी मुस्लिम मतदाता लुभाने लगे. बसपा ने सपा के पाले में खड़े मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिये कभी–कभी, थोड़ी–बहुत सेंधमारी जरूर की, लेकिन मुसलमानों का सपा प्रेम वह कभी खत्म नहीं कर पाई.

पिछले कुछ चुनावों के नतीजों से यह भी पता चलता है कि मुसलमान एकमुश्त वोट तो करते ही हैं, इसके साथ–साथ ऐसा करते समय इनके जेहन में भाजपा का चेहरा भी रहता है. लोकसभा चुनाव 2009 के नतीजे इसका प्रमाण हैं. तब मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए जिस पार्टी का जो मजबूत उम्मीदवार दिखा, उसे एकमुश्त वोट दे दिया. नतीजा यह हुआ कि यूपी में समाजवादी पार्टी को 23, कांग्रेस को 21, बहुजन समाज पार्टी को 20, भाजपा को 10, रालोद को 5 और निर्दलीय को एक सीट मिली.

16वीं लोकसभा के लिये हो रहे प्रचार पर नजर दौड़ाई जाये तो बसपा नेत्री मायावती गुजरात दंगों का दोष मोदी के सिर मढ़कर इनका रास्ता (नरेन्द्र मोदी का) किसी भी दशा में रोकना चाहती हैं. कांग्रेस और सपा भी मोदी की काट के लिये खुलकर मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं. इस बार तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोटरों की नाराजगी से बचने के लिये भारतीय जनता पार्टी भी कमर कस कर मैदान में कूद पड़ी है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का बयान,'अगर इनसे कोई गलती हुई है तो वह मुसलमानों से माफी मांगने को तैयार है,' को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि राजनाथ के बयान पर कुछ मुल्ला–मौलवी नुक्ताचीनी जरूर कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को लगता है कि 21वीं सदी का मुसलमान जागरूक नागरिक किसी के बहकावे में आने की बजाय देशहित में वोटिंग करेगा. 16वीं लोकसभा के सत्ता संघर्ष को लेकर अब तक जो तस्वीर दिख रही है, इसमें भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी का अचानक उभरा मुस्लिम प्रेम, कांग्रेस का सेक्यूलर होने का दावा, समाजवादी पार्टी सरकार के मुस्लिम उत्थान व हित के निर्णय और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में इस समुदाय के लिए किये गये कामों की चर्चा तैर रही हैं.

समाजवादी पार्टी ने तो मुस्लिम वोटरों को सहेजे रखने के लिये पार्टी में बड़ा बदलाव तक करने से नहीं चूक रही है. लगता है कि मौके की नजाकत को भांप कर सपा ने प्रदेश में नया मुस्लिम चेहरा अहमद हसन को आगे का मन बना लिया है. ऐसा आजम खां के स्वभाव के कारण हो रहा है. आजम की विवादित छवि और बात–बात पर रूठ जाना मुलायम को भले ही बुरा न लगता हो, लेकिन इसी के चलते पार्टी के अन्य नेता ही, यहां तक की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी आजम से विश्वास उठता जा रहा है. सपा आलाकमान को चुनावी मौसम में हर समय यह डर सताता रहता है कि कब आजम खां नाराज होकर इस खेल बिगाड़ दें. आजम के साथ समस्या यह है कि वह पार्टी में एक मात्र मुसलमानों के रहनुमा बने रहना चाहते हैं. किसी और मुस्लिम नेता को आगे किया जाता है तो वह भी इन्हें रास नहीं आता है. चाहे जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी को आगे किया जाये या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रसीद मसूद की किसी से नहीं बनती है. इतना ही नहीं, इन्हें अखिलेश कैबिनेट में शामिल मुस्लिम चेहरा अहमद हसन से भी नाराजगी रहती है. कई बार वह अपनी नाराजगी जगजाहिर भी कर चुके हैं. इसीलिये सपा नेतृत्व काफी सोच–विचार कर स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन को आगे बढ़ा रही है.

प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 24 (सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अमरोहा, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बदायूं, बहराइच, गोंडा, कैसरगंज, आजमगढ़, डुमरियागंज, बाराबंकी और लखनऊ) ऐसी है, जहां 20 से 50 फीसद मुस्लिम मतदाता हैं, जिनका वोट निर्णायक भूमिका निभाता है. आबादी के अनुसार मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर सभी दल मंथन में जुटे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव 2009 में प्रदेश की 80 सीटो पर कुल 154 मुस्लिम उम्मीदवार उतरे थे, जिसमें 7 विजयी हुए. इसमें तीन कांग्रेस और चार बसपा के थे. इस बार सपा और बसपा दोनों ने 2009 के मुकाबले ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिये हैं. बाकी दलों ने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं. चुनावी मौसम में तमाम दलों के नेता मुसलमानों को लुभाने के लिये रैलियों में इनकी उपस्थिति अलग से दिखाने को प्रयासरत रहते हैं. भाषणों के जरिए 18 फिसद मुस्लिम मतों को रिझाने की कोशिश होती है. समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार मुसलमानों के सामने पिछले दो साल की उपलब्धियों का ब्योरा पेश कर रही है. सभाओं और रैलियों में सपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि सपा ने विधानसभा चुनाव 2012 में मुसलमानों के उत्थान के लिए जो वायदे किये, उनमें अधिकतर पूरे कर दिये हैं. रैलियों में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के निशाने पर मोदी और कांग्रेस दोनों रहते हैं. वह जहां सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में यूपीए सरकार की उदासीनता का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ते हैं, वहीं मोदी के लिए कहते हैं कि हमने पहले भी प्रदेश में भाजपा का रथ रोका था. इस बार भी मोदी के रथ को यूपी में घुसने नहीं देंगे. दरअसल, मोदी के खिलाफ जहर उगल कर मुलायम मुसलमानों को इनका हितैषी होने का संदेश देना चाहते हैं. अखिलेश यादव भी अपनी सभाओं में यह बताते रहते हैं कि इनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या किया.

बात भाजपा की कि जाये तो वह किसी भी तरह से मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण रोकना चाहती है. इसीलिये इसने हिन्दुत्व का मुद्दा भी पीछे छोड़ रखा है. राजनाथ के बयान से कुछ दिन पूर्व गुजरात में एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी का यह कहना कि हिन्दू और मुसलमान देश के विकास के दो पहिये हैं. इसे मुस्लिमों को रिझाने की ही एक कड़ी माना जा रहा है. मोदी मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि भाजपा शासित प्रदेशों में दंगे कम हुए हैं और सभी वर्ग के लोग महफूज हैं.

कांग्रेस गठबंधन वाली यूपीए सरकार के मुस्लिमों के लिए किये कामों को गिना रही है. मुसलमानों को आरक्षण देने का झुनझुना 2012 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के नेताओं ने बजाया था. इस बार भी यही राग अलापा जा रहा है. कांग्रेस नेता धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़कर और मोदी का हौवा खड़ा कर अपने भ्रष्टाचार और नाकामी पर पर्दा डालने की जुगत में लगे हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती मुस्लिमों को समझाने में लगी हैं कि प्रदेश में सरकारी योजनाओं में मुसलमानों का आरक्षण कोटा तय किया जाना सपा का छलावा मात्र है. बसपा नेता कहते हैं कि सपा मुस्लिम वोटों के लिये पिछड़ों को कैसे नाराज कर सकती है. इधर, राष्ट्रीय लोकदल अपने पेंच कसने में लगी है. मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मुस्लिम मतों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल में खासी बेचैनी है, क्योंकि पश्चिम में इसकी सारी राजनीति जमीन जाट–मुस्लिम के ध्रुवीकरण पर टिकी रहती है. रालोद की ओर से डैमेज कंट्रोल की हर कोशिश की जा रही, लेकिन इसकी राह के रोड़े कम नहीं हो रहे हैं. सभी दलों के नेता मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने के लिये मदारी की तरह डमरू बजा रहे हैं, लेकिन मुसलमान तरक्की पसंद बने इसकी चिंता किसी को नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मनरेगा घोटालेबाजों की उड़ी नींद

सीबीआई ने शुरू की जांच

अजय कुमार

तमाम नेताओं, नौकरशाहों, अधिकारियों, ठेकेदारों और संगठनों के लिये वर्षों से गले की फांस बना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) घोटाला एक बार फिर ठंडे बस्ते से निकल कर सुर्खियां बटोरने लगा है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर हाल में ही सीबीआई ने सात जिलों में मनरेगा घोटाले के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर क्या दर्ज की, तमाम जिला प्रशासन से लेकर पंचम तल (एनेक्सी) तक हिल गया. वैसे तो यह घोटाला मायाराज के समय का था, लेकिन इसकी सीबीआई जांच कराये जाने को लेकर अखिलेश सरकार काफी समय से ना–नुकुर कर रही थी. एक मोटे अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश का मनरेगा घोटाला पांच हजार करोड़ से ऊपर का है. हाल में ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर पधारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भी उत्तर प्रदेश के मनरेगा घोटाले की सीबीआई जांच की बात कही थी, लेकिन छत्तीस का आंकड़ा रखने वाले सपाई–बसाई मनरेगा घोटाला की जांच के मुद्दे पर सुर मिलाते दिखे, लेकिन 31 जनवरी, 2014 को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक पीएल की सुनवाई के दौरान मनरेगा में गोंडा, बलरामपुर, महोबा, सोनभद्र, संतकबीर नगर, मिर्जापुर और कुशीनगर जिले में वर्ष 2007 से 2010 के बीच हुए घोटाले की जांच के आदेश दिये तो अखिलेश सरकार के साथ–साथ नौकरशाहों के भी हाथ–पैर फूल गये. सीबीआई की मानें तो इस दौरान उत्तर प्रदेश को मनरेगा के तहत केन्द्र से करीब 25 हजार करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से 15 से 20 फीसद तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था. सीबीआई ने रिपोर्ट लिखकर विवेचना भी शुरू कर दी है, लेकिन अभी एफआईआर में किसी अधिकारी का सीधे नाम नहीं होने के कारण आरोपी थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं.

गौरतलब हो करीब दो वर्ष पूर्व दिल्ली से आई केंद्रीय जांच टीम ने उत्तर प्रदेश के गोंडा, कुशीनगर, मिर्जापुर, बलरामपुर, बहराइच आदि सात जिलों का निरीक्षण करके मनरेगा योजना में करीब पांच हजार करोड़ के घोटाले का खुलासा किया था. इसके बाद 24 अक्टूबर, 2011 को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को पत्र लिखकर मनरेगा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी, लेकिन बसपा सरकार ने जांच सीबीआई से कराने की बजाए राज्य की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) को सौंप दी थी. बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद सपा की सरकार बनी, तो एक बार फिर केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने अखिलेश सरकार से मनरेगा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने को कहा, लेकिन अखिलेश ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया. कहा जा रहा था कि पंचम तल पर बैठे कुछ नौकरशाह इस मामले में अखिलेश को लगातार गलत जानकारी दे रहे थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया.

मनरेगा जांच की तपिश इतनी तेज थी कि अखिलेश सरकार के काफी करीबी पंचम तल पर बैठने वाले आईएएस पंधारी यादव भी बच नहीं पाये. पंधारी के डीएम रहते सोनभद्र में जो चेकडैम बनाए गये या मरम्मत कराई गई थी, इसमें कुछ समय बाद दरारें पड़ गई थीं. इनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हो गई है. कहा तो यही जाता है कि पंधारी के कारण ही सपा सरकार मनरेगा घोटाले जी जांच सीबीआई से कराने में कतरा रही थी, जिस समय यह घोटाला हुआ था, उस समय पंधारी सोनभद्र के जिलाधिकारी थे और पांच हजार करोड़ के घोटाले में सोनभद्र में ही अकेले 250 करोड़ का घोटाला हुआ था. आज की तारीख में पंचम तल पर बैठने वाले अधिकारियों में पंधारी यादव प्रमुख सचिव अनीता सिंह के बाद सबसे ताकतवर नौकरशाह थे. मनरेगा में धांधली के तमाम मामले हैं. तत्कालीन बसपा विधायक राम प्रसाद जायसवाल के भतीजे प्रदीप की पत्नी व तत्कालीन कुशीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष ने तो नियमों को दरकिनार करके 30 मीटर लंबे पुल का निर्माण करा दिया, जो 6 माह में ही टूट गया था. जायसवाल आजकल जेल में हैं. बलरामपुर में 11 मदों में 181.18602 रुपये की आर्थिक चपत लगी. दो गुना से अधिक दाम में सामान खरीदा गया. गोंडा में वित्तीय नियमों को दरकिनार कर सामग्री खरीदी गई और आरोपियों को बचाने का प्रयास हुआ. महोबा में ऐसी फर्म को भुगतान किया गया, जो लाइसेंसधारी नहीं थी. कैमरा

खरीद में लाखों का घोटाला हुआ. मिर्जापुर में समान की खरीदारी में फर्जी कोटेशन और अभिलेख के बल पर भुगतान हुआ. संतकबीर नगर में गैर–पंजीकृत संस्थाओं के नाम भुगतान हुआ. प्रतियुक्ति पर केन्द्र में तैनात आईएएस अधिकारी अनिल संत का नाम भी कभी यूपी में काफी चर्चा में रहा था. अनिल ने अपने फॉर्म हाउस के लिए मनरेगा के पैसे से 17 करोड़ की लागत से नहर बनाकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया था. तत्कालीन जिलाधिकारी सुल्तानपुर आरके सिंह, मैनपुरी के सच्चिदानंद दुबे, गाजियाबाद के हृदयेश कुमार मनरेगा घोटाले की जांच रिपोर्ट में दोषी तक साबित हो चुके हैं, लेकिन इन अधिकारियों के खिलाफ सरकार व नियुक्ति विभाग ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की थी.

माया सरकार मनरेगा घोटाले में फंसे बड़े अफसरों पर शिकंजा कसने से हमेशा ही बचती रही. यूपी में मनरेगा में धांधली को उजागर करने में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की महत्व–पूर्ण भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है. सोनिया और राहुल गांधी ने करीब तीन वर्ष पूर्व अपने–अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान मनरेगा के पैसों में लंबा घोटाला होने की बात कही थी. इससे पूर्व जिला गोंडा, कांशीराम नगर, बलरामपुर, कानपुर देहात, मथुरा चित्रकूट तथाा महोबा जिलों में मनरेगा घोटाले का खुलासा हो चुका था. जांच में आईएएस अफसरों के अलावा पीसीएस जसवंत सिंह, एनके पाल, वाल, राजबहादुर, बीराम, प्रमोद चंद्र श्रीवास्तव व जयराम वर्मा के ऊपर उंगली उठी थी. राज बहादुर दागी आईएएस और मायावती के वफादार रहे फतेह बहादुर के रिश्तेदार थे. राज बहादुर को बचाने के लिये फतेह (पूर्व प्रमुख सचिव, नियुक्ति) ने घोटाले की जांच को दफन करा दिया. सीबीआई जांच शुरू होने के बाद यह अधिकारी सहमे हुए हैं.

खैर, हाईकोर्ट ने भले ही सात जिलों में मनरेगा घोटाले की जांच का आदेश देकर अन्य जिलों में मनरेगा घोटाले की जांच का फैसला सीबीआई के विवेक पर छोड़ दिया हो, लेकिन राज्य के 17 जिलों में मनरेगा घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू तो कर ही रहा है. कुछ माह पूर्व मिर्जापुर जिले में तैनाती के दौरान दो आईएएस समेत तमाम अफसरों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने शासन को पत्र भेजकर दोषी अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी है. कई जिलों में महिला मजदूरों के बच्चों के बालगृह के नाम पर एक करोड़ के खिलौने, 1.09 करोड़ के टेंट, 50–50 लाख की पानी टंकी, दो करोड़ के फावड़े, तसला और गैंती की फर्जी खरीद दिखाकर मनरेगा का पूरा पैसा ही हजम कर लिया गया. पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ के मनरेगा घोटाले की सीबीआई जांच निष्पक्ष तरीसे से हुई तो बसपा शासनकाल के कई पूर्व मंत्री समेत बड़े कद्दावर अफसरों के नामों का भी खुलासा होगा.

भुक्तभोगी मनरेगा मजदूर अपनी मजदूरी के लिये अधिकारियों के साथ मारपीट तक करने लगे हैं. कुछ समय पूर्व बहराइच में बीडीओ पर मनरेगाकर्मियों का गुस्सा उतर आया. पेमेंट में हो रही देरी से क्षुब्ध मजदूरों ने पहले तो बीडीओं को अर्धनग्न करके बेइज्जत किया. इससे भी इनको शांति नहीं मिली तो बीडीओ के मुंह पर गोबर पोत कर पूरे गांव में घुमाया गया. कई जिलों के मनरेगाकर्मियों ही यही शिकायत है कि इन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला है. इसके खिलाफ लखनऊ में धरना–प्रदर्शन का भी दौर चल चुका है. उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई जिला या ब्लॉक होगा, जहां मनरेगा से जुड़े मजदूर पारिश्रमिक नहीं मिलने का मातम न मना रहे हों.

हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस योजना के क्रियान्वयन की पूरी जानकारी केंद्र को सौंपे जाने के आदेश दिए थे. केंद्र ने इस मामले में न केवल यूपी सरकार की खामियों को गिनाया था, बलिक उसने अखिलेश सरकार से इस मामले में शपथ पत्र देने को भी कहा था. केंद्र ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इस योजना के तहत सरकार के कई प्रोजेक्ट अब तक लंबित पड़े हैं और इनके क्रियान्वयन में देरी हो रही है. केंद्र का आरोप है कि मनरेगा की राशि सही हाथों में नहीं पहुंच रही है. इसलिए सड़कों तथा अन्य विकास कार्य अधूरे पड़े हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

संकटमोचक ही बने सपा का संकट

नरेश भदौरिया

सैफई महोत्सव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि संकट मोचक ही बन गए हैं, सपा का संकट. वे और उनके पिता जी मुलायम सिंह यादव, महासचिव रामगोपाल दर्जनों बार दबंग कार्यकर्ताओं को सुधर जाने को कह चुके हैं, लेकिन दबंगों की जुबानी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रहीं हैं. सपा के विधायक व कार्यकर्ता आए दिन अधिकारियों व कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं. रोजाना खबरें छपती हैं, लेकिन दबंगों के हौसले बुलंद हैं. महासचिव रामगोपाल कहते हैं कि सत्ता के मद में कुछ लोग गरीबों को सता रहे हैं. जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं. यदि गरीबों का ध्यान न रखा गया तो सपा की वापसी संभव नहीं है. वे कहते हैं कि नेताओं के दबाव में अफसर गुंडों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं. कैबिनेट मंत्री शिवपाल कहते हैं कि पार्टी के सत्ता में आने के बाद कई घुसपैठिये पार्टी में आ गए हैं, जो आराजकता फैला रहे हैं. सपा मुखिया कह चुके हैं कि जो नेता गुंडई कराएगा और जो करेगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पर अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है. गुंडई चरम पर है. शहर में जो लड़कियां निर्भय होकर स्कूल-कॉलेज जाती थीं, वे अब घरों से नहीं निकलतीं. [illegible]

feedback@chauthiduniya.com

बुन्देलखंड

दिल्ली सिंहासन किसका होगा

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

बुन्देलखंड के छोटे-छोटे गांव से लेकर शहरों के बीच आम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. दिल्ली सिंहासन किसका होगा, इस बात की चर्चा हो रही है. बदहाली की बुनियाद पर कर्ज से बदहाल बुन्देलखंड इस बार किसको गले लगाता है, किसको ठुकराता है, कहना आसान नहीं है. देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी का कौन सांसद 16वीं लोकसभा में पहुंचता है.

बुन्देलखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. पिछले कई चुनाव में बुंदेलियों को कुछ खास नहीं नसीब हुआ. इसलिए इस चुनाव से भी बुन्देली किसान न कोई उम्मीद लिये है, न इसे भविष्य की चिन्ता परेशान किये है, क्योंकि उसे तो आधारभूत सुविधाएं बिजली, पानी ही मयस्सर नहीं हो पा रही हैं, तो नेताओं से वह क्या उम्मीद पाले. घोर चुप्पी साधे मतदाता हाल ही में सम्पन्न समाजवादी पार्टी की देश बचाओ, देश बनाओ महारैली में आशा से आया, लेकिन निराशा के आंसू लेकर लौट गया. प्रदेश सरकार के मंत्रीमंडल विस्तार में एक बार फिर ठगा गया. 19 में से 5 सीटों पर काबिज समाजवादी पार्टी ने बुन्देलखंड के लोगों को प्रदेश सरकार में एक मंत्री न देकर बुन्देलखंड की अपनी नीति से अवगत करा दिया है. सफल रैली के बाद यहां के समाजवादी पार्टी के विधायकों को प्रदेश मंत्री मंडल में शामिल होने का एक मौका दो वर्ष बाद दिखा था. वह भी निराशा बनके रह गया.

यह क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रहा, लेकिन अब इस गैप को भरने के लिए प्रदेश सरकार संजीदगी दिखा रही है. बुन्देलखंड जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो जायेगा. वहीं दूसरी ओर छोटे राज्यों का ककहरा बजाने वाली बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर बुन्देलखंड राज्य के नाम पर चुनावी जंग में आर-पार की लड़ाई लड़ने को आतुर दिखाई दे रही है. आम आदमी पार्टी का बुन्देलखंड में प्रभाव पैदा करने के लिए ललितपुर में एक पार्टी के सदस्य की हत्या पर धरना देने अरविंद केजरीवाल बुन्देलखंड में आकर पार्टी में जोश भर चुके हैं.

बुन्देलखंडियों के अधूरे ख्वाब के बल पर अपने राजनीतिक ख्वाब पूरे करने के लिए 4 लोकसभा स्थानों में एक पर सिमट गई बहुजन समाज पार्टी इस बार कम से कम 2 सीटें जीतने की जुगत में लगी हुई है. बसपा के वरिष्ठ नेता दद्दू प्रसाद कहते हैं कि बुन्देलखंडी अब ठगे जाने के लिए तैयार नहीं हैं. प्रतिकूल परिस्थितियों में पार्टी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विधानसभा चुनाव में उभरी है. पार्टी लोकसभा चुनाव में भी अपना इतिहास दुहरायेगी. इसी रणनीति के तहत झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चन्द्र मिश्र की समधिन श्रीमती अनुराधा शर्मा को प्रत्याशी बनाया है. भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के उम्मीदवार बनने से इंकार करने के बाद रवि शर्मा पर दांव लगा सकती है. समाजवादी पार्टी की ओर से डॉ चन्द्रपाल सिंह यादव तथा कांग्रेस से केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य उम्मीदवार रहेंगे. आम आदमी पार्टी से मुरारी लाल जैन उम्मीदवार रहेंगे. इस सीट पर मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय होने की बात राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा कही जा रही है.

गौरतलब है कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य को इस लोकसभा क्षेत्र में 2,52,712 मत मिले थे, जबकि दूसरे नम्बर पर रमेश शर्मा बहुजन समाज पार्टी को 2,5042 मत मिले थे. अब बसपा से रमेश शर्मा की पत्नी श्रीमती अनुराधा शर्मा चुनाव लड़ रही हैं. यहां समाजवादी पार्टी के चन्द्रपाल सिंह यादव तीसरे नम्बर पर रहे थे. इन्हें 1,32,096 मत मिले थे. इस प्रकार इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने 34,583 मतों से विजय हासिल की थी. झांसी से लगे उरई संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है. यहां से समाजवादी पार्टी ने वर्तमान सांसद घनश्याम अनुरागी का एक बार टिकट काटने के बाद फिर से प्रत्याशी बनाया है. भाजपा से भानुप्रताप वर्मा तथा बसपा से ब्रजलाल खाबरी मैदान में हैं. कांग्रेस द्वारा पत्ते न खोलने के कारण चुनावी परिदृश्य साफ नहीं दिख रहा है. हाल में ही नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष विजय चौधरी द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी विजय चौधरी को अपना उम्मीदवार बना सकती है. 2009 के चुनाव में घनश्याम अनुरागी समाजवादी पार्टी को 2,83,023 मत मिले. दूसरे नम्बर पर तिलक अहिरवार बीएसपी 271614 मत मिले तथा तीसरे नम्बर पर भानु वर्मा को 131379 मत मिले. घनश्याम अनुरागी ने 11,409 मतों से विजय हासिल की थी, लेकिन मोदी के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है. उरई से लगा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र समाजवादी पार्टी के कब्जे में भले ही नहीं था, लेकिन इस बार सबसे आसान सीट हमीरपुर ही मानी जा रही है. बसपा के वर्तमान सांसद विजय बहादुर सिंह भाजपा से तकदीर अजमाने की जुगत में लगे हैं. भाजपा के वरिष्ठ नेता मानवेन्द्र सिंह, स्वतंत्रदेव सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, उम्मीदवारी की दावेदारी ठोंक रहे हैं. सपा ने अपने राष्ट्रीय महासचिव विशंभर प्रसाद निशाद को प्रत्याशी बनाया है.

कांग्रेस से रंजीत सिंह जूदेव, राजेन्द्र सिंह लोधी के अलावा गंगाचरण राजपूत भी टिकट झटकने की जुगाड़ में है. गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी के विजय बहादुर सिंह को 2009 के लोकसभा चुनाव में 1,99,343 मत मिले थे तो दूसरे नम्बर पर कांग्रेस के सिद्ध गोपाल साहू को 1,73641 मत मिले थे. वहीं समाजवादी पार्टी के अशोक चन्देल को 1,65,938 मत मिले थे. विजय बहादुर सिंह के आम आदमी पार्टी से भी तार जुड़े हैं. बहुजन समाज पार्टी के विजय बहादुर सिंह ने 25, 502 मतों से विजय हासिल की थी. बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र में दस्यु ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होने के कारण इस क्षेत्र में एक बार फिर दस्यु के फरमान क्या गुल खिलाते हैं, इस बात की चर्चा जोरों पर है. समाजवादी पार्टी के निवर्तमान सांसद आर.के. सिंह पटेल ने पार्टी द्वारा टिकट काटे जाने पर पाला बदलते हुए बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर मैदान में खम्म ठोंक दिया है. ददुआ परिवार के रिश्तेदार आर.के. सिंह पटेल और बाल कुमार पटेल के बीच विधानसभा चुनाव में ही टिकट बंटवारे के कारण मनमुटाव हो गया था. मिर्जापुर से सांसद बाल कुमार पटेल को इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हो जाने के बाद पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता के स्थान पर उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अब मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र फिर से सामान्य घोषित होने से बाल कुमार पटेल मिर्जापुर जाते या नहीं, कहना कठिन है. वहीं दूसरी ओर श्यामाचरण गुप्ता ने पार्टी द्वारा अपना टिकट काटे जाने के बाद बगावत कर दी है. अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाने के लिए पूरे संसदीय क्षेत्र में पोस्टर बैनरों के साथ विशाल अभियान चलाया जा रहा है. कांग्रेस से इस संसदीय क्षेत्र के लिए केन्द्रीय राष्ट्रीय महासचिव जनार्दन द्विवेदी को उम्मीदवार बनाये जाने की मांग पूरे बुन्देलखंड के कांग्रेसियों द्वारा की जा रही है. विवेक कुमार सिंह, सम्पतपाल कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं. ब्राह्मण और कुर्मियों के बीच राजनीतिक घमासान के लिए चर्चित बांदा संसदीय क्षेत्र में इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार के लिए रास्ता सबसे आसान दिख रहा है. इस आसानी का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस जनार्दन द्विवेदी पर दांव लगा दें तो आश्चर्य नहीं होगा? गौरतलब है कि 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के आर.के. सिंह पटेल को 240948 मत मिले थे तो दूसरे नम्बर पर बहुजन समाज पार्टी के भैरव प्रसाद मिश्र को 206355 मत मिले थे तथा भाजपा के अमित वाजपेयी को 85,587 मत मिले थे. वह तीसरे नम्बर पर थे. समाजवादी पार्टी के आर.के. सिंह पटेल ने 34,583 मतों से विजय हासिल की थी.

किसी से मिलकर किसी को मजा चखाने लिए कांग्रेस के अन्दर बहुजन समाज पार्टी से जो समझौता का प्लान चल रहा है, उसमें बुन्देलखंड की एकमात्र झांसी सीट कांग्रेस को देने के बाद 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को मौका मिलने की बात हो रही है. यदि कांग्रेस और बसपा कुनबे में समझौता होता है तो बुन्देलखंड में सियासी तस्वीर कुछ और ही होगी. भाजपा ने चित्रकूट में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक करके तथा झांसी में मोदी की सफल रैली के बल पर अपने क्षेत्र को फिर से पाने के लिए दलित, पिछड़े और सवर्ण गठजोड़ को नई दिशा दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि यूपी जीते बिना पूरा देश कहां मिलने वाला है. इसलिए 3-4 अप्रैल 2013 में चित्रकूट में हुई बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में राम का नाम लेकर चुनावी जंग के लिए नई धार दी है तो बहुजन समाज पार्टी ने 15 जनवरी, 2014 की लखनऊ महारैली में बुन्देलखंड की बड़ी भागीदारी कराके दलित और पिछड़ों के साथ मुस्लिम तथा सवर्ण समीकरणों को जोड़ कर सबसे मजबूत स्थिति बुन्देलखंड में भी बरकरार रखने की कोशिश की है. इन सब कोशिशों के बीच कांग्रेस जहां बुन्देलखंड पैकेज के नाम पर तो समाजवादी पार्टी देश बचाओ देश बनाओ महारैली के लिए झांसी में उमड़ी भीड़ के जलवे से गदगद होकर चुनावी जंग को जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक मजबूत संदेश देने में कामयाब रही है. लंगड़े घोड़े की जगह मजबूत घोड़े पर दांव लगा रहे सभी राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों को सबसे तेज घोड़े के रूप में बताने की कवायद में जुटी हुई है. अब सब कुछ जनता के हाथ है कि वह किस घोड़े को लंगड़े या तेज घोड़े या टट्टू के रूप में पहचान देती है. पार्टियों के वादे और इरादों के बीच वोटरों की नई पौध किसे उम्मीदों का वॉयस बनाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा, पर इतना तय है कि वादों का मारा बुन्देलखंड राहुल या मोदी, मुलायम या मायावती के बीच थाली के बैगन की तरह यहां-वहां डोलने को तैयार नहीं दिख रहा है. समाजवादी पार्टी बुन्देलखंड में दो सीटों पर विनर रही तो कांग्रेस और बसपा एक-एक सीट पर विनर और एक-एक सीट पर रनर रही है. आम आदमी पार्टी का बुन्देलखंड में प्रभाव के कारण थोड़ा नुकसान सभी को हो सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लखनऊ

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन सबसे पहले

रवि प्रकाश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शहरी गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना का आगाज कर दिया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप मिशन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के पहले चरण में प्रदेश के सभी 75 जनपद मुख्यालयों व एक लाख से अधिक आबादी वाले 8 शहरों सहित कुल 83 शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित गरीब समुदाय को स्वास्थ्य की मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके तहत 100 नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाएंगे. पहले से ही संचालित 115 शहरी हेल्थ पोस्ट को भी सुदृढ़ किया जाएगा. लखनऊ में पहले से ही संचालित टीबी अस्पताल में 100 बेड का शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी शुरू किया जाना है. इस योजना के माध्यम से शहरी मलिन बस्तियों की जनता एवं घुमन्तू आबादी के लिए विशेष आउटरीच हेल्थ कैम्प आयोजित कर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैय्या कराई जाएंगी. गौरतलब हो कि प्रदेश में जारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार-प्रसार के लिए हाल ही में हौसला अभियान का शुभारम्भ किया गया था, जिसके माध्यम से आम जनता में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता में काफी वृद्धि हुई है. सेहत संदेश वाहिनी का शुभारम्भ इसी दिशा में एक अन्य कदम है. इस परियोजना में प्रत्येक ब्लॉक के अधिक मातृ एवं शिशु मृत्यु दर वाले तथा परिवार नियोजन की दृष्टि से कम जागरूकता वाले अधिक आबादी के 20 गांवों का चयन किया गया है. आज यह परियोजना प्रदेश के 11 मंडलों के 48 जनपदों में शुरू की गई है, जिसे शीघ्र ही प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किया जाएगा. इसके तहत मोबाइल वैन द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म का प्रदर्शन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा. लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में ही बलरामपुर चिकित्सालय में नवीन ओपीडी ब्लॉक, आधुनिक अग्निशमन संयत्र तथा प्रदेश के 29 जनपदों के 66 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी आश्रय स्थलों का शिलान्यास किया. इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने सेहत संदेश वाहिनी का लैग-ऑफ करके शुभारम्भ भी किया. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है. प्रदेश की जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है. 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, 102 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, गम्भीर रोगों का नि:शुल्क इलाज, नि:शुल्क एक्स-रे एवं पैथोलॉजी टेस्ट, नि:शुल्क दवाओं की सुविधा का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा कि इसके बेहतर परिणाम निरन्तर सामने आ रहे हैं. इसके फलस्वरूप राजकीय चिकित्सालयों की चिकित्सा पर प्रदेश की जनता का विश्वास बढ़ा है. श्री यादव ने राजकीय अस्पतालों में नवीन ओपीडी भवनों की स्थापना को वर्तमान समय की जरूरत बताते हुए कहा कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग ने अपनी अलग पहचान बनाई है और जनता का विश्वास जीता है. इन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद चिकित्सा विभाग ने सर्वाधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है. इन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिन कार्यक्रमों का शुभारम्भ हो रहा है, उनका सीधा लाभ जनता को मिलेगा.

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अहमद हसन ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सराहना करते हुए कहा की कि इन्हें गरीबों की समस्याओं और इनके निराकरण में विशेष रूचि है. इनकी सकारात्मक सोच और नेतृत्व के फलस्वरूप ही पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम प्रदेश में हुआ है, वह संभवत: पिछले 66 वर्षों में भी नहीं हुआ है. स्वास्थ्य मंत्री ने देश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किए जाने पर खुशी जाहिर की. स्वास्थ्य विभाग और इसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए इन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बधाई भी दी. ■

चन्दौली

सपा और बसपा के बीच चुनावी रणसंग्राम

चंदौली में सियासी रणसंग्राम उलझता नज़र आ रहा है, क्योंकि सपा और बसपा को छोड़कर अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है. देखना यह होगा कि 19 लाख वोटरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए इस लोकसभा सीट के लिए आनेवाले दिनों में बाकी बची पार्टियां किसे टिकट देती हैं. फिलहाल तो चर्चाओं और कानाफूसी का बाज़ार गर्म है.

सैयद शावेज़ फ़िरोज़

1952 से ही चन्दौली लोकसभा सोशलिस्टों की धरती रही है, लेकिन नए परिसीमन के तहत वाराणसी का एक तिहाई भाग अजगरा और शिवपुर विधानसभा समेटे इस लोकसभा सीट से 19 लाख वोटरों की उम्मीद जुड़ी हुई है. हरिजन और मुसलमान वोटर्स यहां से बराबरी में सेंधमारी का दावा ठोकते हैं. इनके बाद कुर्मी यानी पटेल और मौर्या व कुशवाहा वोटर्स भी कुछ खास अहमियत रखते हैं. नए परीसीमन के तहत राजपूत और ब्राॅ मण वोटों ने भी चुनावी रंगभूमि पर अपनी भागीदारी की ताक़त का एहसास दिलाया है.

वर्तमान में यह सीट समाजवादी पार्टी के पास है, जिसके सांसद एक कुशल राजनीतिज्ञ घराने से ताल्लुक रखते हैं. जिस घराने के स्व गंजीप्रसाद ने हिन्दुस्तान की जंग-ए-आज़ादी में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी और वे लोहिया के बेहद क़रीबी थे. इन्हीं के पुत्र श्री रामकिशुन यादव इस वक्त सांसद हैं और 2014 की पारी खेलने को बेताब हैं. पार्टी ने पुन: अपना सिक्का इन्हीं पर ठोंका है. यह सीट इन्होंने 2009 में बहुजन समाज पार्टी के श्री कैलाश नाथ सिंह यादव से तक़रीबन चार-पांच सौ वोट के अन्तर से छीनी थी.

ताज़े चुनावी माहौल में सपा से रामकिशुन यादव और बसपा से अनिल कुमार मौर्या को पार्टी ने चुनावी रणभूमि में उतार रखा है. दोनों ही अपनी-अपनी हैसियत और ताक़त के मुताबिक़ ताल ठोंक रहे हैं. जहां तक रामकिशुन का सवाल है तो इन्हें नापसन्द करते हुए भी वोटर्स पसन्द कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश की बागडोर इन्हीं के पार्टी के हाथों में है. जिस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो घोषणाएं कर रखी थी, इसमें तक़रीबन सभी एक-एक कर के पूरी किए जाने के आखिरी पायदान पर हैं. शायद ही कोई कोर-कसर बाक़ी हो. सोने पर सुहागा यह कि 17 साल का वनवास टूटा और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिले को अपना मुक़ाम देते हुए जिला मुख्यालय निर्माण का शिलान्यास 23 जनवरी को वाराणसी-चन्दौली में देश बचाओ देश बनाओ रैली के दरम्यान कर डाला. यही नहीं, चन्दौली में मुग़लसराय को एक नई तहसील और राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा करते हुए जहां आम वोटर्स एवं आम जनता का दिल जीता, वहीं गंगा कटान पर भी ध्यान देते हुए क्रियान्वयन शुरू कर दिया, ताकि किसानों और ग़रीबों के मकान व खेत को कटान से मुक्ति मिले, बर्बादी से बचें. इस नज़रिए से इन्होंने आम मतदाताओं के साथ किसानों का भी दिल जीतने में कामयाबी पाई है, जिसका परिणाम अवश्य ही रामकिशुन यादव को मिलेगा. इसमें कोई दो राय नहीं है. अब रहा अन्य राजनीतिक पार्टियों का सवाल. खासकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का तो इन्होंने अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से जो कुछ छनकर आ रहा है, वह ज़रूर बताता है कि बसपा से अनिल मौर्या को स्थाई नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहां तो ऐन वक्त भी टिकट बदलता रहता है. यदि भाजपा ने अपने पुराने साथी पर भरोसा करते हुए आनन्द रत्न मौर्या पर अपना विश्वास पुन: जताया तो अनिल मौर्या का टिकट कट सकता है और पीछे शिद्दत से आसरा लगाए बैठे विनीत सिंह या फिर अन्नापूर्णा सिंह को मौक़ा मिल सकता है, जो दोनों ही क्रमश: मिरज़ापुर, सोनभद्र एवं वाराणसी, चन्दौली और भदोही से एमएलसी हैं. एक खब़र यह भी है कि भाजपा की दो सीटें पूर्वांचल में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से गठबंधित भी हो सकती हैं. यदि वाक़ई में ऐसा हुआ तो प्रमासपा अपने क़रीबी साथी बृजेश सिंह पर दांव खेलेगी और भाजपा इनकी सहयोगी होगी. तब ऐसे में जहां विनीत सिंह की दिलचस्पी लोकसभा में क़िस्मत आज़माने में कम होगी तो वहीं अन्नपूर्णा सिंह उर्फ़ पूनम सिंह, जो बृजेश सिंह की पत्नी हैं, वह भी अपने पांव पीछे खींच लेंगी. अब रहा सवाल कांग्रेस और सकलडीहा विधायक सुशील सिंह और सैयदराजा विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू का तो मनोज सिंह डब्लू को तो पार्टी ने राबर्ट्सगंज से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन यह सीट पूर्व की भांति फिर से सुरक्षित हो गई और इनके मौक़े खत्म हो गए. फिर भी इनका आसरा वाराणसी और मीरज़ापुर पर है कि शायद पार्टी इन्हें मोक़ा दे दे. जैसा कि इनका कहना भी है कि पार्टी का सिपाही हूं, जो आदेश होगा उसका अक्षरश: पालन करूंगा.

बताते चलें कि बीते विधानसभा चुनाव में डब्लू निर्दलीय उम्मीदवार होकर चुनाव लड़े और अपने ही हमबिरादरी वाले कैंडिडेट बृजेश सिंह को शिकस्त दी थी. जबकि इन्हें समाजवादी पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी से हटाते हुए हिरन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसको करारी पटखनी देते हुए उन्होंने निर्दलीय बाज़ी मारी और पार्टी में अपना विश्वास पक्का किया. सकलडीहा विधायक सुशील सिंह का भी यही सफ़रनामा रहा कि धानापुर से पार्टी विधायक होते हुए बसपा ने सकलडीहा से नए परिसीमन के तहत टिकट काट दिया और इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतकर पार्टी को अपनी हनक, कुशल व्यवहार और ताक़त का अन्दाज़ा दिलाया, लेकिन वापस पार्टी में फिर नहीं गए, बल्कि अपना नया मुक़ाम बनाया और पुन: लोकसभा चुनाव 2014 के लिए निर्दलीय क़िस्मत आज़माइश के लिए तैयारी अच्छी कर चुके हैं. वैसे भाजपा से इनके चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट बार-बार आ रही है, जो वक्त के गर्भ में है. रही बात दिल्ली की राजनीति से उपजी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तो यह अपने 'मिशन करप्शन हटाओ देश बचाओ' का जादू यहां नहीं बरक़रार रख सकी है, क्योंकि चन्दौली से 'आप' में दल-बदलू और सिर-फिरे नेताओं की एक ऐसी फौज तैयार हो गई है, जो अपनी नेतागीरी चमकाने के लिए पार्टी की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं नहीं छोड़ेगी. खैर आप प्रत्याशी का नाम अभी फ़ाइनल नहीं है, लेकिन ऐसे दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता अपनी दावेदारी की ताल ठोंक रहे हैं, जिनका जनता के बीच कोई वजूद नहीं है. अब आइए चलते हैं कांग्रेस पर, तो इनके पास वैसे तो कोई ऐसा पावरफुल कैन्डीडेट चन्दौली के लिए नहीं दिख रहा है, लेकिन वीरेन्द्र सिंह का नाम आ रहा है. इसके अलावा क़ौमी एकता दल, गांधीयन पीपुल्स पार्टी सहित दर्जनों ऐसे दल हैं, जो लोकसभा में अपना प्रत्याशी चन्दौली से ज़रूर लड़ाएंगें. इनके लड़ने न लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है. ये सिर्फ वोटकटवा की उपाधि तक ही महदूद रह पाएंगे. जहां तक आम वोटर्स की बात है तो कांग्रेस की छाया इनसे दूर है, क्योंकि अभी आम मतदाता भाजपा, सपा और बसपा के ईद-गिर्द ही तैयारी कर रहा है.

बहरहाल, चन्दौली लोकसभा में जो तस्वीर दिख रही है, वह तो यही कह रही है कि यहां न राहुल फ़ैक्टर का कोई नाम लेवा है और न ही मोदी का जादू चलने वाला है. रणसंग्राम सपा और बसपा के बीच किसी को पटखनी देगा. कुछ ऐसी ही बातें चट्टी-चौराहों पर छन रही हैं. जहां तक ख्‍वाहिशात की बात है तो भाजपा के पंकज सिंह और राणा प्रताप सिंह व कांग्रेस के डॉ राजेश कुमार चौधरी भी आस लगाए बैठे हैं कि इनकी पार्टियां इनपर भरोसा करें तो वह भी चुनावी संग्राम में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

समाजवादी पार्टी की बलिया जनसभा

अखिलेश की खुशी, गम और चिंता

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव को पीएम बनते देखना चाहते हैं. इन्हें लगता है कि यह सपना जल्द हकीकत में बदलेगा, क्योंकि समाजवादी सोच के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है. वह इस बात से खुश हैं कि प्रदेश में साम्प्रदायिक ताकतों के मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं. अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश खुशहाल राज्य बनते देखने की इच्छा पाले सीएम अखिलेश को हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती है कि भारत नौजवान देश है, लेकिन सबसे अधिक चुनौतियों का सामना नौजवानों को करना पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान उत्तर प्रदेश के हैं. सपा के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के मुखिया अखिलेश का यह दर्द बलिया में आयोजित जनसभा के दौरान जनता के सामने आया. कुछ मसलों को लेकर मुख्यमंत्री के दिल में टीस थी तो इन्हें खुशी इस बात की थी कि यूपी को लेकर इन्होंने चुनाव के समय में जनता से जो वायदे किए थे, वह तेजी के साथ पूरे हो रहे हैं. इनकी सरकार की उपलब्धियों में बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता व 12वीं पास छात्र-छात्राओं को लैपटॉप दिना जाना, जिससे युवा पीढ़ी आगे बढ़े. गरीब परिवारों की बालिकाओं को आगे पढ़ाई के लिए कन्या विद्याधन योजना, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा, अल्पसंख्यक परिवार की बालिकाओं के लिए हमारी बेटी-इसका कल योजना, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एम.बी.बी.एस. की 500 सीटों की वृद्धि, किसानों के लिए दुर्घटना बीमा की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये, मुफ्त सिंचाई, समय पर खाद-बीज की उपलब्धता, मंडी से टैक्स माफ कर धान ले जाने की छूट, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा एवं किसानों का 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ किया जाना और कौशल विकास योजनान्तर्गत लाखों आवेदकों का रजिस्ट्रेशन कराया जाना शामिल है.

सभा चुनावी थी, इसलिये अखिलेश कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते थे. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि इनकी सरकार ने गन्ना किसानों को इसका उचित मूल्य दिलाया तथा बन्द पड़ी चीनी मिलों को पुन: संचालित किया. बलिया को खुश करने के लिये इन्होंने रसड़ा चीनी मिल को नयी तकनीक देकर चलवाने और बलिया में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की भी बात की. गंगा नदी के श्रीरामपुर घाट व घाघरा नदी पर पुल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में ट्रामा सेन्टर की स्थापना का भरोसा, चितबड़ा गांव में 132 केवीए तथा रसड़ा सूती मिल की खाली पड़ी जमीन पर 400 केवीए का विद्युत सब स्टेशन स्थापित किया जाना, साथ ही तहसील बैरिया व बेल्थरा रोड में अग्निशमन केंद्र तथा सिकन्दरपुर में मंडी समिति खोले जाने के वायदे जनता को काफी लुभावने, लेकिन हकीकत से दूर नजर आये. अखिलेश यादव ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बलिया में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा. वर्ष 2016 तक गांवों में 16 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 20 से 24 घंटे बिजली दी जाएगी. बलिया में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अच्छी सड़क बनाकर फोरलेन से जोड़ा जाएगा.

लम्बे-चौड़े भाषण के बाद पूरे तामझाम के साथ अखिलेश यादव अपने उड़न खटोले से छूमंतर हो गये. जनता अपने घरों में लौट गई. वहीं सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों ने चैन की सांस ली. यह सिलसिला चुनावों तक ऐसे ही जारी रहेगा. अखिलेश गये हैं तो कोई और आयेगा, लेकिन जनता का भला कल भी सपना था आज भी सपना ही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बस्ती

प्रत्याशियों को लेकर मचा घमासान

दशरथ प्रसाद यादव

बस्ती मंडल की डुमरियागंज, बस्ती एवं सन्तकबीर नगर (आंशिक) से कांग्रेस पीस पार्टी एवं भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर काफी चर्चायें हो रही हैं, जबकि सपा एवं बसपा ने अपने प्रत्याशियों का नाम पहले ही घोषित कर दिया है. अब कांग्रेस के एक प्रभावी एवं चर्चित नेता के इस बयान के बाद कि कांग्रेस से इनका मोहभंग हो रहा है, हलचल और तेज हो गयी है. यह हलचल कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी में तो है ही, इसके कारण डुमरियागंज एवं बस्ती संसदीय क्षेत्रों में भाजपा में भी हलचल है. हलचल इस बात की है कि अब कौन कहां से प्रत्याशी होगा. डुमरियागंज से कांग्रेस के सांसद जगदम्बिका पाल द्वारा प्रेस के समक्ष अपनी उदासीनता यह कहकर जगजागिर की गयी है कि इन्हें पार्टी संगठन एवं सरकार में उचित स्थान व महत्व नहीं दिया गया है. इससे इनकी पत्नी और पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका, बस्ती भी सहमत हैं. चौक-चौराहे एवं सभा-समारोहों में लोग इसके अर्थ ढूढ रहे हैं और सम्भावना व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे गोंडा के सांसद ब्रजभूषण सिंह (सपा) ने भाजपा का दामन थाम लिया है, वैसे ही क्षत्रिय राजनीति में पाल जी भी चौंकाने वाले निर्णय ले सकते हैं. पिछले दिनों जगदम्बिका पाल के भाजपा में जाने की खबरें भी हवा में उड़ीं. वैसे डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र से बासी के राजा, जो वर्तमान विधायक हैं, के क्षत्रिय होने एवं निष्ठावान भाजपाई होने के नाते वहां से इनके प्रत्याशि होने की संभावना से भाजपा में कम मजबूती नहीं दिखती है. सन्तकबीर नगर खलीलाबाद से भी पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान में सक्रिय भाजपा नेता के पुत्र को भाजपा की ओर से प्रत्याशी होना ही है. इससे मात्र बस्ती संसदीय क्षेत्र बचता है. हालांकि बस्ती से भी कई लोग भाजपा से प्रत्याशी के लिए अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं. सपा और बसपा अपने पूर्व प्रत्याशी को बरकरार रखे हुए हैं.

पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पहले खलीलाबाद से संसदीय चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे, अब चर्चा है कि वे मुस्लिम बाहुल्य डुमरियागंज से चुनाव लड़ सकते हैं. इस दरम्यान इनके पार्टी के राष्ट्रीय महामन्त्री एवं पूर्व में एमएलसी रह चुके चौधरी जाति के सशक्त उम्मीदवार साबित होने वाले नेता ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो किस ओर जायेंगे, अभी तक अपना पत्ता नहीं खोले हैं. इसका लाभ बसपा के प्रत्याशी एवं पूर्व मन्त्री एवं कप्तानगंज के वर्तमान विधायक को मिल सकता है. सपा अपने दमदार प्रचार से बस्ती में मजबूत आधार बनाने में सक्रिय है. कांग्रेस की ओर से बातें कम और काम ज्यादा की तरफदारी करते हुये बात और काम दोनों सामान्य ढंग से किया जा रहा हैं. डुमरियांगज से विधानसभा के वर्तमान सभापति सपा से प्रत्याशी हैं और विश्वविद्यालय सहित मेडिकल कॉलेज एवं विभिन्न योजनाओं को लेकर सक्रिय हैं. यहां कांग्रेस पाल जी के हटने के बाद किसे उतारेगी या खुद पाल जी ही उतरेंगे, अभी इस पर संशय बरकरार है. बसपा ने अपने पुराने एमएलए एवं एमपी रह चुके मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगाये हुये है. सन्तकबीर नगर से यादव प्रत्याशी लाकर सपा ने बसपा के सामने बेहतर विकल्प देने का प्रयास किया है. बसपा के सांसद पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं और इन्हें अपने पिताश्री, जो पूर्वांचल के नामी-गिरामी नेता हैं और कई बार कैबिनेट मन्त्री रह चुके हैं, का लाभ मिलना तय है. पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हट जाने की स्थिति में सपा को मुस्लिम समर्थन बढ़ सकता है. भाजपा ब्राह्मण प्रत्याशी की स्थिति में दल एवं हिन्दू कार्ड को लेकर अपनी स्थिति मजबूत करने में पीछे नही है. गोरखपुर एवं अम्बेडकर नगर की दो विधानसभा सीटों को मिलाकर बनने वाले इस संसदीय सीट के भाग्य का निर्णय तय होता है, जिसमें सपा, बसपा एवं भाजपा अपनी साझेदारी बढ़ा रही हैं.

आम आदमी पार्टी के काम को देखते हुए इस क्षेत्र को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा है. सन्तकबीर नगर डुमरियागंज में मीडिया में भी इनकी गतिविधियां कम हैं, जबकि बस्ती में ईमानदार, तेजतर्रार एवं प्रभावी नेतृत्व दे सकने वाले प्रत्याशियों की खोज की स्थिति यह है कि वे कुछ लोगों से मिलकर पूरे संसदीय क्षेत्र का आंकलन कर लेना चाहते हैं. वैसे यहां से व्यापारी के चुनाव लड़ने की सम्भावना है, लेकिन अब इसमें एक नवयुवक ब्राह्मण समाजसेवी का नाम आने से स्थिति बदल भी सकती है. ■